चिंतन

विश्व को ट्रेड वॉर की ओर धकेल रही ट्रंप की सनक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ सनक ने पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका पैदा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगा चुके हैं। इसके जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। अब ट्रंप चीन और कनाडा ही नहीं, भारत पर भी भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। राष्ट्रपति ने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए भारत के साथ जैसे को तैसा टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। यह भी नहीं है कि ट्रंप ऐसा पहली बार कर रहे हैं। उनके पहले कार्यकाल के दौरान भी भारत से आयातित एल्युमिनियम और स्टील पर उच्च टैरिफ लगाए थे, जिसका असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा था। इसके जवाब में भारत ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर भी टैरिफ लगाते हैं तो इसका क्या असर होगा। क्या इसकी मार सिर्फ भारत पर ही पड़ेगी या फिर अमेरिका भी ट्रंप की 'टैरिफ सनक' की आग से झुलसेगा। यह तो साफ है कि भारतीय आयात पर टैरिफ लगाने का असर न केवल दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों पर पड़ेगा बल्कि भारत और अमेरिका दोनों के उद्योगों और आम लोगों पर भी पड़ेगा। अमेरिका और चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाने पर निश्चित तौर पर भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। वह भी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। ऐसे में अमेरिका का भारत के साथ किसी छुटभैया देश की तरह व्यवहार करना सुपरपावर के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 119.71 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें भारत का लगभग 35.31 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। इसका मतलब है कि देश के निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक है। अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाता है तो यह व्यापार संतुलन बिगड़ सकता है। इससे भारतीय उद्योगों के लिए चुनौतियां पैदा होंगी, लेकिन इसका सीधा असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। वहां महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होगा। जब ट्रंप प्रशासन ने पहली बार टैरिफ लगाया था तो अमेरिका में महंगाई की मार शुरू हो गई थी। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करे और उनसे अधिक खरीदे। ट्रंप और मोदी के बीच हाल ही में हुई बातों के बाद अमेरिका ने व्यापारिक संबंध बढ़ाने के महत्व पर जोर तो दिया, लेकिन संसद में ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान करके नई स्पर्धा खड़ी कर दी है। अमेरिका से भारत को कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थों का आयात सबसे ज्यादा किया जाता है। मोती, कीमती पत्थर और नकली आभूषणों का इसके बाद नंबर आता है। इसके अलावा भारत अमेरिका से स्टील, महंगी मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर जैसे पावर प्लांट के उपकरण, विद्युत मशीनरी और उपकरण, विमानन, चिकित्सा और सैन्य उपकरण भी बड़ी मात्रा में खरीदता है। भारत अमेरिका को हीरे और आभूषण, चिकित्सा उपकरण और सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल और परिधान, बैग, जूते आदि निर्यात करता है। अमेरिका भारत के सॉफ्टवेयर और अन्य सर्विसेज के लिए भी बड़ा बाजार है। टैरिफ वार शुरू होने से इन उद्योगों पर सीधा असर पड़ेगा। पहले से ही ट्रंप की टैरिफ वार से दुनियाभर के शेयर बाजार दहशत में हैं। अगर वे लगातार ऐसे ही फैसले लेते हैं तो नई विश्व ट्रेड वार छिड़ने की आशंका है। वे पूरी दुनिया के लिए घातक होंगी।

टैरिफ कटौती
प्रो. अश्वनी महाजन

टेस्ला का भारतीय ईवी उद्योग पर असर

टेस्ला कंपनी के संस्थापक एलन मस्क, जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी प्रशासन में एक अहम भूमिका रखते हैं, का लगातार यह आग्रह रहा है कि टेस्ला कारों के भारत में आयात पर शुल्क घटाया जाए। हाल ही में प्रस्तुत केंद्र सरकार के बजट में 40 हजार डालर से अधिक कीमत वाली कारों पर आयात शुल्क 110 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। आयात शुल्क घटने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत में टेस्ला कारों की बिक्री का मार्ग प्रशस्त हो गया है। टेस्ला कंपनी ने भारत में अपने शोरूम खोलने की कवायद शुरू कर दी है। लंबे समय तक भारत की ऑटोमोबाइल सभी कारों के आयात पर शुल्क घटाने का विरोध करती रही हैं।

लंबे समय से इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली एक अमेरिकी कंपनी टेस्ला, जिसकी इलेक्ट्रिक कारें अमेरिका और अन्य देशों में काफी लोकप्रिय है, भारत में अपनी कारों को बेचने के लिए प्रयास करती रही है। कंपनी का यह कहना है कि पहले उसे अपनी कारें बेचने हेतु मार्ग प्रशस्त किया जाए, और बाद में कंपनी भारत में उत्पादन केंद्र खोलकर यहीं पर विनिर्माण शुरू करने पर विचार करेगी। गौरतलब है कि लंबे समय से भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संरक्षण हेतु सरकार विदेशों से आने वाले वाहनों पर भारी आयात शुल्क लगाती रही है। अभी तक 40 हजार डॉलर की कीमत से ज्यादा की कारों पर 110 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाता है। 40 हजार डालर से कम की कारों पर आयात शुल्क 60 प्रतिशत है।

टेस्ला कंपनी के संस्थापक एलन मस्क, जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी प्रशासन में एक अहम भूमिका रखते हैं, का लगातार यह आग्रह रहा है कि टेस्ला कारों के भारत में आयात पर शुल्क घटाया जाए। हाल ही में प्रस्तुत केंद्र सरकार के बजट में 40 हजार डालर से अधिक कीमत वाली कारों पर आयात शुल्क 110 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। आयात शुल्क घटने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारत में टेस्ला कारों की बिक्री का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके साथ ही टेस्ला कंपनी ने भारत में अपने शोरूम खोलने की कवायद शुरू कर दी है। गौरतलब है कि लंबे समय तक भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियां टेस्ला समेत सभी कारों के आयात पर शुल्क घटाने का विरोध करती रही हैं। उनका विरोध बिना कारण नहीं रहा। जब लगभग तीन साल पहले भारत में टेस्ला कंपनी ने आयात शुल्क घटाने हेतु लॉबिंग शुरू की थी, तब तक देश में इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन अत्यंत शैशव अवस्था में था।

भारतीय कंपनियों का कहना था कि यदि इस स्थिति में टेस्ला कंपनी की विनिर्मित कारों पर आयात शुल्क घटाया जाता है तो उनके द्वारा देश में विकसित इलेक्ट्रिक कारों के विकास में बाधा आएगी। एक वर्ष पहले भी इसी प्रकार का प्रयास टेस्ला कंपनी द्वारा किया गया था, तो ऐसे में भारत सरकार ने यह शर्त लगाई थी कि टेस्ला कंपनी भारत में अपना उत्पादन केंद्र शुरू करेगी। जहां तक कारों के आयात का प्रश्न है, कंपनी को 15 प्रतिशत के अत्यंत कम आयात शुल्क पर अधिकतम आठ हजार कारों के आयात हेतु अनुमति दी गई थी। अभी जहां आयात शुल्क को 110 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत किया गया है, अधिकतम कारों की सीमा को बढ़ाकर 50 हजार करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही देश में यह बहस शुरू हुई है कि टेस्ला कंपनी को कम आयात शुल्क पर अधिक कारें आयात करने की अनुमति से भारत के इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण पर क्या असर पड़ सकता है? समझना होगा कि भारतीय ईवी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जिसका बाजार आकार 20 प्रतिशत वार्षिक से भी अधिक तेजी से, 2032 तक लगभग 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, वर्तमान में कुल वाहन बिक्री में ईवी की मात्र 5 प्रतिशत ही हिस्सेदारी है, लेकिन दो पहिया और तिपहिया वाहनों की श्रेणियों में ईवी को तेजी से अपनाने के कारण यह संख्या 2030 तक 40 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और विनिर्माण के लिए एक दृढ़ और अनुकूल

सरकारी नीतियां रही हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक दो पहिया और तिपहिया वाहनों की बढ़ती मांग ईवी उद्योग के लिए एक प्रेरक शक्ति रही है। साथ ही, बैटरी की लागत में भी भारी कमी आई है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें भी कम हुई हैं। चार पहिया वाहनों के क्षेत्र में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रमुख खिलाड़ी हैं, जबकि दो पहिया वाहनों के क्षेत्र में ओला एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी है। टेस्ला कारों पर टैरिफ में कटौती के बाद भी टेस्ला कारों की ऑन-रोड कीमत 45 लाख रुपये से दो करोड़ रुपये के बीच होगी।

दूसरी ओर, ज्यादातर भारतीय ईवी कारों की कीमत आठ लाख रुपये से 20 लाख रुपए के बीच ही है। इसलिए, यह मानना कि टेस्ला कारों के आने से भारतीय इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन और बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा, सच नहीं है। भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उद्योग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। ईवी पर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर कुछ सीमा तक सब्सिडी भी दी जाती है। सरकार डिजिटल लेनदेन जैसे कुशल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहन दे रही है। ईवी और उनके घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की गई है। सरकार ने 2025 तक ईवी के लिए 2.7 लाख सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है। राज्यों द्वारा भी ईवी नीतियों को लागू किया जा रहा है, जिसमें 50 प्रतिशत राज्यों की अपनी ईवी नीतियां हैं। इन नीतियों में ईवी खरीद के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, रोड टैक्स और कार पंजीकरण शुल्क से छूट और ईवी खरीद के लिए कम ऋण ब्याज दरें शामिल हैं।

दिल्ली और कई अन्य राज्यों में ईवी को रोड टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है। कुल मिलाकर, भारत सरकार और राज्य सरकारें राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और राज्य ईवी नीतियों के माध्यम से ईवी उद्योग को व्यापक बढ़ावा दे रही हैं। टेस्ला समेत आयातित कारों पर टैरिफ कम करने के सरकार के इस फैसले के बाद, ऐसा लग रहा है कि टेस्ला भारतीय ईवी बाजार का एक बड़ा हिस्सा छीन सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि टैरिफ कम करने के बाद भी टेस्ला भारत में अधिकतम 50,000 वाहन ही बेच सकती है। अगर हम देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री देखें तो चीनी दिग्गज पहले ही ईवी बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि, भारत सरकार ने चीन से निवेश पर खासी कड़ाई कर दी है, जिसने भारत में चीनी ईवी खिलाड़ियों की योजनाओं को धूमिल कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद चीनी कंपनियां अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी करके इन चुनौतियों से निपटने के तरीके खोज रही हैं।

हालांकि, सुरक्षा चिंताओं के चलते चीनी कारों के भारत में प्रवेश को लेकर सरकार की ओर से की गई प्रतिबंधों के कारण, इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों के मामले में चीन से अभी भी बड़ी चुनौती आ रही है। भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण तो शुरू कर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों, खासकर बैटरी और मोटरों के लिए इन कंपनियों की बहुत बड़ी निर्भरता बनी हुई है। वर्तमान बजट में, भारत सरकार ने इन कलपुर्जों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर बुनियादी सीमा शुल्क को कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी और मोटरों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने का एक गंभीर प्रयास किया है। यह माना जा सकता है कि आने वाले वर्षों में, आत्मनिर्भर भारत रणनीति के तहत, भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा।

(लेखक पेजोलीकोपी वर्तमेव के पूर्व प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

दो टूक

रोहित कौशिक

अनर्गल बयानों से गिर रही राजनेताओं की साख

इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर कांग्रेस की महिला प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद की टिप्पणी से एक नया हंगामा हो गया है। शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को मोटा खिलाड़ी बताया और उन्हें वजन कम करने की सलाह दी थी। हालांकि कांग्रेस ने शमा मोहम्मद के बयान से किनारा कर लिया है लेकिन इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस बैठे-बिठाए ही सवालों के घेरे में आ गई है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस के राजनेता या प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर हमलावर होने के मौके दे देते हैं। कांग्रेस के कुछ राजनेता यह समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्हें किस तरह का व्यवहार करना है। कांग्रेस के नेता यह गंभीरता कब समझेंगे कि उनके वक्तव्य का समाज पर असर पड़ता है। सार्वजनिक रूप से या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए जिससे कांग्रेस की राजनीति पर गलत असर पड़े। पहले तो कांग्रेस के नेता बिना सोचे-समझे बयान दे देते हैं और फिर अपने बयानों पर सफाई देते फिरते हैं। ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में आ जाती है। केन्द्र और ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस सत्ता से दूर है। क्या ऐसे बयानों से कांग्रेस को कोई लाभ होने की उम्मीद है। निश्चित रूप से ऐसे बयान कांग्रेस की परेशानी ही बढ़ाएंगे। कांग्रेस को यह सोचना होगा कि वह कैसे अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा सकती है। जनता कांग्रेस पर तभी विश्वास कर पाएगी, जब कांग्रेस अपने व्यवहार में भी गंभीरता दिखाएगी। शमा मोहम्मद ने एक्स पर लिखा था कि रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं। उन्हें वजन कम करने की जरूरत है। साथ ही वह भारतीय टीम के अब तक के सबसे निराशाजनक कप्तान हैं। वह एक औसत कप्तान होने के साथ-साथ औसत खिलाड़ी भी हैं, जिन्हें भारत का कप्तान होने का सौभाग्य मिला है। शमा मोहम्मद मूल रूप से केरल की रहने वाली डॉक्टिस्ट हैं। उन्हें 2018 में पहली बार कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। 2019 में भी अपने एक बयान के कारण शमा मोहम्मद चर्चा में आई थीं। उस समय उन्होंने कांग्रेस के टिकट वितरण पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, ऐसे समय में कांग्रेस को केरल में ज्यादा महिलाओं को टिकट देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने शमा मोहम्मद की टिप्पणी पर कांग्रेस को घेरा। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जो लोग राहुल गांधी की कप्तानी में 90 चुनाव हार चुके हैं, वे रोहित शर्मा की कप्तानी को अप्रभावी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली में 6 बार शून्य पर आउट होना और 90 बार चुनाव हारना प्रभावशाली है लेकिन टी 20 विश्वकप जीतना प्रभावशाली नहीं है। वैसे कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। हालांकि कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जो शमा मोहम्मद ने कहा है कि वह पार्टी का स्टैंड नहीं है। शमा को एक्स से संबंधित पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। कांग्रेस भारतीय खिलाड़ियों के योगदान को सर्वोच्च सम्मान देती है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद खूब ट्रोल हो रही हैं। एक्स पर रोहित शर्मा के फैन्स शमा से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस टिप्पणी को अनुचित बताया है। राहुल गांधी भी शमा की टिप्पणी से नाराज बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता कब तक ऐसी हरकतें करते रहेंगे जो कांग्रेस के लिए अनावश्यक समस्याएं पैदा करें। शायद ऐसे नेताओं को ज्यादा बोलने की बीमारी हो रही है। अतिरेक में कुछ भी कह देना ऐसे नेताओं की आदत में शुमार हो गया है। भाजपा के कई नेता भी अपनी टिप्पणियों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। अतिरेक में बयान देने वाले और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नेता चाहे कांग्रेस में हों या फिर भारतीय जनता पार्टी में हों, अपना ओछापन दिखा ही देते हैं। जनप्रतिनिधियों को तो बहुत सोच-समझ कर बयान देने चाहिए लेकिन जनप्रतिनिधि घमंड में होते चूर हैं कि कुछ भी बयान दे देते हैं। ऐसे बयान वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। बयान बहादुर बनने वाले राजनेताओं को यह सोचना चाहिए कि ऐसे बयानों से राजनीति की गरिमा तो गिरती ही है, राजनेताओं की साख भी दांव पर लग जाती है। राजनीति में राजनेताओं की साख बचे रहना बहुत जरूरी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस दौर में राजनेताओं के क्रियाकलापों की वजह से उनकी साख लगातार गिरती जा रही है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सफलता पाने क्यों मन पर अंकुश लगाना ज़रूरी है?

संकलित
दर्शन

मन अधिक चंचल है, क्योंकि वह माया में रमा हुआ है। उसे जीवन सफलता के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए बड़े अंकुश की आवश्यकता होती है। परमात्मा के भय से बड़ा कोई नियंत्रक नहीं है। वह दृष्टिगोचर नहीं है। फिर भी सर्वव्यापी है। उसके कोई अधिकारी नहीं हैं। फिर भी उसका राज्य अनंत एवं व्यवस्था अति सुचारु है। उसने कोई संविधान नहीं बनाया। फिर भी वह गुण-दोष परखकर फल देता जा रहा है। परमात्मा अंतर्यामी है। कुछ भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं है। उसका न्याय ठोकर खाता है। सांसारिक विधानों से बचा जा सकता है, किंतु परमात्मा की परम शक्ति से नहीं। परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना ही दंड से बचने का एकमेव उपाय है। परमात्मा निराकार है, किंतु उसका कौतुक जीवन को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है। परमात्मा का सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य का तन है, जो पांच तत्वों जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश के संयोग से बना है। ये पांचों तत्व परस्पर विपरीत प्रकृति के हैं। वे एक साथ नहीं रह सकते। परमात्मा की ही महिमा है कि एक साथ जीव के तन में बस रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार कोई और नहीं हो सकता। परमात्मा ने अगण्य जीव रचे हैं और नित्य रचता जा रहा है। वह जीवों को रचता ही नहीं, उनका प्रतिपालन भी करता है। उसकी कृपा एवं उसका दंड पल-पल संसार में प्रकट होते हैं। वह राजा से रंक, रंक से राजा, ज्ञानी से अज्ञानी एवं अज्ञानी से ज्ञानी बना रहा है। उसकी लीला वही जानता है।

व्यक्ति के विचार अच्छे नहीं, तो नीयत साफ नहीं

संकलित
प्रेरणा

महाभारत में द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर दुर्योधन और शकुनि से सब कुछ हार गए थे। उस समय ये तय हुआ था कि जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लेंगे, तब उन्हें उनका हारा हुआ राज्य लौटा दिया जाएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया था। शर्त के मुताबिक, दुर्योधन को पांडवों का राज्य लौटाना था। इसके लिए श्रीकृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों ने वनवास पूरा कर लिया है, अब उन्हें उनका राज्य लौटा दो। श्रीकृष्ण की बात सुनने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को राज्य लौटाने से मना कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि वो पांडवों को एक गांव भी नहीं देगा। दुर्योधन की जिद के आगे धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य भी कुछ बोल नहीं सके। इसके बाद श्रीकृष्ण दरबार से जाने लगे तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, आप बिना भोजन किए न लौटें। श्रीकृष्ण ने कहा कि मैं किसी के यहां खाना खाते समय दो बातें ध्यान रखता हूं। पहली, मुझे बहुत भूख लगी हो। दूसरी, सामने वाला मुझे बहुत प्रेम से खिला रहा हो। अभी ये दोनों ही बातें नहीं हैं, न तो मुझे भूख है और न ही तुम मुझे प्रेम से निमंत्रण दे रहे हो। जैसा तुम्हारा स्वभाव है, इसमें भी कोई षड़यंत्र हो सकता है। इतना कहकर श्रीकृष्ण वहां से चले गए और बाद में भगवान ने विदुर के यहां भोजन किया था।

अट्टुकल पोंगाला उत्सव

तिरुवनंतपुरम में सुरक्षित अट्टुकल पोंगाला उत्सव के दौरान भक्त अट्टुकलेश्वरी मंदिर में चारंगाविलक्कू अनुष्ठान करते हुए।

आज की पाती

मतदान के लिए न आना वाकई चिंताजनक

राजनीति और लोकतंत्र की ताकत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में निहित है। आखिरकार, मतदान एक महत्वपूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और हर मतदाता के लिए इसे पहचानना महत्वपूर्ण है। राष्ट्र हमारा है और हमारा लोकतंत्र भी हमारा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वोट की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस शक्ति से हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवारते हैं। इसलिए 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह चुनाव में भाग ले। मतदान न करने का विकल्प चुनना अनिवार्य रूप से इस लोकतांत्रिक दायित्व से मुंह मोड़ना होगा। हर मतदाता को अपने व्यस्त जीवन के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरह लोग खुद-ब-खुद के लिए पूजा स्थलों पर जाने को समय निकालते हैं, उसी तरह मतदान के लिए भी समय निकालना चाहिए। -साकेत अग्रवाल, मुरसमुंद

ट्रेंड

शीतकालीन पर्यटन

देवभूमि उत्तराखंड से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने वाद प्रयास अत्यंत सराहनीय है। हमेंलि में इसी से जुड़ी ट्रैक और बाइक रैली में शामिल लोगों के जोश और उत्साह ने नई ऊर्जा से भर दिया है।

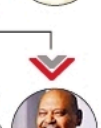

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नेशनल कोऑर्डिनेटर

अब ताजी मौसत ने राष्ट्रीय बेसीपा ठोनो बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में तीनों तीर पर देश के विभिन्न हलकों वाली जिम्मेदारियों को संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ वार्ता रहेंगे।

-मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

फेरोक्रोम का महत्व

क्या आप जानते हैं स्टील को स्टेनलेस क्या बनाता है। फेरोक्रोम जो क्रोमेशियल से बनता है। इसमें अद्भुत जंगरोधी गुण होते हैं जो स्टील को खाना पकाने के बर्तनों से लेकर सर्जरी तक के अनुप्रयोगों में इस्तेमाल करने से सक्षम बनाते हैं।

-अनिल अग्रवाल, उद्योगी

वन्यजीव कल्याण

अनंत अंबानी और राधिका ने जामनगर पूर्ण टीम वन्यजीव रक्षणाय ने उल्लेखनीय बदलाव ला रही है। बचाव, पुनर्वास और संरक्षण के प्रति उनका समर्पण छठा अधिक दिखाऊ और दयालु पारिस्थितिकी तंत्र को आकार दे रहा है।

-विराट कोहली, क्रिकेटर

करंट अफेयर

कश्मीर पर जयशंकर की टिप्पणी 'बेबुनियाद': पाक

पाकिस्तान ने कश्मीर के संबंध में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी को 'बेबुनियाद' बताते हुए बहुस्पतिवार को खारिज कर दिया। साथ ही इस मुद्दे के समाधान की मांग की। जयशंकर ने बुधवार को लंदन में चैथम हाउस थिंक-टैंक के एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर विवाद का समाधान 'कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी के बाद होगा, जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है।'

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकात अली खान ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में जयशंकर की इस टिप्पणी को खारिज कर दिया और भारत से कश्मीर के उस हिस्से को खाली करने को कहा, जिस पर उसने कब्जा कर रखा है। खान ने कहा, 'हम पांच मार्च को लंदन के चैथम हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत के विदेश मंत्री की ओर से की गई टिप्पणी को खारिज करते हैं।' उन्होंने कहा, 'आजाद जम्मू-कश्मीर के बारे में बेबुनियाद दावे करने के बजाय भारत को पिछले 77 वर्षों से अपने कब्जे में रखे गए जम्मू-कश्मीर के एक बड़े क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए।'

ऑफ बीट

अपने दर्द को 10 में से अंक देना क्यों मुश्किल है?

सबसे सामान्य पैमाना 50 साली से है। यह लोगों से उनके दर्द को शून्य (कोई दर्द नहीं) से लेकर दस (आमतौर पर 'सबसे तेज दर्द जिसकी कल्पना की जा सकती है') तक रेट करने के लिए कहता है। यह दर्द के सिर्फ एक पहलू -इसकी तीव्रता- पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि मरीज की हालत क्या है इसे तेजी से समझा जा सके। यह कितना दर्दनाक है? क्या यह बदतर हो रहा है? क्या उपचार से यह ठीक हो रहा है? रेटिंग स्केल समय के साथ दर्द की तीव्रता का पता लगाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर दर्द के अंक आठ से चार हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं - यह भी हो सकता है कि आपका चार अंक किसी अन्य व्यक्ति के चार अंक से अलग हो। शोध से पता चलता है कि क्रोनिक (पुराने) दर्द की गंभीरता की दो अंक (या 30) की कमी आमतौर पर एक ऐसे परिवर्तन को दर्शाती है जो दैनिक जीवन में अंतर लाता है। पेचीदा अनुभव पता करने के लिए बेहद संकुचित माध्यम मेरी बेटी की दुविधा पर विचार करें। कोई व्यक्ति सबसे भयानक दर्द की कल्पना कैसे कर सकता है? क्या हर कोई एक सी ही कल्पना कर सकता है?

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 17

निजी निवेश पर उलझन

हमारी से उथलपुथल मचने के बाद केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ा दिया है। निवेश ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मांग बढ़ाने का काम बखूबी किया मगर यह भी माना गया था कि कभी न कभी निजी क्षेत्र निवेश का जिम्मा अपने हाथ में लेगा और वृद्धि बरकरार रहेगी। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.67 फीसदी था, जो 2024-25 में बढ़कर 3.4 फीसदी तक पहुंच गया। हालांकि महामारी से तो हम बहुत तेजी से उबर गए मगर निजी निवेश में इजाफा सुस्त ही रहा है। ध्यान रहे कि महामारी से पहले भी निजी निवेश धीमा ही था। महामारी के पहले के सालों में निवेश की स्थिति को कुछ हद तक 'बैलेंस शीट की दोहरी समस्या' से भी समझा जा सकता है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद कंपनियों और बैंकों दोनों की बैलेंस शीट बहुत खस्ता हो गई थीं। हालांकि अब यह दिक्कत पूरी तरह दूर हो चुकी है और कंपनियों तथा बैंकों की बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में है। किंतु निजी क्षेत्र अब भी ज्यादा निवेश करना नहीं चाहता।

इस वित्त वर्ष में स्थिर मूल्यों पर देश का सकल स्थिर पूंजी निर्माण जीडीपी के 33.4 फीसदी के बराबर रहने का अनुमान है। लगातार ऊंची वृद्धि हासिल करने के लिए इसे बढ़ाया देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी हफ्ते निजी कंपनियों से कहा कि उन्हें मुक्त दर्शक नहीं बने रहना है। उन्होंने कंपनियों से मौके पहचानने और चुनौतियां स्वीकारने के लिए कहा। निजी निवेश का मुद्दा पिछले महीने इस समाचार पत्र द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम 'मंथन' में भी बार-बार आया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निजी क्षेत्र को बताना चाहिए कि उन्हें निवेश बढ़ाने से क्या बात रोक रही है। सरकार चुनियादी ढांचा सुधारने के लिए भारी खर्च के साथ ही निवेश बढ़ाने के प्रयास भी कर रही है। उदाहरण के लिए 2014 के बाद से अब तक उसने 42,000 से अधिक नियम-कायदे हटा दिए हैं। 3,700 से अधिक कानूनी प्रावधानों को फौजदारी से बाहर कर दिया गया है और आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। विनियमन आयोग पर चर्चा हो रही है। चूंकि वास्तव में निवेश राज्यों के भीतर होता है, इसलिए आयोग को अपने काम के दायरे के हिसाब से राज्यों के साथ मिलकर काम करना होगा। 2000 के दशक की तेज वृद्धि असल में 1990 के दशक के सुधारों के कारण आई थी।

कुछ प्रस्तावित उपायों को कारोबारी सुगमता बढ़ाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा माना जा सकता है, जिनका फायदा आगे चलकर मिलेगा किंतु भारतीय कंपनियों के निवेश नहीं करने की कई वजह हो सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में 75 फीसदी क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है, जो लंबे अरसे के औसत से कुछ ही ज्यादा है। आम तौर पर कंपनियां इसी स्तर से क्षमता बढ़ाने के लिए नया निवेश करने की सोचती हैं। लेकिन उनकी अनिच्छा की दो बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली, अनिश्चितता भरा वैश्विक माहौल, जिसमें डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद इजाफा ही हुआ है। दूसरी, चीन में आवश्यकता से अधिक क्षमता होना, जिसके कारण कंपनियों के लिए निर्यात बढ़ने की संभावना घट जाती है।

2000 के दशक में अधिक निवेश के साथ ऊंची आर्थिक वृद्धि तो हो ही रही थी, निर्यात भी बहुत बढ़ रहा था। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी 2003 में 15 फीसदी थी, जो 2013 में बढ़कर 25 फीसदी से ऊपर चली गई। मगर 2019 में यह घटकर 18.7 फीसदी रह गई। उसके बाद से हिस्सेदारी बढ़ी है मगर अपने सर्वोच्च स्तर से बहुत कम है। निवेश और कुल वृद्धि में कमजोरी को निर्यात की सुस्ती से समझा जा सकता है। सरकार निर्यात पर शुल्क कम कर रही है मगर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

विनय सिन्हा

पश्चिम में जीवन: आधी हकीकत आधा फसाना

चाहे गोल्डन वीजा लेकर जाएं या डंकी रूट के सहारे पहुंचें, विदेश में जीवन की कल्पना और हकीकत में बहुत अंतर है। विस्तार से बता रहे हैं आर जगन्नाथन

अरमान और उनसे जन्मे स्वप्न बहुत विचित्र होते हैं। वे ईंधन की मुश्किल और कई बार तो असंभव या अवांछित काम करने के लिए कहते हैं चाहे लक्ष्य हकीकत से कोसों दूर मरीचिका की तरह ही क्यों न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी-बेड़ी में जकड़कर सेना के जहाज से वापस भेजना शुरू कर दिया है, जिससे कई सपने धूल में मिल गए होंगे। मगर यकीन के साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें अमेरिका ने दूसरी बार निर्वासित किया है। वापस भेजे गए लोगों में से कई ने अवैध तरीके से 'अमरीका' और 'कनेडा' पहुंचने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी होगी और बड़ी रकम उधार ली होगी। उन्हें उधार चुकाने हैं और उसके लिए शायद वे एक बार फिर 'डंकी रूट' से उत्तरी अमेरिका जाने की कोशिश करें - इस उम्मीद में कि इस बार किस्मत साथ देगी।

उधर ट्रंप 50 लाख डॉलर का गोल्ड कार्ड लेने पर अमेरिका की स्थायी नागरिकता देने का वादा भी कर रहे हैं। इसे देखकर अमीरों के अरमान और सपने एक बार फिर परवाज भर सकते हैं। पुर्तगाल, ग्रीस, माल्टा, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कई कैरिबियन देश उन लोगों को गोल्डन वीजा देते आए हैं जो संपन्न देशों (या आसपास के इलाकों) में स्थायी नागरिकता हासिल करने के लिए 2 लाख से 5 लाख यूरो या इससे भी ज्यादा निवेश करने को तैयार हों। उनके बाद लाखों विद्यार्थी भी हैं, जो भारी रकम खर्च कर वहां के औसत विश्वविद्यालयों में दाखिला लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाद में उन्हें उत्तरी अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में स्थायी नागरिकता मिल जाएगी।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैलिफोर्निया या टैक्सस पहुंचने के लिए किसी संदिग्ध एजेंट को 50 लाख या 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं अथवा गोल्डन वीजा हासिल करने के लिए 4-5 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। जो सोचकर इतना खर्च तथा जोखिम उठाया जाता है और वहां जो मिलता है, दोनों में बहुत अंतर है, जो अमीर-गरीब के लिए एक जैसा ही होता है। फर्क केवल इतना है कि अमीर लोग कानूनी रास्ते से वहां दाखिल हो सकते हैं और संपन्न देश की जीवनशैली के जो ख्वाब उन्होंने देखे थे, उनमें तथा हकीकत में मौजूद अंतर को सपना पूरा होने की कीमत मानकर भुला सकते हैं।

किसी भी सरकार को लोगों की हसरतों और सपनों के आड़े नहीं आना चाहिए मगर हकीकत से कोसों दूर हसरतों और सपनों के इस बाजार पर अगर भारत लगाम नहीं कसता है तो वह भविष्य में वहां जाने वालों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। जिस तरह वित्तीय योजनाओं को गलत वादों के साथ बेचना सही नहीं माना जाता उसी तरह पश्चिम की जीवनशैली को स्वर्ग की तरह बताकर बेचने की इस हरकत पर भी लगाम लगनी चाहिए। गरीबों के सपनों का फायदा उठाने वालों पर कार्रवाई करने के अलावा सरकार को मीडिया अभियान भी शुरू करना चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि सपनों और हकीकत में कितना फर्क है। बिचौलियों और एजेंटों को भोले-भाले ग्राहक मिल जाते हैं क्योंकि वे उनके मन में बैठे सपने पूरे करने की बात कहते हैं।

सबसे पहले तो डॉलर और रुपये का भ्रम तोड़ना होगा। 86-87 रुपये का 1 डॉलर देखकर कोई भी मान सकता है कि अमेरिका में कमाया 1 डॉलर भारत में कमाए 86-87 रुपये के बराबर है। मगर यह तभी है, जब आप डॉलर बचाकर भारत भेज रहे हैं। 1 डॉलर देकर आप अमेरिका में उतना सामान नहीं पा सकते, जो भारत में मिल सकता है। वहां रहना, किराया, आना-जाना बहुत महंगा है। इसलिए लोगों को पता होना चाहिए कि भारत और अमेरिका में रोजाना का खर्च कितना बैठता है। इसके बाद आरामदेह जिंदगी का भ्रम तोड़ा जाए। अगर आप 5 लाख डॉलर भारत में निवेश कर देते हैं तो आपको ताउम्र कुछ नहीं करना पड़ेगा और रकम भी जस की तस बनी रहेगी। साथ ही आप यहां घरेलू सहायक, बढ़ई, होम डिलिवरी, उपकरणों की मरम्मत जैसे काम अमेरिका या कनाडा के मुकाबले कौड़ियों के भाव करा सकते हैं। भारत में ढंग की सुरक्षा वाली किसी रिहायशी सोसाइटी में आप पश्चिम के मुकाबले बेहतर जीवन बिता सकते हैं। हां, वहां सरकार का दखल कम रहता है। डिजिटल जमाने में यह दिक्कत भी कम हो रही है मगर बाबुओं से निपटना पड़े तो आप भी सोचेंगे कि काश, कहीं और रहते। पश्चिम में एक बात अच्छी है - वहां भीड़ और शोरगुल नहीं है।

तीसरी समस्या भारतीयों के साथ नस्लभेद है। डॉलर की चाह में हम इसकी अनदेखी करते हैं मगर चाहे किताबी हिंदुफोबिया हो या दफ्तरों में हिंदुओं के प्रति पूर्वग्रह, नस्लभेद तो है। अब तो अमेरिका के शिक्षा जगत ने वहां हिंदुओं को निशाना बनाने का काम भारत में जाति के लिए काम करने वालों को दे दिया है। भारतीयों को हथकड़ी में भेजकर ट्रंप ने दिखा दिया है कि अमेरिका से हमें कितनी इज्जत मिल रही है। परंतु हमारे टिप्पणीकार 'डंकी रूट' से अमेरिका जाने नालों को ऐसे अमानवीय व्यवहार की चेतावनी देने के बजाय इसका इस्तेमाल मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसे रास्तों से अमेरिका जाने वालों की दर्दनाक यात्राओं पर मीडिया में शायद ही कभी चर्चा होती है, इसलिए गैर-कानूनी तरीकों से जाने की कोशिश कर रहे लोग हकीकत से रूबरू ही नहीं हो पाते।

चौथी भ्रांति अक्सर बॉलीवुड फिल्मों (दिल चाहता है) के जरिये किए गए झूठे प्रचार से बनी है। जब से बॉलीवुड ने गरीबी पर फिल्में बनानी बंद की हैं, वह लगातार विदेश में ही शूटिंग कर रहा है और पश्चिमी जीवनशैली के लिए भ्रांति गढ़ रहा है। देशभक्ति का एकाध गाना छोड़ दें तो बॉलीवुड पश्चिम को स्वर्ग ही दिखाता है। हमें पश्चिम में अमीरी ही दिखाई गई है टाइम्स स्क्वैर पर घूमते भिखारी नहीं। तो क्या बॉलीवुड को अब यह भ्रांति तोड़नी नहीं चाहिए?

पांचवां भ्रम हमारी औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़ा है। भारत में हसरतें पश्चिम से इस कदर जुड़ी हैं कि हमारी इमारतों के नाम भी वहीं की तर्ज पर होते हैं। बेंगलूरु में मेरी सेटेड कॉलोनी में सभी इमारतों के नाम मैनहटन की इमारतों के नाम पर हैं। इसलिए आज रिवियरा, पाम बीच, ब्रूकलिन हाइट्स, ब्लूमिंगडेल्स जैसे नाम ही मिलते हैं। पश्चिम की श्रेष्ठ मानने वाली औपनिवेशिक मानसिकता खत्म करने के लिए गंभीर होना पड़ेगा। अगर देश का कुलीन वर्ग यह मानता है कि भारतीय छाप वाला कुछ भी अच्छा नहीं है और हर अच्छी चीज में कुछ पश्चिमी होना चाहिए तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता।

पश्चिम के पीछे भारतीयों की दौड़ की वजह यह भी है कि हमारी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था बेहद घटिया है और इसे फौरन दुरुस्त करना होगा। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित को छोड़ दें तो स्नातक में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता, जो उन्हें नौकरी दिला सके। जीवन सुगम होना चाहिए और हमारी अफसरशाही को भी औपनिवेशिक खुमार से उबरकर लोगों की जरूरतें समझनी चाहिए।

मगर लोगों को यह समझाना सबसे जरूरी है कि विदेश में जिस तरह के जीवन की कल्पना वे करते हैं हकीकत उससे बहुत अलग है और वे भारत में वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। पश्चिमी जीवनशैली के मिथक तोड़ना बहुत जरूरी है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

चालू व बचत खातों में जमा कैसे बढ़ाएं बैंक

एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने पिछले दिनों मुझे वित्तीय उद्योग की बड़ी परेशानी का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि फीस से आय बढ़ाने के चक्कर में अपनी शाखाओं पर जमकर म्युचुअल फंड और बीमा पॉलिसियां बेचकर बैंकों ने बड़ी आफत मोल ले ली है। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक मामला हाथ से निकल चुका था।

ज्यादातर बैंक ग्राहकों से रकम जमा कराने की जद्दोजहद में लगे हैं ताकि वे अधिक से अधिक कर्ज दे सकें। ऐसे में उन्हें पछताया हो रहा है कि अपनी शाखाओं को उन्होंने दूसरे गैर-बैंकिंग वित्तीय उत्पाद बेचने के लक्ष्य क्यों दिए थे। आलम यह है कि फरवरी में नीतिगत दर में चौथाई फीसदी कटौती की गई है मगर बैंक अपनी जमा दरों में कमी नहीं कर सकते। आम तौर पर ऐसा कहां होता है? जमा पर ब्याज जैसी देनदारी जस की तस बनी हुई है या बढ़ रही है मगर कर्ज से होने वाली ब्याज आय घटना तय है क्योंकि ज्यादातर कर्ज की ब्याज दरें नीतिगत दर से जुड़ी रहती हैं।

ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब बैंक उन ग्राहकों को म्युचुअल फंड में निवेश के लिए मना रहे थे, जिनके जमा खाते में भारी रकम थी। लेकिन शेयर बाजार में भारी गिरावट के बाद कई फंड कंपनियां नकदी शेयरों में लगाने के बजाय अपने पास बचाकर रख रही हैं। इस पैसे का वे क्या करती हैं? इसे वे बैंकों में रखती हैं। फिर बैंकों को शिकायत किस बात की है? म्युचुअल फंडों के जरिये जो रकम बैंकों की तिजोरी में लौट रही है वह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) की शक्ल में आ रही है। सीडी पर सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के मुकाबले ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। बैंक ज्यादा से ज्यादा 1 साल के सीडी जारी करते हैं। फरवरी के पहले हफ्ते में 5.19 लाख करोड़ रुपये के सीडी बकाया थे। बैंक अब जमा बढ़ाने की जुगत सीखने सलाहकार फर्मों के पास पहुंच रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि कम खर्च वाली चालू और बचत खाता (कासा) जमा, सावधि जमा और एनआरआई जमा कैसे बढ़ाई जाएं तथा पूंजी हासिल करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ रिश्ते मजबूत कैसे किए जाएं।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता और बचत खाते पर 2.6 फीसदी से 4 फीसदी ब्याज मिलता है। ज्यादातर सरकारी बैंक 1 लाख रुपये तक जमा राशि पर 2.6 से 2.75 फीसदी, 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच रकम पर 2.7 से 2.9 फीसदी तक और उससे अधिक जमा पर 2.7 से 4 फीसदी तक ब्याज देते हैं। आपकी शिकायत हो सकती है कि ये बैंक मिलीभगत कर बहुत कम ब्याज देते हैं। मगर बचत खाते के रखरखाव पर बैंकों को बहुत खर्च करना पड़ता है और ब्याज तो इस खर्च का मामूली हिस्सा है।

इसके बाद भी निजी क्षेत्र के कुछ बैंक बचत खाते पर काफी ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। मसलन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5 लाख से 100 करोड़ रुपये तक जमा पर 7.5 फीसदी ब्याज दे रहा है और आरबीएल बैंक 15 लाख से 3 करोड़ रुपये जमा पर इतना ही ब्याज दे रहा है। येस बैंक भी 10 लाख से 100 करोड़ रुपये तक जमा पर 7 फीसदी ब्याज दे रहा है। कम खर्च में रकम हासिल करने में कासा जमा बैंकों के बहुत काम आती है। इससे बैंक परिसंपत्ति की गुणवत्ता गिराए बगैर ब्याज से ज्यादा कमा लेते हैं। मान लीजिए, किसी बैंक के लिए रकम की कुल लागत 5 फीसदी है तो यह ग्राहक से 9 फीसदी ब्याज वसूलकर 4 फीसदी शुद्ध ब्याज मार्जिन पा सकता है। मगर रकम की लागत 7 फीसदी हुई तो 4 फीसदी शुद्ध ब्याज मार्जिन के लिए उसे 11 फीसदी ब्याज पर कर्ज देना होगा, जिसे अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाला कोई ग्राहक नहीं लेगा। तब बैंक की परिसंपत्ति बिगड़ेगी और ऊंची लागत के कारण ब्याज मार्जिन का भी फायदा नहीं होगा।

पिछले साल भर में कुछ ही बैंक अपना कासा अनुपात बरकरार रख पाए हैं। कुछ की कासा जमा बढ़ी है। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच ऐक्सिस बैंक का कासा अनुपात 42 फीसदी से घटकर 39 फीसदी, बंधन बैंक का 36.1 से घटकर 32 फीसदी, एचडीएफसी बैंक का 37.7 से गिरकर 34 फीसदी और कोटक महिंद्रा बैंक का अनुपात 47.7 फीसदी से घटकर 42.3 फीसदी रह गया। इसी दौरान सरकारी बैंकों का कासा कम घटा-बढ़ा है। भारतीय स्टेट बैंक का कासा अनुपात 41.18 फीसदी से कम होकर 39.2 फीसदी और पंजाब नैशनल बैंक का 42.47 फीसदी से कम होकर 38.12 फीसदी रहा। ज्यादातर अन्य बैंकों में गिरावट 1 फीसदी के करीब रही।

इसी दरम्यान ज्यादातर बैंकों के सीडी बढ़ गए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 27,971 करोड़ रुपये से बढ़कर 35,260 करोड़ रुपये के हो गए। निजी बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक के सीडी 1.53 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.90 लाख करोड़ रुपये हो गए। आगे का रास्ता साफ है। चालू खाते कि लिए बैंकों को कारोबारी ग्राहक बढ़ाने होंगे, लेनदेन बढ़ाना होगा और नकदी प्रबंधन तथा व्यापार सेवाओं पर ध्यान देना होगा। मगर जमा खातों में रकम लाना ज्यादा मुश्किल है। कुछ बैंकों ने प्रीमियम बचत खातों पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, खुदरा ऋण पर कम ब्याज जैसे फायदे देने शुरू कर दिए हैं।

निजी बातचीत में कई बैंक अधिकारी मानते हैं कि उनका फौरी लक्ष्य वृद्धि नहीं बल्कि कासा जमा में कमी पर अंकुश लगाना है। उन्हें छात्रों, युवा पेशेवरों, महिलाओं, वेतनभोगियों, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनभोगियों के लिए अलग-अलग तरीके अपनाने होंगे। उन्हें कम ब्याज दरों के साथ मुफ्त स्वास्थ्य जांच, रेस्तरां में छूट के कूपन, आकर्षक हॉलिडे पैकेज जैसा कुछ भी करना होगा।

कर लाभ के मामले में बैंक म्युचुअल फंड या शेयर निवेश को सीधे टक्कर नहीं दे सकते। इसकी शिकायत भी वे सरकार से कई बार कर चुके हैं मगर शायद ही कोई सुनवाई हो। किफायती ब्याज के दम पर ही बचत खातों में जमा नहीं बढ़ सकती। अब बैंकों को नए तरीके अपनाने होंगे। साथ ही अगर उन्हें फीस के बजाय ब्याज से कमाई को तवज्जो देते हैं तो म्युचुअल फंड और बीमा बेचने से भी परहेज करना होगा।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

कौशल विकास आधारित पाठ्यक्रम हो

हाल ही में नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने एक साक्षात्कार में कहा कि महंगाई के हिसाब से वेतन में वृद्धि न होने का मुख्य कारण कौशल की कमी है। हम कुशल नौकरियां नहीं दे रहे हैं। कई देशों के आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि हमें कौशल पर काम करने की जरूरत है। यह बहुत कमजोर स्थिति में है। हालांकि केंद्र सरकार कदम उठा रही है, परंतु राज्यों को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। जिला स्तर पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं नौकरियां पैदा होंगी। चीन की तर्ज पर हमारे यहां भी विद्यार्थियों को स्कूलों में ही कौशल विकास से लैस करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें नौकरी तलाशने के दौरान अलग से कौशल विकास का प्रशिक्षण न लेना पड़े। साथ ही, कौशल प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार करते समय स्थानीय के साथ-साथ वैश्विक जरूरतों को भी ध्यान में रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में पूरी दुनिया में नए प्रशिक्षित कामगारों की जरूरत बढ़ गई है। प्रशिक्षित भारतीय युवा इस जरूरत को आसानी से पूरा कर सकते हैं। कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं में टेलरिंग, कंप्यूटर, ब्यूटीशियन, सौर ऊर्जा टेक्नीशियन, घरेलू उपकरणों की रिपेयरिंग, कंप्यूटर एकाउंटिंग, टैली, सिलाई- कढ़ाई आदि विधाओं में समुचित प्रशिक्षण व प्रमाण पत्र प्रदान कर हजारों युवाओं को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेजों में ही कौशल से प्रशिक्षित किया जाए जिससे उन्हें नौकरी तलाशने में अलग से प्रशिक्षण न लेना पड़े

बेरोजगार कहां से देंगे आवेदन के लिए इतनी फीस

पंजाब सरकार ने हाल में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल के लगभग 1,746 पदों पर भर्ती निकाली है। रोजगार देने का सरकार का यह प्रयास काफी अच्छा है लेकिन इन पदों की भर्ती के लिए जो शुल्क तय किया है वह बहुत ही ज्यादा है। इसके आवेदन के लिए सामान्य वर्ग के लिए 1,200 और अन्य वर्गों के लिए 700 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए जब आवेदन मांगे गए थे तब इसके लिए फीस सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,000 और आरक्षित वर्गों और महिला के लिए 800 रुपये थी। केंद्र और प्रदेश की सरकार को बेरोजगारों से नौकरी के आवेदन के लिए फीस नहीं लेनी चाहिए। गरीब बेरोजगार युवा नौकरी के लिए भारी फीस कैसे भर सकेंगे। सरकारी विभागों में जब कोई नौकरी का विज्ञापन निकलता है तो कुछ बेरोजगार नौजवान उसके लिए इस वजह से आवेदन नहीं करते कि उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। सरकारों को बेरोजगारों पर परीक्षा फीस के बोझ कम करने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए इतनी ज्यादा फीस नहीं रखनी चाहिए। सरकार को कम से कम फीस रखना चाहिए जिससे हर जाति वर्ग का गरीब से गरीब बेरोजगार भी नौकरी के लिए आवेदन कर सके।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्की (बाएं) ने गुरुवार को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की बैठक में पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कहा कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सूचना देने पर रोक के बाद फ्रांस उसे सैन्य खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा है।

7.25 प्रतिशत हिस्सा उच्च शिक्षा बजट के रूप में खर्च करता है मणिपुर, जबकि दिल्ली में 1.67 प्रतिशत ही खर्च होता है इस मद में। वहीं, प्रति युवा शिक्षा पर खर्च के मामले में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आगे हैं, जबकि राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ पीछे हैं।

आजकल

ज्ञान आधारित आर्थिकी की ओर अग्रसर भारत

कैलाश बिश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समावेशिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है, ताकि हर वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई से लेकर नौकरी तक समान अवसर मिल सकें। इस उद्देश्य से यूजीसी ने एक नया ड्राफ्ट तैयार कर सभी कुलपतियों को भेजा है और उनकी राय मांगी है। यूजीसी का यह प्रयास विश्वविद्यालयों को अधिक न्यायसंगत, समावेशी और समानता आधारित शिक्षा केंद्रों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के व्यापक उद्देश्यों को साकार करेगा

प्रतीकात्मक

किसी भी समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार उसकी शिक्षा प्रणाली होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रस्तावित नए विनियम इस बात का प्रमाण हैं कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था अब समावेशिता और समानता की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। यह केवल नीतियों का पुनर्गठन नहीं, बल्कि ज्ञान को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने की एक दृढ़ कोशिश है बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अवरोध के। अब, यूजीसी ने "उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने" संबंधी विनियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। यह उम्मीद जगाने वाला कदम है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली एक नए युग की ओर अग्रसर है, जहां समावेशन, नवाचार और व्यावहारिक ज्ञान को प्राथमिकता दी जा रही है। यूजीसी द्वारा नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत पिछले चार वर्षों में उठाए गए कई कदम उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने का प्रयास हैं। चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, डिजिटल विश्वविद्यालय, एकीकृत क्रेडिट फ्रेमवर्क, व्यावसायिक शिक्षा और मातृभाषा में अध्ययन जैसी पहलों ने शिक्षा को पारंपरिक सीमाओं से मुक्त कर एक समावेशी और व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया है। इन सुधारों का उद्देश्य सभी वर्गों को समान अवसर देना, ज्ञान को रोजगारोन्मुख बनाना और भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यदि इन प्रयासों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक स्वर्णिम युग का आरंभ सिद्ध होगा।

वैश्विक मानकों के अनुरूप : चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम उच्च शिक्षा को अधिक व्यापक और लचीला बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। अब विद्यार्थी अपनी परिस्थितियों के अनुसार मल्टी-एंट्री और मल्टी-एग्जिट की सुविधा के साथ अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकते हैं। यह पहल उन छात्रों के लिए विशेष रूप से हितकारी होगी जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। इससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था वैश्विक मानकों के अनुरूप होगी, जहां विद्यार्थी अपनी रुचि और आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं।

जिस प्रकार प्रकृति में विविधता ही उसकी सजीवता का प्रमाण है, उसी प्रकार शिक्षा में बहु-विषयक दृष्टिकोण न केवल ज्ञान को समृद्ध करता है, बल्कि उसे अधिक व्यावहारिक भी बनाता है। संस्थान स्वायत्तता और बहु-विषयक शिक्षा के तहत मोनो-डिसिप्लिनरी संस्थानों को मल्टी-डिसिप्लिनरी बनाया जा रहा है, जिससे छात्र विज्ञान, कला और अन्य विषयों का समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकें। इससे भविष्य के स्नातक संकीर्ण विषयों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण के साथ समाज में योगदान देने में सक्षम होंगे।

प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा का माध्यम थे, उसी प्रकार आधुनिक समय में डिजिटल शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना इस दिशा में क्रांतिकारी कदम है, जो उच्च शिक्षा को आनलाइन संसाधनों से जोड़कर अधिक सुलभ और वैश्विक बना रहा है। अब विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार पाठ्यक्रमों का चयन कर सकेंगे और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से श्रेष्ठ शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यह उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा जो आर्थिक या भौगोलिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे।

शिक्षा के प्रति रुचि : शिक्षा एक निरंतर प्रवाहमान धारा है, जिसे कृत्रिम अवरोधों से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। स्कूली और उच्च शिक्षा के एकीकरण की पहल इसी भावना को मूर्त रूप देती है, जहां अकादमिक बैंक आफ क्रेडिट और स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा में सुगम प्रवेश की व्यवस्था बनाई जा रही है। यह एक ऐसी प्रणाली विकसित करेगा जिसमें विद्यार्थी बिना किसी जटिल औपचारिकता के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें, जिससे शिक्षा के प्रति उनकी रुचि और प्रतिबद्धता बढ़ेगी।

जिस प्रकार एक सुगंधित पुष्प तभी उपयोगी होता है, जब वह समाज को अपनी सुगंध से महका सके, उसी प्रकार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण होता है, जब वह रोजगारोन्मुख और व्यावहारिक हो। व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण उच्च शिक्षा को मात्र डिग्री प्रदान करने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे रोजगार और उद्यमिता से जोड़ता है। नए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ स्नातक अब उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम बेरोजगारी की समस्या को हल करने में भी सहायक होगा।

शिक्षा में नवाचार : समय के प्रवाह में शिक्षा को भी परिवर्तनशील और नवाचारयुक्त बनाना आवश्यक है। उपरोक्त सभी सुधार न केवल भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सशक्त बनाएंगे, बल्कि इसे एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर भी अग्रसर करेंगे। यूजीसी की यह पहल शिक्षा प्रणाली को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकालकर एक नए युग में प्रवेश करा रही हैं, जहां ज्ञान केवल अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास का आधार बनेगा।

शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समाज को नई दिशा देने का माध्यम भी होनी चाहिए। यूजीसी द्वारा उठाए गए ये कदम न केवल उच्च शिक्षा को अधिक प्रभावशाली, समावेशी और व्यावहारिक बनाएंगे, बल्कि भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी सहायक होंगे। यदि इन सुधारों को प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो आने वाला समय भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक स्वर्णिम युग साबित होगा।

नीति आयोग की रिपोर्ट से सीखने योग्य बातें

भारतीय शिक्षा व्यवस्था आज संक्रमण के दौर से गुजर रही है, जहां गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट 'राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार' उच्च शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह का पहला नीतिगत दस्तावेज है, जो विशेष रूप से राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों में उच्च शिक्षा के वित्तीय परिव्यय, नामांकन प्रवृत्तियों, लैंगिक संतुलन, डिजिटल विभाजन और विश्वविद्यालय घनत्व जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों के बीच शिक्षा व्यय में भारी असमानता देखी जा रही है। जम्मू-कश्मीर (8.11 प्रतिशत) और मणिपुर (7.25 प्रतिशत) जहां अपने शिक्षा बजट का बड़ा भाग व्यय कर रहे हैं, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा पर मात्र 1.67 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है। इसी प्रकार, प्रति युवा शिक्षा पर व्यय में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आगे हैं, जबकि राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ पिछड़ रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि कुछ राज्य उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि अन्य अभी भी संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट में विश्वविद्यालय घनत्व को लेकर भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति एक लाख युवाओं पर 0.8 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन सिक्किम (10.3), अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा कहीं अधिक है। दूसरी ओर, बिहार (0.2) में विश्वविद्यालय घनत्व सबसे कम है, जो उच्च शिक्षा तक पहुंच की गंभीर चुनौती को दर्शाता है। यह स्पष्ट करता है कि राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों की उपलब्धता असंतुलित है, जिससे छात्रों के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करना कठिन हो जाता है।

रिपोर्ट दर्शाती है कि केरल, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में महिला नामांकन पुरुषों से अधिक है, जबकि चंडीगढ़, मिजोरम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में यह संतुलित है। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि कुछ राज्यों ने लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कई राज्य अब भी इस लक्ष्य से दूर हैं। महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए संस्थागत स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, शिक्षा पर वार्षिक व्यय 12 प्रतिशत बढ़कर 9.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह दर्शाता है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन राज्यों के बीच संसाधनों का असमान वितरण अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

रिपोर्ट यह भी इंगित करती है कि ड्रापआउट दरों में कमी आई है- प्राथमिक स्तर पर 1.9 प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर 14.1 प्रतिशत तक, जबकि 2014 से 2022 के बीच उच्च शिक्षा नामांकन में 26.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 28.4 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जिसे 2035 तक 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल असमानता अभी भी बनी हुई है।

नीति आयोग की यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को उजागर करती है और यह दर्शाती है कि यदि भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाना है, तो राज्यों को अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी बनाना होगा। संसाधनों का समुचित वितरण, शिक्षा पर व्यय में वृद्धि, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन और डिजिटल समावेशन को प्राथमिकता देना आवश्यक है। उच्च शिक्षा केवल ज्ञान का विस्तार ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति की कुंजी भी है। इस संदर्भ में नीति आयोग की यह रिपोर्ट राज्यों को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करने का कार्य करती है, जिससे भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सके। (कैलाश बिश्नोई)

खरी-खरी

...और मुझे दिव्य ज्ञान मिल गया

राजेंद्र बज

काफी समय से मैं दुविधापूर्ण स्थिति से गुजर रहा था। इधर वालों की नजर में देश में सब कुछ अच्छा चल रहा था और उधर वालों की नजर में जो कुछ चल रहा था, वह अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन जो खबरों से दूर तक का वास्ता भी नहीं रखते, वे मुझे इन दिनों मौज में दिखाई देते थे। उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं पड़ती कि महंगाई बढ़ रही है या भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। वे देश-दुनिया के घटनाक्रम से निर्लिप्त अवस्था में महर्षि चार्वाक के अनुगामी बने हुए थे। जो व्यक्ति दुनिया के घटनाक्रम से अनजान रहे, वह हर हाल में मस्त रहता है। या फिर सरकार की खैराती योजनाओं का पात्र बनने पर तो चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता था।

ऐसा भी होता है कि दिमागी उथल-पुथल के दौर में कभी-कभी अंतर्मन में ऐसी दिव्य ज्योति जागृत हो जाती है कि जटिल से जटिल समस्या का समाधान होता दिखाई देता है। जी हां, एक प्रकार से ऐसा 'आत्मज्ञान' होता है कि बस कुछ पूछो ही मत। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। हुआ यूं कि दिल दिमाग में बिजली कौंध गई। और मैं यूरेका यूरेका की भांति मन ही मन उबल पड़ा। समस्या का समाधान मिल चुका था। समाधान यह था कि मैं यदि सत्तारूढ़ दल की सदस्यता लेकर उसके खेमे में आ जाऊं, तो मैं और मेरा देश सुनहरे कल की ओर बढ़ता नजर आएगा। और यदि विपक्षी खेमे में आ जाऊं, तो इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाऊंगा कि तकदीर में ऐ मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं। यानी कम से कम दिमाग के जाले तो साफ हो जाएंगे।

अब मैं पूर्ण रूप से निश्चिंत हो चुका हूं। कल तक राजनीतिक शब्दावली में प्रचलित तथाकथित उदारवादी दृष्टिकोण को आत्मसात करता था। जिसके चलते हर किसी विषय पर 'ढुलमुल रवैया' अख्तियार करने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन अब एक समय में एक ही विचारधारा पर सोचने समझने का सबसे बड़ा हेतु मिल गया है। अब मुझे पता चल गया है कि आदमी को राजनीतिक दृष्टि से या तो इधर का होना चाहिए या उधर का होना चाहिए।

पोस्ट

चिंता आपको व्यस्त तो रखती है, लेकिन आपको कहीं नहीं ले जाती। चिंता पर नहीं, बल्कि काम पर ध्यान दें!
हर्ष गोयनका@hvgoenka

'क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने रोजा न रखकर बड़ा तगड़ा गुनाह कर दिया है।' ऐसा कहने वाले मौलाना या तो इस्लाम समझते नहीं या फिर जानबूझकर रमजान के पवित्र महीने में उपद्रव फैलाने का काम कर रहे हैं। इस्लाम में अल्लाह और बंदे के बीच किसी और के दखल की दरकार नहीं है।
रोमाना ईसार खान@romanaisarkhan

शर्मनाक एवं अपमानजनक। ब्रिटेन की सरकार भारत के विदेश मंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही, जिससे खालिस्तानी चरमपंथियों को उन्हें परेशान करने का मौका मिल गया। क्या यही वह 'कानून और व्यवस्था' है, जिसका ब्रिटेन दावा करता है? अगर ब्रिटेन राजनयिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता तो वह चरमपंथ से लड़ने का दावा कैसे कर सकता है? यह तो भयानक लापरवाही है।
अभिषेक सिंघवी@DrAMSinghvi

झारखंड डायरी

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

बाबूलाल मरांडी पर ही भाजपा का दांव

झारखंड विधानसभा का चुनाव परिणाम आने के लगभग तीन माह बाद राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। 24 घंटे से भी कम अंतराल में ही इससे जुड़ी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। बुधवार पांच मार्च को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को शीर्ष नेतृत्व ने इस निमित्त पर्यवेक्षक बनाया था। गुरुवार को आकर उन्होंने इस बाबत औपचारिकताएं पूरी की। आशा के अनुरूप पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर ही भाजपा ने दांव लगाया है। मरांडी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे। ऐसा कर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य में अपने विधायकों के बीच जारी संशय की स्थिति को भी समाप्त करने की दिशा में पहल की है। राज्य का प्रमुख विपक्षी दल होने के कारण भाजपा विधायक दल के नेता को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल होगा। नेता नहीं चुन पाने के कारण भाजपा की किरकिरी हो रही थी और इस परिस्थिति ने उसके नेतृत्व वाले घटक दलों समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को भी निशाना साधने का मौका दे दिया था। भाजपा के समक्ष राज्य में चुनौती कम नहीं है। राज्य की सत्ता में वापसी करने का पार्टी का मंसूबा असफल रहा। जबकि झारखंड में जीत के लिए कद्दावर नेताओं को भाजपा ने बतौर चुनाव प्रभारी यहां जिम्मेदारी दी थी।

मध्य प्रदेश में लंबे समय तक शासन करने वाले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जैसे सुलझे नेता को यहां चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका साथ असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा थे। प्रचार युद्ध से लेकर जमीनी लड़ाई में भाजपा ने पूरी शक्ति लगा दी थी। राज्य में आदिवासी समुदाय को आकर्षित करने के लिए पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इसी समुदाय का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोग किया गया। लेकिन सत्ता में आने से दूर रही भाजपा ने ना सिर्फ पराजय का स्वाद चखा, बल्कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसके सीटों की संख्या तक कम हो गई। राज्य में आंशिक तौर पर उसका वोट प्रतिशत भी प्रभावित हुआ, जबकि भारी बहुमत के साथ हेमंत सोरेन ने सत्ता में शानदार तरीके से वापसी की।

भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बाबूलाल मरांडी (बाएं) को बधाई देते भूपेंद्र यादव। जागरण

भाजपा की मुश्किल यह है कि उसे ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। कई बड़े नेता चुनाव हार गए। आदिवासी सुरक्षित सीटों पर तो भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया। अब पार्टी के समक्ष कई मोर्चे पर चुनौती है। विधायक दल का नेता चुनने में देरी को इसकी बड़ी वजह में से एक कहा जा सकता है।

भाजपा में यह मंथन चल रहा था कि किस प्रकार आदिवासी और ओबीसी का समन्वय बनाकर राज्य में प्रभावी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज की जाए। इस पसोपेश में काफी दिन गुजर गए और भाजपा के विधायकों की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वैसे विधायक अनुशासन की डोर से बंधे थे, लेकिन आफ द रिकार्ड बातचीत में उनका धर्मसंकट स्पष्ट झलक रहा था। वे कहने लगे थे कि किसी विधायक को नेता चुन लिया जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। विधानसभा में विधायक दल के नेता के बगैर पार्टी नेतृत्व विहीनता की स्थिति में थी। चुनाव परिणाम जारी होने के लगभग एक माह बाद ही भाजपा में हुई एक बड़ी घटना ने सबका ध्यान खींचा था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। इसे उनके समर्थकों ने फिर से उनकी राज्य की सक्रिय राजनीति में वापसी से जोड़कर देखा। यह भी कहा गया कि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। वैसे पांच साल राज्य में शासन कर चुके रघुवर दास की राजनीतिक सक्रियता फिलहाल जमशेदपुर तक सिमटी हुई है।

बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाए जाने की स्थिति में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है। इस पर ओबीसी समुदाय से किसी व्यक्ति को अवसर दिया जा सकता है। भाजपा विधायक दल का नेता चयन नहीं होने के कारण राज्य में एनडीए की एकजुटता पर भी सवाल उठने लगे थे। जदयू से एकमात्र विधायक सरयू राय ने यहां तक कह दिया है कि एनडीए जैसा झारखंड में कुछ नहीं है। सभी अलग-अलग बैठकें करते हैं और सिर्फ विधानसभा में एक जगह सीट आवंटित होने से गठबंधन नहीं हो जाता।

उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसा कि अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नेता चुनने में अक्षम है तो सभी भाजपा विधायकों को सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि देर से ही सही, भाजपा विधायक दल के नेता के चयन के बाद भी पार्टी की चुनौतियां कम नहीं होने वाली। इसे विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज्यपाल के अभिभाषण के उत्तर में दिए गए भाषण से भांपा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे विपक्ष यानी भाजपा के हर गेंद पर छक्का लगाएंगे। ऐसे में बाबूलाल मरांडी झारखंड की राजनीतिक पिच पर सत्तारूढ़ गठबंधन को कितना छका पाते हैं, यह देखना होगा।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या सपा नेता अबू आजमी द्वारा औरंगजेब का महिमामंडन विपक्षी गठबंधन के लिए संकट बन रहा है?

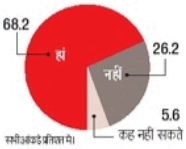

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या औरंगजेब का महिमामंडन करने वाले देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

व्यापारी हैं ट्रम्प जी करें सिर्फ व्यापार,
संबंधों का हो रहा तो हो बंटाधार।
तो हो बंटाधार बढ़े बस खूब कमाई,
बना रहे वो मुल्क जोड़कर राई - राई।
चचा बड़े हैं आप समझिए जिम्मेदारी,
लेकर नव अवतार बन गए क्यों व्यापारी!
- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

डिजिटल मंचों का दुरुपयोग

डा. वेदप्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

डिजिटल मंचों पर अभिव्यक्ति की आजादी के संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। लिहाजा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को तत्काल नया कठोर दंडात्मक कानून बनाना चाहिए

अभिव्यक्ति व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति के अभाव में कुंठा एवं नकारात्मकता के बढ़ने की आशंका है। भारतीय ज्ञान परंपरा और संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी देते हैं। यहां कोई भी बात अथवा विचार किसी पर थोपा नहीं जाता, अपितु उस पर समग्रता में बातचीत करते हुए अथवा संवाद के जरिए स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में अभिव्यक्ति की आजादी को कुछ लोग डिजिटल मंच को कुछ भी बोल देने का लाइसेंस समझ रहे हैं, क्या यह एक नागरिक और सभ्य समाज के लिए घातक नहीं है? पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल मंचों पर अभद्रता, अश्लीलता और हिंसा की बाढ़ आ गई है। विभिन्न डिजिटल मंच सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने पर प्रहार करने के साथ-साथ मानसिक प्रदूषण भी फैला रहे हैं। जल्दी लोकप्रियता और अधिक व्यू मिलने की चाहत में निजता को भी रील बनाकर फैलाने की होड़ लगी हुई है। अनेक वीडियो एवं वेबसीरीज भिन्न-भिन्न रूपों में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इन पर तत्काल नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है?

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को एक कामेडी शो के दौरान अभिभावकों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। ध्यातव्य है कि विगत दिनों उस शो के दौरान रणवीर के साथ वहां मंच पर उपस्थित अन्य लोगों ने भी अश्लील शब्दों एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सैकड़ों युवक-युवतियां उस कार्यक्रम में बैठे हुए थे। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस प्रकार की अश्लीलता और अभद्रता उचित है? कुछ समय में ही इस अभद्र कामेडी शो को करोड़ों लोगों ने देख लिया। इस प्रकार की अश्लीलता एवं अभद्रता का यह पहला मामला नहीं है। हमारे देश में किसी बड़ी घटना के बाद ही प्रशासन एवं सरकार जागती है।

आइटी नियम : इलाहाबादिया प्रसंग के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय डिजिटल मंचों विषयक मौजूदा प्रविधानों की समीक्षा कर रहा है। विचारणीय यह भी है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म, ओटीटी प्लेटफार्म, समाचार प्रकाशक और डिजिटल मीडिया के लिए बना। जिसका उद्देश्य एक खुले, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करना है। क्या विभिन्न प्लेटफार्म इस नियम के उद्देश्य में वर्णित चारों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खरे उतर रहे हैं? नियम में सामग्री प्रसारित करने वाले मध्यस्थों की भी चर्चा है। वहां कहा गया है- मध्यस्थ को बौद्धिक संपदा अधिकारों, अपमानजनक और अश्लील सामग्री, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, भारत के किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री की चोरी को रोकने के लिए नीतियां बनानी चाहिए।

ध्यान रहे कि नियम में सामग्री की चोरी को रोकने के लिए नीतियां बनाने की बात है किंतु अश्लील सामग्री और अभद्र भाषा आदि के प्रयोग पर दंड का प्रविधान कहीं दिखाई नहीं देता। नियम में प्रसारित की जाने वाली सामग्री का पांच श्रेणियों में वर्गीकरण है। क्या केवल किसी सामग्री पर यू, यू/ए आदि लिख देना ही पर्याप्त है? वैसे शिकायत निवारण के लिए भी तीन स्तर बनाए गए हैं। पहले में प्रकाशकों द्वारा स्व-नियमन, दूसरे में प्रकाशकों के स्व-नियामक निकायों द्वारा स्व-विनियमन और तीसरे में निरीक्षण तंत्र की बात कही गई है। क्या ये सभी प्रविधान केवल दिखावटी नहीं हैं?

अश्लील और अभद्र भाषा : इंटरनेट मीडिया कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं, देवी-देवताओं आदि पर भी अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुर्खियों में आने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के वीडियो अनेक बार सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का भी कारण बनते हैं। क्या ये विषय भी कठोर दंडात्मक कानूनी प्रविधानों के दायरे में नहीं आने चाहिए? अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ कहीं भी, कुछ भी बोलना, करना अथवा दिखाना नहीं है, अपितु यह दायित्व के साथ जुड़ी है। भारतीय संविधान के भाग तीन मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 में वाक् स्वातंत्र्य के अंतर्गत लिखा है- सभी नागरिकों को वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार होगा। संविधान की उद्देशिका में भी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन है, किंतु ध्यान रहे संविधान में स्थान स्थान पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने की बात भी प्रमुख है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलते वालों पर संविधान लागू नहीं होता? यदि संविधान सभी को समान रूप से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है तो जिम्मेदारियों का आह्वान भी करता है। ऐसे में अश्लीलता, अभद्रता और हिंसा के प्रति जीरो टालरेंस अपनाना होगा।

अश्लील कंटेंट पर कसे शिकंजा। प्रतीकात्मक

****

दैनिक जागरण

स्वभाव व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला है

मतदाताओं की पहचान

यह सराहनीय है कि चुनाव आयोग मतदाताओं को विशिष्ट पहचान प्रदान करने की पहल कर रहा है। इससे अलग-अलग राज्यों में मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपिक संख्या एक जैसी होने की समस्या से तो मुक्ति मिलेगी ही, किसी मतदाता के अन्यत्र कहीं बस जाने पर उसका पता लगाना भी आसान होगा, लेकिन इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था करना भी समय की मांग है कि वोट कोई मतदाता अपने आवास स्थल से अन्यत्र कहीं हो तो वहीं भी मताधिकार का उपयोग कर सके। ऐसी व्यवस्था बनाना इसलिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब एक बड़ी संख्या में लोग काम-धंधे, पढ़ाई के सिलसिले में दूसरी जगह जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं, जो वहां अस्थायी तौर पर रहने लगते हैं। ऐसे लोग चुनावों के दौरान मताधिकार का उपयोग तभी कर सकते हैं, जब वे वोट देने के लिए वहां लौटें, जहां वे मतदाता के रूप में दर्ज हों। चूंकि सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं होता, इसलिए वे चाहकर भी वोट नहीं कर पाते। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि वोट प्रतिशत कम रहने का एक कारण यह भी है। अब जब एक साथ चुनाव की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तब यह सोचा ही जाना चाहिए कि मतदाता देश में कहीं से भी मतदान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आवश्यक हो तो मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए। अभी यह व्यवस्था स्वैच्छिक है।

एक समय मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने की पहल की गई थी, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति उठा दी और एक जरूरी पहल थम गई। समझना कठिन है कि कुछ दलों को मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने पर आपत्ति क्यों है? आखिर मताधिकार को सुगम-सुलभ बनाने में अड़ंगा लगाने का क्या औचित्य? यदि फर्जीवाड़ा लाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्थायी खाता संख्या अर्थात पैन कार्ड और मोबाइल सिम समेत अन्य दस्तावेजों को आधार से जोड़ा जा सकता है तो मतदाता पहचान पत्रों को क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए और वह भी तब, जब इससे फर्जी वोटरों का पता लगाने में मदद मिलेगी? जो काम फर्जी मतदान रोकने में सहायक हो सकता है, उसके विरोध का कोई तार्किक आधार नहीं दिखता। यह तर्क खोखला ही अधिक है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। आखिर ऐसा तो है नहीं कि इससे यह पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट दिया? हालांकि चुनाव आयोग ने अलग-अलग राज्यों में एक जैसी ईपिक संख्या को लेकर उठे संदेह का समाधान कर दिया है, लेकिन उचित यह होगा कि उसे मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ने का अधिकार प्रदान किया जाए। इससे मतदाताओं को सुविधा होगी, फर्जी मतदान पर लगाम लगेगी और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा।

उपचार में सुविधा

बिहार के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है। विशेषज्ञ डाक्टर से लेकर नर्सिंग कर्मचारियों की संख्या निर्धारित मानक से कम है। ये पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। महिला डाक्टर तो बहुत से अस्पतालों में हैं ही नहीं। मेडिकल कालेज से लेकर जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य जगह इसी तरह की स्थिति है। कई स्वास्थ्य केंद्र तो नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहे हैं। इस कारण मरीजों को निजी अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। वहां उनका आर्थिक शोषण होता है। डाक्टरों की भर्ती को लेकर लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। अब इसके जल्द पूरे होने की आस इसलिए जगी है, क्योंकि इस संबंध में बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही अंतिम चरण में है। पांच हजार से अधिक डाक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इनमें 3623 विशेषज्ञ चिकित्सक पदाधिकारी, 667 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी और 828 दंत चिकित्सक होंगे। बिहार विधान परिषद में एक प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री नीरज कुमार सिंह की ओर से यह जानकारी देने की बात उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक डाक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी। वैसे, देखने वाली बात यह है कि अभी जितने डाक्टर तैनात हैं, वे भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। समय से ड्यूटी पर नहीं आने से लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस करने सहित कई शिकायतें रहती हैं। इसपर भी ध्यान देने के साथ सख्ती की जरूरत है। डाक्टर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, इसकी भी सख्ती से मानीटरिंग हो। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाए। तभी गरीब मरीजों को उपचार की सुविधा मिल सकेगी।

पांच हजार डाक्टरों की भर्ती से अवश्य ही सरकारी अस्पतालों में गरीब मरीजों को लाभ मिल सकेगा

नफरत पैदा करने वाली विचारधारा

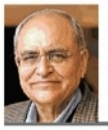

बलबीर पुंज

आरथा- मजहब प्रेरित हिंसा का चक्र तब तक नहीं रुकेगा, जब तक उस मानसिकता से मुक्ति नहीं मिलती, जो अपने सिवा अन्य को अस्वीकार करती है

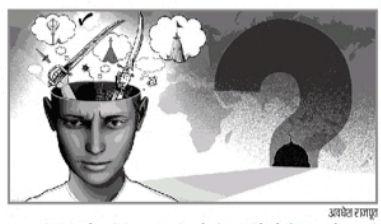

प्रतीकात्मक चित्र

स्वास्थ्यकर्मियों की जीवन बचाने वाला और ईश्वर के प्रतिरूप की संज्ञा दी जाती है, पर बीते दिनों आस्ट्रेलिया में स्वास्थ्यकर्मियों की एक करतूत ने इस पेशे को कलंकित करने का काम किया। इससे जुड़े स्वास्थ्यकर्मी केवल मजहबी कारणों से एक वर्ग विशेष के रोगियों के साथ भेदभाव की बात गौरवान्वित होकर स्वीकार रहे हैं। वे नफरत की आग में उपचाराधीन यहूदी रोगियों को जान से मारने का भी दावा कर रहे हैं। अखिर मजहब के नाम पर मानवों को प्रताड़ित करने के पीछे यह कौन सा जहरीला दर्शन है? यह बाकया आस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बैंक्सटाउन अस्पताल का है। वहां कार्यरत दो मुस्लिम नर्सों (महिला सहित) द्वारा 11 फरवरी को ढाई मिनट के वीडियो पैट में एक इजरायली व्यक्ति से संवाद में दिखाया गया। इसमें पुरुष चिकित्साकर्मी कहता है, "मैं इससे अत्यंत व्यथित हूं कि आप इजरायल से हैं, आपको मरना ही होगा।" इसमें स्वास्थ्यकर्मी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उपचाराधीन कई यहूदी मरीजों को 'जहन्नुम' भेजा है। अर्थात मौत के घाट उतारा है।

पिछले एक साल से आस्ट्रेलिया में गैर-मुस्लिम विशेषकर यहूदी-विरोधी भावनाओं में वृद्धि हुई है। समुदाय से जुड़े लोगों के घरों, कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की कई खबरें आई हैं। इसमें एक स्कूल और दो सिनेगाग (यहूदी पूजास्थल) को आग के हवाले तक कर दिया गया था। यहूदियों से घृणा केवल आस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं। अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है। नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में गत सात नवंबर को एक फुटबाल मैच के दौरान यहूदियों को फलस्तीन समर्थकों द्वारा निशाना बनाया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के बीच नीदरलैंड में यहूदियों पर हमलों में 245 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में ब्रिटेन में 550 यहूदी-विरोधी घटनाएं दर्ज हुई थीं। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश भी इससे अछूते नहीं हैं।

कथित तर्कवादी हालिया यहूदी-विरोधी घटनाओं को फलस्तीन समर्थक आतंकी संगठन हमास द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल पर घातक जिहादी हमले और प्रतिक्रियास्वरूप उस पर गाजा-पट्टी पर इजरायली सैन्य कार्रवाई से जोड़कर देखते हैं। इसके उलट वास्तविकता यही है कि यहूदियों को किसी एक हालिया घटना से नहीं, बल्कि उन्हें मजहबी आधार पर चौथी शताब्दी से ईसाइयत और फिर आठवीं सदी में इस्लाम के उदय से सतत उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मध्यकालीन यूरोप में यहूदियों का मजहबी दमन और तीव्र हुआ। 1466 में तत्कालीन पोप पाल-द्वितीय के निर्देशानुसार क्रिसमस के दिन रोम में यहूदियों को निर्वस्त्र कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। कालांतर में यहूदी पुजारियों (रब्बियों) को विधर्मी के वस्त्र पहनकर परेड करई जाने लगी। 25 दिसंबर, 1881 को फ्रेंकैड के बारसा में 12 यहूदियों की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। उत्पीड़न की ऐसी अनगिनत घटनाएं प्रमाणित करती हैं कि यहूदी-विरोधी अभिशापों ने सदियों तक यूरोप में उनके लिए एक असुरक्षित और हिंसक परिवेश बनाया, जिसे चर्च का समर्थन प्राप्त था। गहरी जड़ें जमा चुकी इसी घृणा ने 1933-45 के बीच एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में यहूदियों के व्यापक नरसंहार 'होलोकास्ट' का रूप लिया। इस अवधि में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिसमें 15 लाख बच्चे भी शामिल थे।

जहां यहूदियों को दुनिया भर में दमन का सामना करना पड़ता रहा है, वहीं भारतीय भी अपनी जमीन पर उत्पीड़न के शिकार होते रहे हैं। भारत में मजहबी अत्याचार की शुरुआत आठवीं शताब्दी में अरब आक्रांता मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण के साथ हुई। इस्लामी आक्रांताओं की इसी मानसिकता के वशीभूत गजनी, गौरी, खिलजी, तैमूर, तुगलक, बाबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसे शासकों ने भारत की मूल सनातन संस्कृति, मानबिंदुओं और परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया। इन आक्रांताओं के वैचारिक उत्तराधिकारी आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में इसी जहरीले चिंतन के साथ सक्रिय हैं। इसी जिहादी मानसिकता के कारण भारत का बड़ा भाग इस्लामी निर्वज्ञण में चला गया, जहां हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन किसी शरीयत व्यवस्था के अनुरूप दोयम दर्जे के नागरिक हैं।

जब मध्यकाल में उत्तर-भारत इस्लामी आतंकवाद से त्रस्त था, तब 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जेसुइट मिशनरी फ्रांसिस जेवियर ने ईसाइयत के प्रचार हेतु कदम रखा। उसने 'गोवा इंक्विजीशन' के अंतर्गत न केवल हिंदुओं, बल्कि उन ईसाइयों के खिलाफ भी हिंसक मजहबी अभियान चलाया, जो रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं-परंपराओं का पालन नहीं कर रहे थे। इसकी भयावहता को संविधान-निर्माता बाबासाहेब आंबेडकर ने अपनी रचनाओं में उकेरा था। विडंबना है कि यह मतांतरण स्वतंत्रता के बाद सेक्युलरिज्म के नाम पर आज भी जारी है, जिसमें लालच, धोखाधड़ी और भय का सहारा लिया जाता है।

यह चिंतनीय है कि स्वयं को सभ्य कहने वाले लोग घृणा फैलाने वालों को महिमामंडित करते हैं। औरंगजेब का महिमांडन इसका उदाहरण है। 'स्टालिन-लेनिन' जैसे तानाशाहों का भी तिरस्कार नहीं किया जाता, जिनके आदेश पर लाखों निर्दोष लोगों को वैचारिक मतभेद-असहमति के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था। भारत में एक फिल्मी परिवार ने अपने बेटे का नाम तैमूर रख, जो प्रमाण है कि क्रूर आक्रांताओं को गौरवान्वित करने की मानसिकता आज भी जीवित है। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण केवल इसलिए किया था, क्योंकि वह मानता था कि तत्कालीन मुस्लिम शासक हिंदुओं के प्रति उतना क्रूर नहीं थे, जितना एक 'काफिर' के साथ किया जाना चाहिए। यह सत्य है कि घृणा से घृणा का ही जन्म होता है। इससे प्रेरित हिंसा का चक्र तब तक नहीं रुकेगा, जब तक उस मानसिकता से मुक्ति नहीं पा ली जाए, जो अपने सिवा अन्य सभी को अस्वीकार करती है और हिंसा को बढ़ावा देती है।

(लेखक 'ट्रिस्ट बिट अयोध्या' और 'नैरेटिव का मायाजाल' पुस्तक के लेखक हैं)

response@jagran.com

गरीब मुस्लिमों के हित में है वक्फ बिल

डा. फैयाज अहमद फैजी

वक्फ संशोधन बिल पर विचार करते सांसद। पाइल

वक्फ बिल के प्रविधान ऐसे हैं, जिनसे मुस्लिम महिलाओं-पसमांदा लोगों की बेहतरी की राह खुलेगी

हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जगदंबिका पाल के नेतृत्व वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के सभी 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी। इसके बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड में व्याप्त अनियमितताओं एवं विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से वक्फ अधिनियम, 1995 के कुछ प्रविधानों को हटाने की बात करता है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण पाना, वक्फ संपत्तियों के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग हितधारक समुदाय के लाभ के लिए ही किया जा सके। सरकार के इन दावों के बावजूद विपक्ष एवं उलेमाओं का एक वर्ग और तथाकथित सेक्युलर-लिबरल बुद्धिजीवियों द्वारा इस प्रस्तावित विधेयक का विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वालों के अपने कुछ तर्क हैं और आशंकाएं भी। वे इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सरकार का हस्तक्षेप मानते हैं। उनका मानना है कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करता है। इस विधेयक के संदर्भ में सतापक्ष और विपक्ष के तो अपने-अपने तर्क हैं ही, जिस मुस्लिम समुदाय के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उसके भीतर भी इस विधेयक को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हैं।

मुस्लिम समाज को एक समतावादी समाज माना जाता है, लेकिन व्यवहार में भारतीय मुस्लिम समाज में भी भेद और स्तरीकरण दिखाई देता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था का अस्तित्व है। इसमें तीन प्रमुख श्रेणियां देखी जाती हैं। अशराफ उच्च वर्ग के मुसलमान माने जाते हैं, जिनका दावा है कि वे अरबी, तुर्की, फारसी या अफगान वंश से संबंधित हैं। अशराफ में सैयद, शेख, पठान और मुगल जैसी उच्च जातियां आती हैं। अजलाफ निम्न वर्ग के मुसलमान माने जाते हैं, जिनका संबंध परिवर्तित हिंदुओं से है। इस श्रेणी में कारीगर, किसान और श्रमिक वर्ग के मुसलमान शामिल होते हैं। अरजाल सबसे निचली श्रेणी के मुसलमान माने जाते हैं, जो मुख्यतः दलित जातियों से मतांतरित हुए हैं। इन्हें समाज में सबसे अंतिम पायदान पर रखा जाता है। नीचे के इन दो मुस्लिम वर्गों को मिलाकर 'पसमांदा मुस्लिम' समूह की रचना होती है। पसमांदा मुस्लिम एक सामाजिक-आर्थिक और जातिगत श्रेणी है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को संदर्भित करती है। "पसमांदा" शब्द का अर्थ है "पीछे छूट गए" या "वंचित"। यह उन मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अधिकतर पसमांदा मुस्लिम अधिकार कार्यकर्ता वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। हैरानी नहीं कि उनकी नजर में वक्फ संशोधन बिल से वक्फ की संपत्तियों के पंजीकरण, सत्यापन, लेनदेन में पारदर्शिता आएगी और गरीब मुसलमानों को वक्फ के बिचौटों से मुक्ति मिलेगी। प्रायः मुसलमानों की हर संस्था पर अशराफ वर्ग यानी खुद को विदेशी मूल का मुसलमान कहने वालों का कब्जा है। वे यह नहीं देख पा रहे हैं कि संशोधित वक्फ बिल के प्रस्तावों में महिलाओं के साथ-साथ पसमांदा वर्ग के पिछड़े मुसलमानों के लिए भी ऐसे अहम प्रविधान किए गए हैं, जिनसे महिलाओं-पसमांदा वर्ग के लोगों की बेहतरी की राह खुलेगी। इस कारण ही प्रमुख पसमांदा संगठन- आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। उसका मानना है कि वक्फ बोर्ड पर कुल मुसलमानों के लगभग 15 प्रतिशत आबादी वाले अशराफ मुसलमानों का कब्जा है। अशराफ उलेमा और राजनीतिज्ञ वक्फ संपत्तियों पर कुंडली मारे बैठे हैं, जबकि 85 प्रतिशत पसमांदा (अति पिछड़ा एवं वंचित) मुसलमानों को वर्षों से मुगतुआ दिखाई जा रही है। उन्हें वक्फ संपत्तियों से कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले मौलाना अरशद मदनी और उन जैसे तमाम लोगों की दलीलें मतलबपरस्ती वाली हैं। इन लोगों ने पसमांदा मुसलमानों के हित में कभी कुछ नहीं किया, उल्टे उनका इस्तेमाल किया है। वक्फ संशोधन बिल लाकर सरकार कुछ अच्छा करने जा रही है तो ऐसे लोग एवं उनके रहनुमें सरकार के खिलाफ अभियान चलाने में जुटे हुए हैं। बेहतर होगा कि जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, वे यह सुनें कि पसमांदा मुसलमान क्या कह रहे हैं?

वक्फ की संकल्पना जिस नेक इरादे के साथ की गई थी, उसमें समय के साथ तमाम बुराइयां घर कर गईं। वक्फ की आड़ में कई जगहों पर धूं-धांधिया पैदा हो गए, जिन्होंने कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लिया और सरकार से मिलने वाले हर लाभ का खुद फायदा उठाने लगे। धूं-धांधिया वक्फ की जमीन को निजी संपत्ति बनाकर बेच रहे हैं और नाम मात्र के भाव में लीज कराकर बड़े-बड़े शापिंग कांप्लेक्स बनाकर मोटा किराया वसूला रहे हैं। चूंकि इन पर रोक लगाने के लिए भी वक्फ अधिनियम में यथोचित बदलाव का किया जा रहा है, इसलिए वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है।

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

इच्छा और आत्मसंयम

इच्छा मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है। इच्छा भौतिक भी हो सकती है, जो धन, संपत्ति या सुख-सुविधाओं से जुड़ी होती है और आध्यात्मिक भी, जो ज्ञान, आत्मज्ञान या धन, संपत्ति से संबंधित होती है। आज के समय में मनुष्य अपनी इसी क्षमता को संभाल नहीं पा रहा है। वह इच्छाओं का गुलाम होता जा रहा है, जिसमें अंततः उसे दुख भोगना पड़ रहा है। इच्छा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह हमारी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, सपनों या निर्धारित लक्ष्यों से जुड़ी हो सकती है। यह हमें प्रेरित करती है। कहीं न कहीं, इच्छा ही जीवन की गति का आधार भी है। जीवन में आगे बढ़ने की लालसा, कुछ पाने की चाह और उस चाहत के लिए किया गया प्रयास, इच्छा के कारण ही संभव होता है, लेकिन जब यही इच्छा अनियंत्रित हो जाती है, तो व्यक्ति के दुख और असंतोष का कारण बन जाती है। अनुभव के आधार पर कहा गया है कि "अति सर्वत्र वर्जयेत।" अर्थात किसी भी चीज की अधिकता बुरी होती है। अति करने पर औषधि भी विष के समान प्रभाव डालने लगती है। यही कारण है कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखना हमारी प्रगति, आत्मविकास और विशेष रूप से मानसिक शांति के लिए अति आवश्यक है।

इच्छाएं असंख्य हो सकती हैं और यह संभव भी नहीं है कि हमारी हर इच्छा पूरी हो, लेकिन जिनमें आत्मसंयम होता है, वे ही इच्छा रूपी भंवर से निकले अमृत की चख्ख पाते हैं। स्पष्ट है कि मन-मस्तिष्क में इच्छा उत्पन्न होना गलत नहीं है, लेकिन उस पर बुद्धि-विवेक का नियंत्रण होना भी आवश्यक है। मनुष्य में इसे नियंत्रित करने की समझ होनी चाहिए। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सीख ले, तो उसका जीवन शांति, आनंद से परिपूर्ण होकर बहुत खूबसूरत हो सकता है। अन्यथा वह अपने ही मन के बुने हुए जाल में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ कर लेगा।

लकली आनंद

कार्यबल में बढ़ती महिला शक्ति

डा. गोविंदा शर्मा

हमारे सामाजिक-पारिवारिक परिवेश में दिखता है कि कार्यबल में आधी आबादी की भागीदारी बढ़ ही रही है। इस बदलाव को पुख्ता करने वाले आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार से जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी से जुड़े सर्वेक्षण में सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार वर्ष 2019 में आर्थिक संबंधित गतिविधियों में स्त्रियों की भागीदारी 21.8 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2024 में 25 प्रतिशत हो गई है।

भारतीय महिलाएं सदा से ही श्रमशील भूमिका में रही हैं। खेती-किसानी से लेकर घरेलू कामकाज के किसी न किसी मोर्चे पर डटी रही हैं। स्त्रियों की यह भागीदारी व्यवसायिक गतिविधियों के बजाय अवैतनिक कार्यों में अधिक रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, 2019-2014 के दौरान महिलाओं द्वारा घरेलू काम में निवेश किया गया समय घटा है। मंत्रालय का 'टाइम यूज सर्वे' नामक अध्ययन बताता है कि अवैतनिक घरेलू कार्यों में महिलाओं की भागीदारी पांच साल पहले लगभग 315 मिनट देने की थी। बदलती परिवेश में आधी आबादी द्वारा घरेलू कामकाज को दिया जा रहा वक्त कम हुआ है। वर्ष 2024 में यह अवधि घटकर 305 मिनट रह गई है। आंकड़ों के ठिकाने सकारात्मक रुझान अहम बदलाव को सामने रखते हैं। आमदनी वाले क्रिया-कलापों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ना आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा अहम पक्ष है। देश के विकास में महिलाओं की मजबूत होती स्थिति की बानगी है। आय देने वाली गतिविधियों में महिलाओं के रुचि लेने संबंधित बदलाव व्यक्तिगत चुनाव और पारिवारिक सहयोग के वैचारिक मोर्चे पर भी रेखांकित करने योग्य पक्ष है।

हमारे परंपरागत ढांचे में पुरुषों की तुलना में सामूहिक क्रिया-कलापों में महिलाओं की भागीदारी कम रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के इस सर्वे में भी यह अंतर सामने आया है। आंकड़े बताते हैं कि 41 प्रतिशत महिलाओं ने घर के सदस्यों की देखभाल को समय दिया, वहीं पुरुषों के लिए यह हिस्सा 21.4 फीसद था। स्त्रियां घर के सदस्यों की देखभाल संबंधित कार्यों में हर दिन 140 मिनट बिताती हैं तो पुरुष हर दिन 74 मिनट का वक्त इन गतिविधियों को दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट भी बताती है कि वैश्विक स्तर पर महिलाएं अवैतनिक घरेलू कार्यों के लिए कुल घंटों का 76 फीसद समय देती हैं। भारत सहित अन्य एशियाई देशों में यह आंकड़ा 80 फीसद से भी ज्यादा है। वहीं आक्सफैम की 'टाइम टू केयर' की रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक स्तर पर महिलाएं सालभर में करीब 10 हजार अरब डालर के अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं। ऐसे में वैतनिक कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी का बढ़ना रोजगार के मोर्चे पर सकारात्मक बदलाव है। यह रुझान बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

वैतनिक कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी का बढ़ना रोजगार के मोर्चे पर सकारात्मक बदलाव है

एआइ के युग में भारत की भूमिका

'एआइ क्रांति का साक्षी बनता भारत' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में अश्विनी वैष्णव ने भारत द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मसात करने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा 'इंडिया एआइ मिशन' के तहत डिजिटल प्रगति को सशक्त करने पर प्रकाश डाला है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तेज लहर ने जब विश्व को घेरा, तब भारत मात्र एक दर्शक नहीं, अपितु एक सशक्त भागीदार बनकर उभरा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) की क्रांति ने केवल डिजिटल भारत की अवधारणा को नया आयाम दे दी है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, औद्योगिक परिदृश्यों और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की नई इबारत लिख रही है। तकनीकी प्रगति के इस युग में भारतीय मनीषियों के ज्ञान-विज्ञान को आधुनिक संदर्भों में देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि भारत की बौद्धिक परंपरा ने युगों पूर्व उन अवधारणाओं का प्रतिपादन किया, जो आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आधारशिला मानी जाती हैं। 'योगवाशिष्ठ' में उल्लिखित चेतनशील यंत्रों की परिकल्पना और 'कणाद' जैसी कणनाएं आज की स्वचालित प्रणालियों की ओर संकेत करती हैं। महर्षि वशिष्ठ और ऋषिराज के संवादों में ऐसे यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जो इच्छाओं का संज्ञान लेकर समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है, जैसे आज के आधुनिक एआइ एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के व्यवहार को समझते हुए, प्रतिक्रिया देते हैं। आज एआइ केवल रोबोटिक्स या स्वचालित प्रणालियों तक सीमित नहीं, अपितु यह स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में

मेलबाक्स

चमत्कारी परिवर्तन ला रही है। भारत का 'डिजिटल इंडिया' अभियान, जो डाटा-संचालित अर्थव्यवस्था को सशक्त करने हेतु प्रारंभ हुआ, अब 'एआइ-समर्थ भारत' के रूप में वैश्विक धितिज पर अपनी पहचान बना रहा है। भारत में नवाचार का दायरा लगातार विस्तारित हो रहा है। 10,000 से अधिक स्टार्टअप, जिनमें से अनेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में एक शक्तिशाली नायक की भूमिका निभाने को तत्पर है।

awanishg30@gmail.com

अबू आजमी के बयान पर विवाद

महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान पर देश की राजनीतिक गरमा गई है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने अबू आजमी को सदन के सत्र के लिए निलंबित कर दिया, जिस पर सपा नेता ने नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। उद्धव ठाकरे ने भी अबू आजमी की कड़ी आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में चर्चा के दौरान कहा कि अबू आजमी को उत्तर प्रदेश भेजा जाए, वहां उनका उपचार कर दिया जाएगा। भारतीय इतिहास में औरंगजेब एक शासक के रूप में क्रूर और क्रूर आक्रांता के रूप में ज्यादा जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसके शासनकाल के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे और हिंदू मंदिरों को तोड़ कर मस्जिदों का निर्माण करवा गया था। यदि औरंगजेब पर चर्चा की जाती है, तो किसी तो यह विषय का विषय बनेगा। ऐसे विवादों से हमेशा असंतोष-प्रत्यारोप का दौर चलेगा और समाज में तनाव भी देखने को मिलेगा। यह भी एक गलत परंपरा है कि राजनेताओं का समर्थन करने के चक्कर में हम भी उसी भाषा में चर्चा करना अच्छा लगता है और अपनी राजनीतिक रोटियां सिंक करने का अवसर भी मिलता है, लेकिन यह भी समझना होगा कि इस तरह के विवादों से समाज गुटों में बंटता नजर आता है। यह सब राजनीति के बदले मिजाज का संकेत है। आरएसएस मुखिया मोहन भागवत के इस बयान को भी सभी राजनेताओं एवं राजनीतिक दलों को गंभीर से लेना होगा कि मत भिन्नता के चलते हुए भी सभी को साथ लेना होगा। मेरा मानना है कि जन प्रतिनिधियों एवं राजनेताओं को अपनी बौद्धिक क्षमता को राज्य की प्रगति और जन कल्याण के लिए लगानी चाहिए न कि अनावश्यक विवाद खड़ा करने में।

बीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

इस स्तंभ में पिछली दो तिथि पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संरक्षक- स्व. पूर्णचन्द गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेंद्र मोहन, पूर्व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेंद्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. नि. पीतांबर डीलक्स हाउस 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और इंडोरेंस हाउस प्रा.लि. डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) : चैतन्य प्रकाशपिपासु*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43566300, नोएडा कार्यालय : 0120-4635800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त सामग्री के पाठन एवं संकलन हेतु पी. आर. बी. एक्ट के अंतर्गत उलताही। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हार्ड/ऐप शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 7 मार्च • 2025
www.rashtriyasahara.com

ट्रंप, टैरिफ और विश्व

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में सब को चकित करने वाले जिस तरह की फैसला ले रहे हैं उसके कारण समूचा विश्व परिदृश्य बदल रहा है। अमेरिका के पारंपरिक मित्र देश उनसे दूर होते जा रहे हैं और दूसरी और पारंपरिक शत्रु देश करीब आ रहे हैं। सब कुछ इतनी तेज गति से हो रहा है कि अमेरिका के मित्र और सहयोगी देश स्तब्ध और चिंतित हैं। इस बीच बुधवार को ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों पर 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। सिटी रिसर्च नामक संस्था के अनुमान के मुताबिक ट्रंप के इस फैसले से भारत को प्रतिवर्ष करीब 7 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। सबसे ज्यादा

प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, मेटल, केमिकल और ज्वेलरी हो सकते हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिकी सामानों पर भारत जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका भी भारतीय सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य चैंबर ने चेतावनी जारी किया कि ट्रंप के टैरिफ से विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और 1930 की जैसी महान मंदी आ सकती है। जाहिर है यूक्रेन को लेकर ट्रंप के फैसलों के खिलाफ यूरोपीय देश एकजुट और लामबंद हो रहे हैं और अब टैरिफ में बढ़ोतरी से उनपर विपरीत असर पड़ेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के टैरिफ को बेहद मूर्खतापूर्ण बताते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को खुश करने के लिए कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू किया है। चीन ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अमेरिका युद्ध चाहता है, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या कोई अन्य युद्ध हो। यह स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप 'अमेरिका फर्स्ट' के तहत संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका दुनिया भार की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यदि ट्रंप मानते हैं कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसलिए वह उसके साथ दोस्ताना संबंध काम करना चाहते हैं तो उन्हें यह भी याद रखना होगा कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में भारत की जरूरत पड़ेगी। भारत को टैरिफ से बचने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आगे बढ़ना होगा। यहां के प्रमुख निर्माताओं को अपने उत्पादन को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा ताकि उनकी मांग और बढ़े।

रिश्ते सुधारने की कवायद

पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हर दिन नई करवट लेते दिखाई देते हैं। ताजा घटनाक्रम में बांग्लादेश ने यह उम्मीद जताई है कि वह भारत के साथ मजबूत संबंध का हितैषी है। स्वाभाविक है बांग्लादेश के ऐसा सोचने के पीछे उसकी मजबूरी है। बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त महीने में तख्तापलट के बाद से वहां रह रहे हिन्दू अल्पसंख्यकों के साथ नृशंसता बरती जा रही है। कई हिन्दुओं को मार डाला गया, कइयों के घर बर्बाद कर दिए गए तो कई हिन्दू लड़कियों और महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। भारत के लाख समझाने और बांग्लादेश पर दबाव डालने का भी कोई सकारात्मक परिणाम निकलता नहीं दिखाई दिया। इसके बाद भारत ने जब बांग्लादेश पर नकेल कसी

तो उसका रवैया नरम दिखा। मुहम्मद युनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहिद हुसैन ने यह कहकर कि वह भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है, नरमी के संकेत दिए हैं। हुसैन ने यह भरोसा भी जताया कि भारतीय उच्चायोग जल्द ही बांग्लादेशियों को वीजा जारी करना शुरू कर देगा। दरअसल, बांग्लादेश को अब यह बात समझ में अच्छे से आ गई है कि भारत के साथ रिश्ते खराब करने के दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। बांग्लादेश के साथ भारत के सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच पानी की साझेदारी, सीमा से होने वाले कारोबार और शरणार्थियों के मुद्दे अहम रहे हैं। साझी भौगोलिक स्थिति के कारण दोनों देशों के साथ ये मुद्दे जुड़े रहेंगे। बांग्लादेश चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी, कॉटन, अनाज, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिक उपकरण, प्लास्टिक और इस्पात के लिए भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भी इस नाते विश्व भर में अव्वल है क्योंकि कच्चा माल के लिए वह भारत पर निर्भर है। कुल मिलाकर अगर बांग्लादेश का लंबे वक्त तक भारत से संबंध कड़वाहट भरा रहेगा तो उसकी स्थिरता और पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। बहरहाल, बांग्लादेश को यह बात थोड़ी देर से समझ आई है। अगर उसे तरक्की करनी है और पहले जैसा बनना है तो उसे भारत के साथ रिश्तों को सहज और सौहार्दपूर्ण बनाना ही होगा। देर से ही सही लेकिन लगता है उसे यह बात समझ में आ गई है।

पर्यावरण/अमरपाल सिंह वर्मा

अच्छी बात है डाल्फिन की संख्या बढ़ना

देश में जैव विविधता की समृद्ध परंपरा है। हमारी नदियां जलीय जीवों की कई दुर्लभ प्रजातियों की प्राकृतिक आवास हैं। ऐसे ही जलीय जीवों में महत्त्वपूर्ण जलचर जीव है नदी डॉल्फिन, जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है। तीन मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश की पहली 'नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट' जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत की नदियों में डॉल्फिन की कुल संख्या 6327 दर्ज की गई है। यह उम्मीदों से भरा समाचार है क्योंकि कई सालों से डॉल्फिन की संख्या लगातार कम होने पर चिंता व्यक्त की जाती रही है। यह आंकड़ा यह भी दर्शाता है कि हमारी नदियों का पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर स्थिति में है क्योंकि डॉल्फिन का साफ एवं ताजा पानी में ही जीवित रहना मुमकिन है।

पहला मौका है, जब वैज्ञानिक रूप से सर्वे करके डॉल्फिन की संख्या का पता लगाया गया है। वर्ष 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव और असम राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन को सबसे बड़ा खतरा जल प्रदूषण और अवैध शिकार से है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में बढ़ते औद्योगिक और घरेलू कचरे ने जल की गुणवत्ता को प्रभावित किया है जिससे डॉल्फिन के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचा है। मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल जालों में फंसने से भी इनकी मौत हो जाती है। डॉल्फिन का हर दो-तीन वर्षों में एक बच्चा पैदा होता है। डॉल्फिन के तेल के लिए किया जाने वाला अवैध शिकार चिंताजनक है। डॉल्फिन की तादाद तभी बढ़ेगी जब हम उसे मानव जनित खतरों से भी बचाएंगे। कुदरत का बनाया हर जीव-जंतु, पेड़-पौधे, घास-फूस का अस्तित्व जरूरी है। जैव विविधता का मतलब यही है। अगर कोई एक भी खत्म हो रहा है तो समझिए हम मुश्किल से घिर रहे हैं। डॉल्फिन संरक्षण को लेकर स्थानीय लोगों और ग्रामीण समुदायों की भागीदारी जरूरी है। प्रधानमंत्री का डॉल्फिन के आवासीय क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के लिए जागरूकता यात्राएं आयोजित करने का सुझाव उपयोगी है। नदी डॉल्फिन की संख्या में सुधार सकारात्मक संकेत है लेकिन इसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। यदि हम अपनी नदियों को स्वच्छ रखेंगे और डॉल्फिन जैसे जीवों का संरक्षण करेंगे तो न केवल जैव-विविधता बनी रहेगी, बल्कि हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहेगा।

सही रणनीति अपनाए भारत

टैरिफ वार

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल में 5 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ (प्रतिस्पर्धी शुल्क) लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप द्वारा 4 मार्च से कनाडा और मैक्सिको पर 25 फीसद और चीन के आयात पर भी 10 फीसद अतिरिक्त टैरिफ प्रभावी किए जाने के बाद इन देशों द्वारा भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए जाने से नया ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। यद्यपि अभी ट्रंप ने भारत पर टैरिफ रेट का ऐलान नहीं किया है, किंतु भारत पर टैरिफ वृद्धि चीन और कनाडा से कम ही होगी।

यह स्थिति भारत के पक्ष में है। भारत अभी अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर औसतन 9 फीसद का टैरिफ लगाता है। ऐसे में अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ के आधार पर 9 फीसद से अधिक टैरिफ नहीं लगाएगा। गोल्डमैन सॉक्स के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ से भारत की जीडीपी पर अधिकतम 0.6 फीसद तक असर संभव है, जो की बेहद कम है। सिटी रिसर्च के अनुसार भारत को करीब 7 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, जबकि अमेरिका के साथ व्यापार लक्ष्य 500 अरब डॉलर सुनिश्चित किया गया है। निस्संदेह टैरिफ वॉर की चुनौतियों के बीच भारत अमेरिका के लिए उपयुक्त टैरिफ रियायतों की नई रणनीति के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं की भी नई रणनीति के साथ ट्रंप की टैरिफ मार से मुकाबला करने की डगर पर सुनियोजित रूप से आगे बढ़ रहा है।

खास बात यह भी है कि जहां अमेरिका से निर्मित टैरिफ चुनौतियों के बीच अब भारत को निर्यात के नये मौके मिलने की उम्मीद है वहीं ट्रंप की नीति से भारत को चीन प्लस वन के रूप में वैश्विक व्यापार में तेजी से बढ़ने का मौका भी मिलते दिखाई दे सकेगा। उल्लेखनीय है कि 4 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने बेविनार को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया का हर देश भारत के साथ आर्थिक कारोबारी साझेदारी मजबूत करना चाहता है। ऐसे में भारत के उद्योग-कारोबार क्षेत्र द्वारा नये मौकों को मुट्ठी में करने के लिए तत्परता के साथ बढ़ना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि ट्रंप द्वारा अपनाई जा रही अमेरिका फर्स्ट और रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति के कारण दुनिया में बहुत तेजी के साथ आर्थिक और कारोबारी उठापटक चल रही है। नया व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। वैश्विक व्यापार नये सिरे से दोबारा स्थापित होने जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अब मुख्य स्तंभ के रूप में नहीं बचा है, और सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे के तहत गैर-भेदभावपूर्ण शुल्क खत्म हो रहे हैं। ऐसे में भारत ने इस नये बदलाव को समझते हुए रणनीतिकपूर्वक एक अप्रैल से प्रभावी होने वाले

वर्ष 2025-26 के बजट में अमेरिका से आने वाली वस्तुओं जैसे महंगी मोटरसाइकिल, सैटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस जैसे कुछ सामानों पर शुल्क घटा दिए हैं। मित्र देशों के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की ऐसी नई रणनीति पर बढ़ना शुरू कर दिया है, जिसमें मित्र देशों को पर्याप्त रियायतें भी हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग (ईयू) की प्रेसिडेंट उर्सला वोन लेयेन ने दोनों पक्षों के बीच कारोबार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौता को लेकर जारी किंतु-परंतु को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। दोनों नेताओं ने इस बारे में प्रतिबद्धता जताते हुए अपने संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के हितों के मुताबिक भारत-ईयू व्यापार समझौते पर इस वर्ष 2025 के अंत तक मुहर लगाई जाए। उल्लेखनीय है कि विगत 13 फरवरी मोदी और राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के बीच हुई वार्ता के दौरान द्विपक्षीय कारोबार को 2030 तक 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार पिछले माह फरवरी में भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के व्यवसाय एवं कारोबार मंत्री जोनाथन रेनाल्ड्स ने कहा कि व्यापारिक समझौते का उद्देश्य पांच से छह वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार को तीन गुना करना है। इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार और निवेश समझौते को इसी साल 2025 में पूर्ण किए जाने के मद्देनजर भी भारत ने रणनीति तय की है।

यह बात महत्त्वपूर्ण है कि अमेरिका, यूरोपीय आयोग और ब्रिटेन, इन तीनों का भारत के कुल द्विपक्षीय वैश्विक कारोबार में एक तिहाई से भी ज्यादा का हिस्सा है।

वर्ष 2030 तक भारत इन तीनों के साथ अपने द्विपक्षीय कारोबार को कम से कम तीन गुना बढ़ाने की डगर पर आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से इस समय ट्रंप के टैरिफ तूफान के बीच प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं ऐसी डगर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने पिछले वर्ष अपने तीसरे कार्यकाल से ही लगातार आगे बढ़ाना शुरू किया है। पिछले वर्ष से ही इस रणनीति से द्विपक्षीय व्यापार के अच्छे अध्याय लिखे गए हैं। इन सबके साथ जिस तरह ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की रणनीति के साथ अमेरिका को तेजी से आर्थिक मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी इंडिया फर्स्ट की रणनीति को तेजी से बढ़ा कर घरेलू उद्योग- कारोबार और अर्थव्यवस्था को बेरोकटोक बढ़ाने के मौके को मुट्ठी में ले सकते हैं।

उम्मीद करें कि अमेरिका द्वारा 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने की नई चुनौती के बीच भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा ट्रंप प्रशासन की नीतियों से भारत पर होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों का सतत मूल्यांकन करते हुए रणनीतिक रूप से द्विपक्षीय कारोबार की डगर पर बढ़ा जाएगा। हम उम्मीद करें कि सरकार अमेरिकी टैरिफ की नई चुनौतियों के बीच नई द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं और नये मुक्त व्यापार समझौतों की डगर पर तेजी से बढ़ेगी और अमेरिका सहित दुनिया के कोने-कोने के देशों में कारोबार की नई संभावनाओं को मुट्ठियों में लेते हुए 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की डगर पर तेजी से बढ़ाने में सफल होगी।

(लेख में विचार निजी हैं)

> निश्चित रूप से ट्रंप के टैरिफ तूफान के बीच प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं की ऐसी डगर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल से ही लगातार बढ़ाना शुरू की है। पिछले वर्ष से ही इस रणनीति से द्विपक्षीय व्यापार के अच्छे अध्याय लिखे गए हैं। जिस तरह ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की रणनीति के साथ अमेरिका को आर्थिक मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी इंडिया फर्स्ट की रणनीति पर तेजी से बढ़ रहे हैं

मसालों में लजीज भोजन का छिपा है राज

- भारत को 'मसालों का देश' कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघ (आईएसओ) की सूची में शामिल 109 में से करीब 75 मसाले भारत में पैदा किए जाते हैं। हमारे बाद तुर्किए और फिर बांग्लादेश का नंबर आता है
- कुछ गरम मसाले ऐसे हैं जिन्हें हम भारतीय सुपर मसाले कहते हैं। ये मसाले हैं जायफल, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और जीरा। भारत विश्व में शीर्ष मसाला उत्पादक है, और हल्दी, मिर्च और जीरा उत्पादन में अग्रणी है

स्रोत : मीडिया इनपुट्स

भारत में असमानता आजादी के बाद अब तक के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत की कर प्रणाली बेतुके तरीके से मध्यम वर्ग पर बोझ बन गई है। हैरत नहीं होती देखकर मध्यम वर्ग कर्ज के संजाल में फंसता जा रहा है। कर प्रणाली की समीक्षा किया जाना जरूरी है ताकि करों का बोझ बनिस्बत अमीर वर्ग की ओर बांटा जा सके।

कौशिक बसु, अर्थशास्त्री
@kaushikcbasu

शेयर बाजार — **सतीश सिंह**

कतई न घबराएं निवेशक

अट्ठाईस फरवरी को सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों के क्रैश करने के बाद भी शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। चूंकि, सेंसेक्स में पिछले 5 महीनों से गिरावट दर्ज की जा रही है और निफ्टी में भी 1996 के बाद यानी 29 सालों के बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लिहाजा, छोटे निवेशकों में घबराहट की स्थिति बनी हुई है।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के सूचकांक सेंसेक्स में कुल 30 कंपनियां सूचीबद्ध हैं और एनएसई या निफ्टी में कंपनियां सूचीबद्ध हैं। शेयर बाजार में देसी, विदेशी संस्थागत निवेशक, व्यक्तिगत विदेशी निवेशक आदि सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करते हैं। दोनों सूचकांक बेहद संवेदनशील हैं। जब सूचीबद्ध कंपनियों में से किसी खास कंपनी के शेयर की लगातार बिकवाली की जाती है तो उक्त कंपनी पर से निवेशकों का भरोसा कम हो जाता है और उस कंपनी के शेयरों की कीमत कम हो जाती है, जिससे निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने 100 रुपये में एक्स कंपनी का 1 शेयर खरीदा है और जब उस शेयर की कीमत घट कर 80 हो जाती है तो निवेशक को 20 रुपये का नुकसान होता है।

शेयरों की कीमत में उतार-चढ़ाव आने के कई कारण होते हैं। जैसे कंपनी का खराब वित्तीय प्रदर्शन या फिर कंपनी का किसी विवाद में पड़ना, राजनीतिक अस्थिरता, सरकार की नीतियां, डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना, वैश्विक अनिश्चितता, कारोबारी युद्ध की आशंका, भू-राजनैतिक संकट, अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा अपनाई गई नीतियां आदि। सेबी शेयर बाजार का नियामक है, लेकिन सेबी की उपस्थिति के बावजूद इसमें कृत्रिम रूप से गिरावट लाने और फिर उसे उठाने के कुछ मामले देखे गए हैं। ऐसा कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक नुकसान छोटे निवेशकों को होता है। मामले में हर्षद मेहता कांड का जिक्र किया जा सकता है। बाजार में गड़बड़ी को भांपने के लिए सतर्क रहने और बाजार को समझने की जरूरत है।

जरूरी है कि शेयर बाजार में निवेश को जीवन यापन का जरिया बनाने की कोशिश नहीं की जाए और लालच से बचा जाए। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत

निवेशकों ने बड़ी राशि निवेश कर रखी है, जिनमें अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि लक्जमबर्ग और कनाडा दूसरे एवं तीसरे स्थान पर हैं। 28 फरवरी को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 11,639 करोड़ की बिकवाली की, जबकि इस साल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों ने की है। घरेलू निवेशकों ने 28 फरवरी को लगभग 8 लाख 88 हजार करोड़ रुपये की बिकवाली की। दरअसल,भारत में भीड़ के साथ चलने की परंपरा है। कुछ लोगों को बिकवाली करते देख दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करने लगते हैं। 28 फरवरी को आईटी, टेलीकॉम, स्वास्थ्य, बैंकिंग, एफएमसीजी आदि सभी क्षेत्रों के शेयरों में बिकवाली दर्ज की गई। इसलिए,बाजार के साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं प्रतीत हो रही है। जीडीपी के आंकड़े भी दर्शा रहे है कि विकास की रफ्तार में तेजी आ रही है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी को मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की, जिससे यह 6.50 प्रतिशत से घट कर 6.25 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। गौरतलब है कि करीब 5 सालों के बाद रेपो दर में कटौती की गई है। मुख्य तौर पर महंगाई के कारण केंद्रीय बैंक रेपो दर में कटौती करने से परहेज कर रहा था। पिछले दो सालों में 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच ऋण वृद्धि रहने के बाद समग्र क्रेडिट ग्रोथ बीते कुछ महीनों से धीमी हो रही है। इसका बड़ा कारण उधारी दर का महंगा होना है। दरअसल, बैंकों के पास सस्ती पूंजी नहीं है। इसलिए वे महंगी दर पर ऋण देने को मजबूर हैं। महंगी दर पर ऋण उपलब्ध होने के कारण आमजन और कारोबारी ऋण लेने से बच रहे हैं। इस वजह से, कंपनियों के पास पूंजी की कमी है, जिसके कारण वे पूरी क्षमता के साथ उत्पादन नहीं कर पा रही हैं।

बजट में सरकार ने साफ तौर पर बता दिया है कि उसका मकसद विकास को गति देना है। दिसम्बर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर के 6.2 प्रतिशत रहने से विकास की गति में तेजी आने की उम्मीद बढ़ी है। साथ ही, विकास दर में और भी इजाफा लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कटौती की है। पुनश्चः जनवरी महीने में महंगाई में कमी आने से आगामी मौद्रिक समीक्षाओं में भी रेपो दर में कटौती करने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे देश के विकास की रफ्तार को बल मिलेगा और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो शेयर बाजार में बिकवाली की गुंजाइश कम होगी और निवेशकों को अपने निवेश पर आकर्षक प्रतिफल मिलना संभव सकेगा। इसलिए, निवेशकों को घबराने की कतई जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ बेवजह बिकवाली से बचने की आवश्यकता है।

चेतना — **श्रीराम शर्मा आचार्य**

आत्मा को कितना ही कुचला जाए वह न मरने वाली है, और न हार मानती है। अनसुनी, उपेक्षित पड़ी रहने पर भी अन्तरात्मा की विरोधी आवाज उठती ही रहती है। दुष्कर्म करते समय जी धड़कता और पैर कांपते हैं। यह स्थिति कितनी ही दुर्बल क्यों न कर दी जाए, उसका अस्तित्व बना ही रहेगा और झंझट तब तक चलता ही रहेगा, जब तक दुष्प्रवृत्तियां उस घुसपैठ से अपना पैर वापस न लौटा लें। अन्तर्द्वन्द्व जीवन की शांति और सुव्यवस्था को नष्ट करते हैं। प्रगतिपथ अवरुद्ध करते हैं, और भविष्य को अंधकारमय बनाते हैं। पापों की परिणति से किसी भी बहाने बचा नहीं जा सकता। यह शारीरिक संविधान की सामान्य क्रिया पद्धति हुई। इसके अतिरिक्त समाजगत, प्रकृतिगत एवं ईश्वरीय व्यवस्था के और भी ऐसे कितने ही आधार हैं, जिनके कारण कुमार्गगामी को अपने दुष्कृत्यों के दंड अनेक प्रकार से भुगतने के लिए विवश होना पड़ता है। राजदंड की व्यवस्था इसीलिए है कि दुष्कर्मों की आवश्यक रोकथाम की जा सके और अनीति बरतने वालों को उनकी करतूतों का मजा चखाया जा सके। पुलिस, कचहरी, जेल, फांसी आदि की शासकीय दंड व्यवस्था का अस्तित्व मौजूद हैं। चतुरता बरतने पर भी लोग अक्सर पकड़ में आ जाते हैं, और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दंड भुगतते हैं, बदनामी सहते और नागरिक अधिकारों से वंचित होते हैं। इतने पर भी पीछा नहीं छूटता। शारीरिक और मानसिक व्याधि उन्हें घेरती हैं, और तिल-तिल करके रीतने, काटने जैसा कष्ट देती है। शरीर पर मन का अधिकार है। अचेतन मन के नियंत्रण में आकुंचन-प्रकुंचन, निमेष-उन्मेष, श्वास-प्रश्वास, रक्त-संचार, ग्रहण-विसर्जन आदि अनेक स्वचालित समझी जाने वाली गतिविधियां चलती हैं। चेतन मन की शक्ति से ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां काम करती हैं। शरीर तभी तक जीवित है जब तक उसमें चेतना का अस्तित्व है। प्राण निकलते ही शरीर सड़ने और नष्ट होने लगता है। चेतना का केंद्र स्थान मस्तिष्क है। मन के रूप में ही हम चेतना का अस्तित्व देखते एवं क्रियाकलाप का अनुभव करते हैं। यह संस्थान मनोविकारों से पाप-ताप एवं कषाय-कल्मषों से विकृत होता है तो उसका प्रभाव शारीरिक आरोग्य, मानसिक संतुलन पर पड़ता है।

रीडर्स मेल

बेतुके मुद्दों पर राजनीति ठीक नहीं

पाकिस्तान और मुसलमान इस देश की राजनीति में पिछले दस पंद्रह वर्षों के दौरान काफी अहम मुद्दे बन कर उभरे हैं। हमें कहना नहीं चाहिए मगर एक खास विचारधारा के लिए ये 'दो शब्द' उनकी रोजी-रोटी का जरिया बन गए हैं। अगर इन दोनों शब्दों को इस देश में प्रतिबंधित कर दिया जाए तो यह निश्चित हो जाएगा कि कुछ लोगों की दुकानदारी चौपट हो जाएगी जो सिर्फ 'मुसलमान' और 'पाकिस्तान' का नाम लेकर चल रहा है। आखिर, इन दोनों शब्दों में ऐसा क्या है कि इनके चलते हमारे देश में दर्जनों युवाओं को 'राष्ट्रद्रोह' का मुकदमा झेलते हुए महीनों नहीं, बल्कि वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। मगर जब झारखंड के चास में सूचना के अधिकार कार्यालय में उर्दू अनुवादक और कार्यवाहक क्लर्क मोहम्मद शमीमुद्दीन को एक व्यक्ति, जिसका नाम हरिनंदन सिंह है, ने गाली देते हुए 'पाकिस्तानी' एवं 'मिया तियां' कह कर उलाहना दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस केस को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद तो अब कोई भी किसी को पाकिस्तानी और मिया कह कर उसका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि अदालत और कानून उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

साफ-सफाई की सिविक सेंस जरूरी

हमारी संस्कृति में स्वच्छता का विशेष महत्त्व है। आम तौर पर हमारी साफ-सफाई अपने घरों तक ही सीमित रहती है। घरों के बाहर की साफ-सफाई पर हम ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ गंदगी फैलाने में अपना योगदान देते हैं। पारिवारिक और सामाजिक उत्सव के दौरान सड़कों पर कचरे का अंबार लग जाता है। कहना गलत न होगा कि आमजन में सिविक सेंस की कमी है, और इसी के चलते वह अपने सामाजिक दायित्व की अनदेखी करता है। नतीजन, चारों तरफ गंदगी फैलती है, और गंदगी में बीमारियां फैलती हैं। स्वच्छता के प्रसार से शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी आई है। कचरा निष्पादन की ठोस व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि सभी शहरों में कचरे का पहाड़ देखने को मिलता है। पॉलिथीन का बढ़ता इस्तेमाल कचरे को बढ़ावा दे रहा है। हमें पॉलिथीन का विकल्प अपनाना चाहिए। स्वच्छता को हमें अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।

हिमांशु शेखर, गया

नियमन के साथ नियंत्रण भी हो

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रणवीर इलाहाबादिया के शो को भारतीय संस्कृति की सीमा लांघना, सोशल मीडिया की प्रवृत्ति को गलत दिशा में जाने तथा कांग्रेस सांसद की कविता में इंसाफ और इश्क के भाव बताने के बावजूद इन पर सियासत के मद्देनजर कार्रवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना तथा सेंसरशिप और नॉर्म्स के बीच अंतर भी स्पष्ट नहीं कर रही है। जरूरत है कि राजनैतिक शैक्षणिक, साहित्यिक, सामाजिक और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अश्लील और फूहड़ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण के साथ सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए सशक्त नियामक संस्था गठित की जाए करे या सरकार गाइडलाइंस तय करे ताकि अभिव्यक्ति की आजादी के हो रहे दुरुपयोग पर नकेल कसी जा सके। मान कर चला जाए कि बिना गाइडलाइंस के यह समस्या गंभीर से गंभीरतर होती जाएगी। नियमन के साथ नियंत्रण जरूरी है।

बी एल शर्मा, 'अकिंचन', उज्जैन
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 200
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

सबसे ऊपर देशहित

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में हुई चूक कोई सामान्य घटना नहीं है और इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। लंदन में किसी अलगाववादी का भारतीय विदेश मंत्री के इतने करीब पहुंच जाना चिंताजनक है और यह ब्रिटिश पुलिस की लापरवाही है। भारत विरोधी अलगाववादी ने सबके सामने तिरंगे का भी अपमान किया है। ब्रिटिश पुलिस को सचेत रहना चाहिए था कि एस जयशंकर के पास कोई भी अवांछित व्यक्ति न पहुंच पाए। यह अपने आप में गंभीर बात है कि ब्रिटिश पुलिस ने अलगाववादियों को अपने झंडे के साथ बैठक स्थल के पास ही प्रदर्शन करने दिया। क्या भारत अपनी सुरक्षा के प्रति कुछ ज्यादा ही उदारवादी रवैया अपना रहा है? अगर ऐसा किसी विदेश मंत्री के साथ भारत में होता, तो क्या प्रतिक्रिया होती? क्या भारत अपने किसी मेहमान की यात्रा के दौरान उसके खिलाफ प्रदर्शन की मंजूरी देता है? क्या ब्रिटेन यह नहीं जानता कि भारत में यह अलगाववाद किस स्तर पर पहुंच गया था और किन कुर्बानियों के बाद भारत में अमन-चैन बहाल है?

यह बात छिपी हुई नहीं है कि ऐसे अलगाववादियों के चलते ही भारत और कनाडा के बीच तनाव है और ब्रिटेन भी इस तनाव को बढ़ाने से रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर रहा है। यदि ब्रिटिश सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी सचेत रहते, तो वे भारतीय विदेश मंत्री के सामने इस प्रदर्शन को रोक सकते थे। क्या ब्रिटिश अधिकारियों को यह पता नहीं है कि ऐसे अलगाववादी आंदोलन को किस आतंकवाद समर्थक देश से मदद मिल रही है? यहां दुखद रूप से यह करने की जरूरत आन पड़ती है कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के बंटवारे का रास्ता तैयार किया था? आज यह वाक्य भी अशोभनीय और आपत्तिजनक लगता है कि भारत के बंटवारे को हवा देने की साजिश आज भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है! बेशक, ब्रिटिश शासन-प्रशासन ने अपने कूटनीतिक दायित्व का पालन नहीं किया है। ऐसे में, भारत की नाराजगी बिल्कुल जायज है।

भारत को ज्यादा सचेत और मुखर होना पड़ेगा। भारत की भलमनसाहत गलत नहीं है, पर इसके दुरुपयोग की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए।

वैसे, आज दुनिया जिस मुकाम पर है, उसमें भारत को ज्यादा सचेत और मुखर होना पड़ेगा। भारत की भलमनसाहत गलत नहीं है, पर इसके दुरुपयोग की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। भारत राष्ट्र और उसके प्रतीकों की सम्मान रक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। भारत को अपने आर्थिक और कूटनीतिक हितों के लिए ज्यादा सक्रिय व दृढ़ होना चाहिए। यह दृढ़ता विदेश मंत्री जयशंकर ने लंदन में दिखाई है। उन्होंने कश्मीर के समाधान के संबंध में दोटूक जवाब दिया है कि 'हम जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वह कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी है, जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब वापसी हो जाएगी, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा।' ऐसी ही दोटूक दृढ़ता से अलगाववाद के मुद्दे पर समर्थकों को संदेश दिया जा सकता है। बहरहाल, भारत को अपने आर्थिक हितों पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आर्थिक मजबूती देश की ताकत में इजाफा करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बिना उकसावे के भारत को बार-बार निशाने पर रख रहे हैं। ऐसे में, हमें जमीनी मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारत को यूरोप का साथ चाहिए, तो यूरोप के लिए भी भारत पहले की तुलना में महत्वपूर्ण हुआ है। भारत अगर रूस का पुराना मित्र है, तो उसे यूक्रेन की भी चिंता है। मतलब, भारत की राह आसान नहीं है और हम संतुलन साधकर चल रहे हैं।

शहर और नदी के बीच सुधरे संबंध

के के पाण्डेय | प्रोफेसर, अर्बन मैनेजमेंट, आईआईपी

राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी की सफाई की नई शुरुआत सराहनीय है। शहरों और नदियों को साफ-सुंदर बनाने के लिए योजनाओं को ठीक से लागू करने का समय आ गया है।

नगर और नदी का निकट संबंध है। नगर प्राचीन समय से ही नदियों के तट पर बसते रहे हैं। जल व्यक्ति और समाज की जीवन रेखा है और उसकी उपलब्धता लगातार बनी रहे, इसलिए उन्हीं स्थानों पर शहर बसाए जाते हैं, जहां जल की प्रचुरता होती है। हरिद्वार, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, दिल्ली, पटना, कोलकाता इत्यादि ज्यादातर शहर नदियों के किनारे ही विकसित हुए, पर समय के साथ नदियों में गंदगी आनी शुरू हुई। शहरों का जो ड्रेनेज सिस्टम था, वह धीरे-धीरे नदियों से जा मिला। शहरीकरण के साथ यह समस्या विकराल होती चली गई। जल का प्रदूषण उतना ही घातक है, जितना चावु प्रदूषण है। आज दिल्ली और यमुना प्रदूषण के केंद्र हैं। करीब 1,376 किलोमीटर लंबी यमुना का केवल 22 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है, पर यमुना का 76 प्रतिशत प्रदूषण अकेले दिल्ली से आता है।

जिस यमुना को दिल्ली में अब साफ किया जा रहा है, उसमें पिछले साल प्रदूषण तमाम सीमाओं को पार कर गया था। यहां फीकल कॉलीफार्म का अनुपात प्रति 100 एमएल पानी में 49 लाख तक पहुंच गया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, यह अधिकतम 2,500 यूनिट तक हो सकता है। दिल्ली में बहुत ज्यादा रूप से प्रदूषित यमुना को साफ करने के प्रयास पहले भी हुए हैं, पर पूरी कामयाबी का इंतजार है। दिल्ली के उप-राज्यपाल यमुना को इस साल साफ कर देना चाहते हैं। ध्यान रहे, अभी भी यमुना में लगभग 13 नाले गिरते हैं, जो बेहद प्रदूषित जल के साथ आते हैं। दिल्ली का लगभग आधा सीवेज अब भी शोधित नहीं होता है। मतलब, दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट को दुरुस्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही, दिल्ली में जो दूसरे उपाय हैं, उन्हें अपनाना चाहिए। जैसे सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था की जरूरत है। शहर का जो कचरा व सीवेज है, उसका निपटारा ऐसे होना चाहिए कि उसका आर्थिक व प्राकृतिक लाभ हो। समस्या को अवसर में बदलने की जरूरत है। यहां कचरे के पहाड़ खड़े हो गए हैं। यहां मुख्य समस्या है कि कचरे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। अपने स्रोत पर ही कचरे को अलग-अलग करना होगा, जब तक यह काम शहर में नहीं होगा, कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निष्पादन भी संभव नहीं होगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था में कचरे से धन जुटाया जा सकता है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

दिल्ली सहित भारत के ज्यादातर शहरों में सीवेज बड़ी समस्या है। सीवेज का संपूर्ण शोधन या निष्पादन जरूरी है। यहां समाधान के लिए विदेश के उदाहरण देखने के बजाय हमें अपने ही देश के उदाहरणों को मानक बनाकर आगे काम करना होगा। सीवेज का शोधन करके बेचा भी जा सकता है। जैसे नागपुर में सीवेज बेचकर 300 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आय होती है। बाकी शहरों को ऐसे करना चाहिए। सीवेज का अगर पर्याप्त शोधन हो, तो औद्योगिक उपक्रम ऐसे जल को आसानी से खरीदेंगे। ऐसे जल का इस्तेमाल उद्यानों या शहरों की सफाई के लिए हो सकेगा। यह काम निजी भागीदारी के साथ किया जा सकता है।

'नमामि गंगे' के तहत कई जल शोधन, संरक्षण मॉडल बनाए गए हैं। ध्यान रहे, यह शोधित पानी पारंपरिक पानी से सस्ता है। इस शोधन मॉडल को देश के दूसरे शहरों में अपनाया जा सकता है। एक बड़ा उपाय यह भी है कि बड़ी सोसायटी या मुहल्लों में सीवेज की स्थानीय स्तर पर ही निष्पादित कर दिया जाए। बेंगलूरु में ऐसी कई सोसायटी हैं, जो अपना सीवेज स्वयं शोधित करती हैं। इस जल का उपयोग सोसायटी में हरियाली या सौंदर्यीकरण के लिए किया जा रहा है।

एक उपाय यह भी है कि सीवेज या गंदे पानी को नदी में गिरने से रोका जाए। ऐसा गुजरात में साबरमती नदी के किनारे किया गया है। वहां रिवर फ्रंट तैयार हुआ है। अहमदाबाद की तरह ही इंदौर, पटना, लखनऊ, हैदराबाद में रिवर फ्रंट विकसित किए जा रहे हैं। रिवर फ्रंट की वजह से नदी की सफाई में भी मदद मिलती है। पर्यटन को भी बल मिलता है। लोग अपने शहर के तालाब, झील या नदी किनारे बैठना-टहलना पसंद करते हैं। नदियों के तटों को ही नहीं, बल्कि तालाबों और जलाशयों के तटों को भी सुंदर और व्यवस्थित करना चाहिए। ऐसे सौंदर्यीकरण से जलाशयों की घटने या सिमटने से बचाया जा सकता है। इससे शहर की सुंदरता में भी चार चांद लग सकते हैं।

सीखने की बात है कि बेंगलूरु में सफाई से जुड़ा एक वॉकर्स एसोसिएशन है। झीलों पर टहलने जाने वालों का संगठन स्वयं सफाई का ध्यान रखता है। मतलब, जनभागीदारी रंग ला रही है। तमाम सामाजिक संगठनों, सिविल संस्थानों को सफाई के अभियान में भागीदार बनाकर शहरों का कायाकल्प किया जा सकता है। यह ज्ञान संस्कार में ढल जाना चाहिए कि सफाई हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है।

एक और चिंता की बात है, अनेक शहरों में जो प्राकृतिक जल निकासी है, उसके विपरीत नगरों का विकास हुआ है या हो रहा है। इसे परखने और सुधारने की जरूरत है। दिल्ली की ही बात करें, तो बारापुला, नजफगढ़, पूर्वी दिल्ली में तीन मुख्य नाले हैं, जिनसे सीवेज का सही समाधोजन नहीं किया गया है। इसलिए ये नाले अक्सर मुसीबत बन जाते हैं। बारिश के समय बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इसे रोकने के लिए एक व्यापक ड्रेनेज प्लान होना चाहिए।

नमामि गंगे के तहत जो अच्छे प्रयास हुए हैं, उनकी चर्चा भी जरूरी है। निर्मल धारा अविरल धारा का विशेष इस अभियान के केंद्र में है। नदियों का बहाव कहीं अवरुद्ध न हो, उनका जल स्वच्छ बना रहे। नमामि गंगे से तमाम शहरों को सीखना चाहिए। गंगा का कैचमेंट एरिया हमारे देश में 27 प्रतिशत भूमि और 47 प्रतिशत आबादी को कवर करता है। नमामि गंगे बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और इसमें कुछ सफलता मिली है, पर अभी बहुत काम बाकी है। कुल मिलाकर, हमारे देश में ही जल संरक्षण या जल शोधन के अनुभव काफी हैं, जिन्हें साझा करने का समय आ गया है।

15वीं वित्त आयोग ने जो सुझाव दिए थे, उन्हें पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है। शहर से जुड़े तमाम क्षेत्रों को मिलाकर सही नियोजन हो और उसी हिसाब से धन आवंटित हो। अब 16वां वित्त आयोग सिफारिश करने जा रहा है और हमें नई सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने यहां ज्ञान की कमी नहीं है, पर ज्ञान को पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है। तभी नदी किसी नगर की शोभा में और नगर किसी नदी की शोभा में चार चांद लगा पाएंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

उदार त्रि-भाषा फॉर्मूले से दूर हो जाएगा भाषायी भेदभाव

अनुराग बेहर | सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन

मैं भोपाल में पला-बढ़ा हूं। कई तरह की हिंदी और उर्दू से मेरा परिचय हुआ और सभी मुझे बेहद प्रिय थीं। अंग्रेजी माहौल के अनुकूल थी और मेरा स्कूल अंग्रेजी माध्यम वाला ही था। हालांकि, मेरी पहली भाषा न तो हिंदी थी और न अंग्रेजी, यह छत्तीसगढ़ी थी। मेरा परिवार चूंकि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ नामक छोटे से शहर से था, इसलिए हम घर में छत्तीसगढ़ी ही बोला करते। स्कूल की पढ़ाई पूरी करते-करते मैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी के कई रूपों को अपनी भाषा मानने लगा। बाद में, कॉलेज के लिए मैं तमिलनाडु में त्रिची चला गया और तमिल भाषा व संस्कृति में मेरी गहरी रुचि पैदा हुई। यहां मैंने तमिल समझना तो सीखा, लेकिन धाराप्रवाह बोल नहीं सका और अब मैं दशकों से कर्नाटक में रह रहा हूं, कन्नड़ की समृद्ध भाषायी और सांस्कृतिक विरासत के बीच।

बचपन में मैंने देखा और हैरान भी हुआ कि छत्तीसगढ़ में मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों में से कई हिंदी में ही बात करना पसंद करते थे, न कि छत्तीसगढ़ी में। बीतते समय के साथ मैंने जाना कि वह एक व्यापक सामाजिक परिघटना है। समझा यही जाता था कि कॉलेजों में आने-जाने, अभिजात वर्गों में उठने-बैठने या अदालत की भाषा हिंदी ही है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए या आगे बढ़ना चाहने लगे या यह दिखाने लगे कि हम पहले से ही दूसरों से आगे हैं, तो हमने अपनी सुंदर और मीठी भाषा छोड़कर दूसरी अपनाने लगे।

हम स्वयं (सभी नहीं, पर छत्तीसगढ़ के लोगों का एक बड़ा हिस्सा) पर खुद ही हिंदी थोप रहे थे। हिंदी के प्रति मेरे प्रेम के बावजूद मुझे यह अच्छा नहीं लगा। निस्संदेह, इस सामाजिक-सांस्कृतिक परिघटना की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य बात यह थी कि हिंदी को एक भाषा के रूप में महत्व दिया जा रहा था, जबकि छत्तीसगढ़ी को बोली के रूप में। हममें से कई लोगों ने इस पदानुक्रम को स्वीकार कर लिया था। न सिर्फ स्कूलों में हमारी शिक्षा की भाषा हिंदी थी, बल्कि छत्तीसगढ़ी को हम किनारे करने लगे थे, यहां तक कि बाद में उसके उपयोग को हतोत्साहित किया जाने लगा। जब 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना, तो इस रुख को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हिंदी भी सामाजिक बदलाव की तरह इसकी अपनी गति थी, जो आज भी बदस्तूर कायम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने छत्तीसगढ़ी और अन्य भाषाओं के हालात में महत्वपूर्ण बदलाव की रूपरेखा तैयार की है। इसके तीन उल्लेखनीय पहलू हैं। पहला, साक्षरता की शुरुआती भाषा मातृभाषा होनी चाहिए (गौर कीजिए, इसमें भाषा बनाम बोली के भेदभाव का मसला नहीं है), क्योंकि यह शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाती है। अगर यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत छोटे समुदाय द्वारा बोली जाती है, तो शिक्षा की भाषा बच्चे की अगली सबसे परिचित भाषा होनी चाहिए। यह सोच सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि पूरे देश में हर भाषा को बढ़ावा देगी।

नई नीति सभी मातृभाषा को आधिकारिक वैधता प्रदान करती है और किसी भी भाषा को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है।

दूसरा, यदि शिक्षा मातृभाषा में नहीं मिल पा रही, मतलब कितायें उस भाषा में उपलब्ध नहीं हैं, तो शिक्षक और स्कूल मातृभाषा में पढ़ाई-लिखाई के सेतु बनेंगे। यह पूर्व की सोच से अलग है, क्योंकि हमारे समय में छत्तीसगढ़ी के उपयोग पर दींडित किया जाता था। और तीसरा, बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी से जुड़ा यह जवाब है कि कैसे नई शिक्षा नीति ने 'त्रि-भाषा फॉर्मूला' को बदल दिया है। असल में, नई नीति सभी मातृभाषाओं को आधिकारिक वैधता प्रदान करती है और इसके तहत किसी भी भाषा को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है। वह तथाकथित 'हिंदीभाषी राज्यों' में तीसरी भाषा पढ़ाने की चुनौती का भी समाधान है। मसलन, छत्तीसगढ़ में ही मातृभाषा होने के कारण पठन-पाठन की पहली भाषा छत्तीसगढ़ी होगी, जिसके बाद हिंदी और अंग्रेजी को दूसरी व तीसरी भाषा बनाया जा सकता है। तीसरी भाषा स्कूल अवसर नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि उनका जवाब होता था कि शिक्षक कहां से लाएंगे? अब, उनके पास हिंदी व अंग्रेजी शिक्षकों की शायद ही कमी होगी। यही तर्क का देश के बड़े हिस्से में भी काम करेगा। हां, हमें देखना होगा कि 'हिंदीभाषी राज्य' इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? यदि वे इसका बेहतर उपयोग कर सके, तो यह नीति न सिर्फ हमारी भाषायी विरासत को आगे बढ़ाएगी, बल्कि शिक्षा में सुधार लाएगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले 07 मार्च, 1950

उद्योगपति और सरकार

अखिल भारतीय निर्माता संघ भारतीय उद्योगपतियों की संस्था है। इसलिए उसके दसवें वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद से डा. अलगप्पा चेट्टियार ने जो भाषण दिया है, वह सरकार के लिए विचारणीय होना चाहिए। जहां तक देश का उत्पादन बढ़ाने का सवाल है, सरकार और उद्योगपतियों के दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है। दोनों लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन वृद्धि को अनिवार्य रूप से आवश्यक मानते हैं। जब उद्देश्य समान है तो कोई कारण नहीं कि उद्योगपतियों और सरकार के बीच गहरा सहयोग न हो। किन्तु उत्पादन बढ़ाने में केवल सरकार और उद्योगपतियों के सहयोग से काम न चलेगा, बल्कि मजदूरों का सहयोग भी अपेक्षित होगा। भारत सरकार के उद्योग मंत्री डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात की उचित ही शिकायत की कि निर्माता संघ के सभापति ने मजदूरों का कोई उल्लेख नहीं किया। उद्योगों के विकास और सुसंचालन में पूंजी का जितना महत्व है, उससे कम महत्व श्रम का नहीं है। देश जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसमें भारतीय मजदूरों ने केवल वर्गीय हितों को ही ध्यान में नहीं रखा, बल्कि राष्ट्रीय हितों को भी उचित महत्व दिया है और इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

डा. अलगप्पा ने जरा कटु शब्दों में सरकार की शिकायत की है। उनका कहना है कि सरकार जल्दी तक उद्योगों का तालल्लुक है, अभी तक न उद्देश्य के संबंध में और न ही नीति और उपायों के संबंध में सुसंगत विचार बना पाई है। इस क्षेत्र में असंगत काम भी किये जा रहे हैं। कठिनाइयों की गुरुता को पूरी तरह अनुभव नहीं किया जाता और देश की विभिन्न आर्थिक और औद्योगिक समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किये जा रहे हैं। इस संबंध में सारा दोष सरकार के मत्थे थोपना अन्याय ही होगा। जिन लोगों ने सरकार की बागडोर अपने हाथों में संभाली है, उनके सामने भूतकाल में समाज-रचना के कुछ आदर्श रहे हैं। उन्होंने देशवासियों के सामने कुछ वादे भी किये हैं। उनकी यह इच्छा हो सकती है कि जहां तक संभव हो, उन वादों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जावे। किन्तु उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि विद्यमान परिस्थितियों में कौन सी वस्तु व्यावहारिक होगी।

मनसा वाचा कर्मणा

झूठ का भोलापन

अविश्वास होते हुए भी यह न समझ पाना कि मन में विश्वास नहीं है, दरअसल अज्ञानता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपमें अविश्वास है, तब आप अविश्वासी नहीं हैं, क्योंकि आपको यह आभास है कि समझ के परे भी कुछ है। वास्तव में, आप कभी नहीं जान सकते कि आप अविश्वासी हैं या नहीं। एक अविश्वासी व्यक्ति अपनी ही सोच में फंसा होता है, उसके लिए किसी प्रकार की संभावना की कोई जगह नहीं। परंतु यह सृष्टि संभावनाओं से भरी हुई है। जैसे-जैसे व्यक्ति को इसकी समझ होती है, उसका अविश्वास मिटने लगता है।

एक सच्चा वैज्ञानिक अविश्वासी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से सभी संभावनाओं के द्वार बंद हो जाते हैं; फिर वह सृष्टि के रहस्यों की खोज कैसे कर पाएगा? अविश्वास है, मैं सब कुछ जानता हूं का भाव। ऐसी सोच बिल्कुल अवैज्ञानिक है। समझ बढ़ाने के दो साधन हैं- अनुभव और अनुमान; ज्ञान से अविश्वास दूर होता है। याद रखें, हर एक मनुष्य के अंतरतम में विश्वास और प्रेम है। जिसे आप अविश्वास समझते हैं, वह एक हलकी सी परत के समान है। यदि आप निश्चय कर लेते हैं कि अमुक अविश्वासी है, तो आप उसके अविश्वास को और पक्का करते हैं। अविश्वासी व्यक्ति के साथ तर्क मत करो, क्योंकि तर्क करने से उसका अविश्वास और भी गहरा होता है। स्वतंत्रता खोने का भय प्रतिरोध लाता है और अविश्वास भी बढ़ता है। आपके मौन और सच्ची मुस्कान से बढ़कर और कुछ भी नहीं, जो उसके अविश्वास को मिटा सके। मौन का अर्थ यह नहीं है कि अपने होठों को बंद रखें; मौन आपकी चेतना का गुण है। बच्चों में अविश्वास नहीं होता। अविश्वास केवल उनमें होता है, जो सीमित दायरों में रहते हैं। बच्चे तो अपनी कल्पनाओं की असीम दुनिया में जीते हैं, अनेक संभावनाओं से परिपूर्ण दुनिया, भोलेपन, आनंद, सौंदर्य और प्रेम से भरी दुनिया।

एक प्रिय व्यक्ति, जिस पर आपको विश्वास है, यदि आपसे कुछ झूठ बोलता है और ऐसा करते हुए वह पकड़ा जाता है, तब आपको क्या महसूस होता है- दुख, गुस्सा, आक्रोश, निराशा, दया, धोखा, मानहानि, अपेक्षा,

एक सच्चा वैज्ञानिक अविश्वासी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से सभी संभावनाओं के द्वार बंद हो जाते हैं; फिर वह सृष्टि के रहस्यों की खोज कैसे कर पाएगा?

आघात या ज़ैप? कुछ ही दिनों पहले किसी ने मुझसे झूठ कहा। मुझे प्रसन्नता हुई और उसके प्रति अधिक प्रेम का अनुभव हुआ, क्योंकि वह ठीक से झूठ बोल नहीं पाया। यदि वह सफाई से झूठ बोलता, तो पकड़ा ही नहीं जाता। यदि पकड़ा न जाता, तो कैसे पता चलता?

इसीलिए, आप असली झूठे व्यक्ति को कभी नहीं पकड़ सकते। जिसे आप झूठा समझते हैं, वह असल में झूठा नहीं है, वह तो भोला है। तो जब कोई आपसे झूठ कुछ कहे, तो उसे केवल आप दुखी या निराश न हों- बस, उसके प्रति दया और प्रेम महसूस करें।

श्री श्री रविशंकर

इमैनुएल मैक्रों | फ्रांसीसी राष्ट्रपति

फ्रांस और यूरोप के लिए रूस एक खतरा बन गया है। यूरोप की सुरक्षा चिंता अब वास्तविकता है। फ्रांस एक ही मार्ग का पालन करेगा, और वह मार्ग है शांति व सुरक्षा की सदिच्छा और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का!

नायकों को अपमानित करने वाली बातें

सपा नेता द्वारा औरंगजेब का बखान अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्र के प्रेरणा-स्रोत छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज का इस तरह अपमान देश कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। अबू आजमी ने कहा था, औरंगजेब को क्रूर शासक मैं नहीं मानता। उसने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिर बनवाए। औरंगजेब के समय हिन्दुस्तान सोने की चिड़िया था। उन्हीं के शासनकाल को देखकर अंग्रेज भारत आए। वास्तव में, औरंगजेब एक ईमानदार पर्सेप्ट बादशाह था। हालांकि, अब वही नेताजी यह कह रहे हैं कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, फिर भी यदि किसी का दिल इससे दुखा है, तो वह माफी मांगते हैं। मगर औरंगजेब की महिमा गाकर उन्होंने न सिर्फ इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का प्रयास किया, बल्कि वीर मराठों के इतिहास का अपमान भी किया। सच्चाई क्या है? इतिहास की किताबें बताती हैं कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दीं और क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। निर्दोषों की हत्याएं और धार्मिक कट्टरता उसकी पहचान थी। तो, ऐसे क्रूर शासक का समर्थन करना राष्ट्रद्रोह ही माना जाएगा।

नवीन जैन, टिप्पणीकार

सपा नेता ने औरंगजेब जैसे क्रूर मुगल बादशाह की तारीफ ही नहीं की, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज का अपमान भी किया। शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं हैं, बल्कि एक मराठा गौरव और हिन्दुस्तान के गौरवशाली इतिहास के सर्वोच्च नायकों में से एक हैं। सवाल है कि छत्रपति संभाजी महाराज को, जिसने 40 दिनों तक बंधक बनाकर मारा, वह भला उत्तम प्रशासक कैसे हो सकता है? असल में, इन नेता जी को लगा होगा कि कुछ भी बोल देंगे और विक्टिम कार्ड खेलकर बच निकलेंगे। इसीलिए अब वह माफी तक मांगने की बात कहने लगे हैं। अखिलेश यादव आज इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उनका समर्थक वर्ग ही सबसे ज्यादा असहिष्णु और कट्टर है, जो किताब की व्याख्या तक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूर्व शर्मा प्रकरण इसका ज्वलंत उदाहरण है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप देश का खाएं और देश के नायकों का अपमान भी करें। सपा नेता ने माफी की बात कही है, लेकिन जब तक सार्वजनिक तौर पर शिवाजी महाराज की सर्वस्वता को वह स्वीकार नहीं करते और औरंगजेब को दुत्कारते नहीं, तब तक उनकी माफी का कोई मतलब नहीं। वह वाकई शर्मिंदा हैं, तो अपनी करनी से इसे साबित करें, अन्यथा उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग सही है।

गुड्डू खेतान, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
औरंगजेब विवाद

हर बात पर विवाद पैदा करना उचित नहीं

विवादों का दूसरा नाम भारत कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई न कोई नेता ऐसा बयान देता ही है कि उस पर विवाद पैदा हो जाए। क्रूर, निर्दयी, अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब पर बहस इसी कड़ी का हिस्सा है, जबकि ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़े जाने से देश व जनता का कोई भला नहीं होने वाला। नफा-नुकसान जो भी होता है, वह नेताओं व राजनीतिक दलों को होता है। आज जब देश को मजबूत व प्रगतिशील बनाने की दरकार है, तब हम ऐसे विवादों में उलझे हुए हैं, जो देश को पीछे धकेल रहे हैं। आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले युग में इनका कोई महत्व व वजूद नहीं है। आज शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति पर कोई बात नहीं कर रहा है। शायद सभी राजनीतिक दल मिली-जुली कबड्डी खेल रहे हैं कि कब्रें खोदो, गड़े मुर्दे उखाड़ो, असल मुद्दों से देश व जनता को दूर रखो और भ्रम का माहौल पैदा करो। वह तो सरासर देश व यहां की जनता के साथ नाइंसाफी है और इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। अच्छा यही होगा कि ऐसे बेतुके विवादों के बजाय विकास के जरूरी मुद्दों पर बात की जाए। तभी देश आगे बढ़ सकता है।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने औरंगजेब की प्रशंसा में दो शब्द क्या बोल दिए, उनके बयान पर विवाद बढ़ गया है। हालांकि, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं और माफी भी मांग ली है, लेकिन अपने देश में नफरत और झूठ के शोर में सच को दबाने का खेल बहुत पुराना है। सच यह भी है कि गांधीजी ने 1921 में ओड़िशा के एक कार्यक्रम में कहा था, अंग्रेजों से पहले का समय गुलामी का समय नहीं था। मुगल शासन में हमें एक तरह का स्वराज्य प्राप्त था। अकबर के समय में प्रताप का पैदा होना संभव था और औरंगजेब के समय में शिवाजी फले-फूल सकते थे। मगर 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन ने क्या एक भी प्रताप और शिवाजी को जन्म दिया? कुछ सामंती देशी राजा जरूर हैं, लेकिन सब के सब अंग्रेज कारिंदे के सामने घुटने टेकते हैं और दास्तां सबकी कहते हैं। इसी तरह, 1931 में उन्होंने कहा था, अंग्रेजों के आने से पहले के इतिहास को आप देखें। उनमें आपको हिंदू-मुस्लिम दंगों के आज से ज्यादा उदाहरण नहीं मिलेंगे, औरंगजेब के शासन-काल में हमें दंगों का कोई हवाला नहीं मिलता। साफ है, कई उदाहरण हैं, जो सच्चाई बयां करते हैं, लेकिन इसे मानेगा कौन? पढ़ेगा कौन? जब सभी मुस्लिम शासकों को आक्रांता बताया जाने लगे, तब गांधी की सुनेगा कौन?

वसीम अकरम त्यागी, टिप्पणीकार

अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 7 मार्च 2025

दुष्प्रचार सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने वास्तविकता को अपने ढंग से पेश करना भी है। -विल हर्ड

वैश्विक रियल एस्टेट परामर्श कंपनी नाइटफ्रैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों व करोड़पतियों की संख्या में वृद्धि के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वे यकीनन देश की आर्थिक प्रगति और सकारात्मक व्यापारिक माहौल को दर्शाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है।

समृद्धि का दूसरा पहलू

वैश्विक रियल एस्टेट परामर्श कंपनी नाइटफ्रैंक की 2025 की रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों व करोड़पतियों की संख्या को लेकर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, वे निश्चित तौर पर देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और सकारात्मक व्यापारिक माहौल को दर्शाते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये कुछ गंभीर चिंताओं की ओर इशारा भी करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में एक करोड़ डॉलर से अधिक संपत्ति वाले भारतीयों की संख्या में इसके पिछले वर्ष की तुलना में छह फीसदी का इजाफा हुआ है और अब करोड़पतियों की संख्या के मामले में भारत सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान से ही पीछे रह गया है। देश में बढ़ते आर्थिक अवसरों और विकसित होते बाजार का ही नतीजा है कि रिपोर्ट में 2028 तक भारत में अमीरों की संख्या में बड़ा उछाल आने की भी बात कही गई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में फिलहाल जो 191 अरबपति हैं, उनमें से 26 तो पिछले वर्ष ही इस श्रेणी में शामिल हुए हैं। 2019 में यह संख्या महज सात थी। दरअसल, तकनीकी कंपनियों के इस युग ने एशिया के आर्थिक परिदृश्य को तो बदला ही है, स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच व स्टार्टअप संस्कृति ने भारत में भी प्रभावशाली प्रगति की राह खोली है और देश को फ्रांस, ब्राजील और रूस जैसी दूसरी बड़ी आर्थिक शक्तियों के साथ खड़ा कर दिया है। इस आर्थिक उछाल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। नए व्यवसायों और तकनीकी नवाचारों के चलते समाज में सकारात्मक बदलाव भी आ रहे हैं। समृद्धों की बढ़ती संख्या को उन सरकारी योजनाओं की कामयाबी का भी प्रतीक माना जा सकता है, जो स्वरोजगार को प्रोत्साहन देती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कुछ ही समय पहले जारी की गई एक अन्य वैश्विक रिपोर्ट का कहना है कि भारत में एक फीसदी सबसे अमीर लोगों के पास देश

की कुल संपत्ति का 40 फीसदी से अधिक हिस्सा है, जबकि नीचे से 50 फीसदी आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल तीन फीसदी हिस्सा ही है। जाहिर है कि देश की बड़ी आबादी अब भी न्यूनतम वेतन और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। यह स्थिति संपत्ति के निर्माण के साथ उसके न्यायसंगत वितरण पर ध्यान देने की जरूरत को भी इंगित करती है। अरबपतियों व करोड़पतियों की बढ़ती संख्या यकीनन इस बात का संकेत है कि भारत आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बन रहा है। लेकिन यह उपलब्धि तभी सार्थक होगी, जब आर्थिक तरक्की का फायदा सबको बराबर मिले।

जीवन धारा

महादेवी वर्मा

ईश्वर तो सर्वत्र हैं। उसे हमारे सत्य और असत्य से कोई मतलब नहीं। वह तो जानता ही है कि क्या सत्य है, क्या नहीं। वास्तव में समाज में एक-दूसरे के व्यवहार में सत्य की आवश्यकता है।

छलें नहीं, दुराव और कपट न करें

नैतिक और मानवीय मूल्यों के बीच में कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। विकास जीवन का धर्म है व विकास के क्रम में मनुष्य ने कुछ जीवन-मूल्यों का आविष्कार किया है। वे सिद्धांत में नैतिक मूल्य कहे जाते हैं और व्यवहार में हम उन्हें मानवीय मूल्य कहते हैं। जीवन मूल्य को बनाने में पीढ़ियां लगी हैं। व्यक्ति का अनुभव नहीं, समष्टि का अनुभव है। इसमें जैसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, इस सत्य का काम मनुष्य को मनुष्यता के निकट लाना है; संसार में सामंजस्य लाना और बहुत से दोषों से मनुष्य को मुक्त रखना है। ईश्वर तो सर्वत्र है। उसे हमारे सत्य और असत्य से कोई मतलब नहीं। वह तो जानता ही है कि क्या सत्य है, क्या नहीं।

वास्तव में समाज में एक-दूसरे के व्यवहार में सत्य की आवश्यकता है। हम छलें नहीं, हम दुराव न करें, हम कपट न करें। इससे समाज की स्थिति बनेगी। इसी तरह हमारे धर्म के मूल्य भी हैं और नैतिक मूल्य भी हैं। ईश्वर को हम दंड नहीं दे सकते। ईश्वर को क्षमा भी क्या हमारी चाहिए? मनुष्य को चाहिए। धी-बुद्धि-का विकास, विद्या का विकास, ये सत्कर्म जिन्हें हम धर्म कहते हैं, वे मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्य भी हैं। दार्शनिक रूप से, सिद्धांत रूप से, मान्यता के रूप में ये नैतिक मूल्य हैं। जब ये नहीं रहेंगे, तो अनैतिक हो जाएंगे। अनैतिक मूल्य तो मानवीय मूल्य नहीं होते। ये दोनों हमें चाहिए। एक व्यवहार में चाहिए, एक धारणा में चाहिए। आप देखेंगे कि जो बुरा व्यक्ति है, जैसे चोर-वह भी विश्वास करता है उसका, जो चोरी नहीं करता; और आप देखेंगे कि डकैत जो है, वह अपने को डकैत नहीं कहना चाहता। वह नहीं मानता कि वह बुरा काम कर रहा है। इसी तरह जो बहुत असत्य बोलता है, वह सत्यवादी का विश्वास करता है। मन में कहीं किसी कोने में मान्यता है पति हमारा सम्मान है। हम मानते हैं कि ये जीवन के मूल्य वास्तव में समाज के लिए आवश्यक हैं। नई परिस्थिति हर युग में आती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, 'संभवामि युगे युगे।' हर युग में वही मूल्य रहते हैं, परंतु नए ढंग से उनकी परीक्षा होती है। वे मूल्य नहीं टूटते, जैसे अहिंसा नहीं टूटी है, सत्य नहीं टूटा है, कोई भी जीवन का क्षेत्र ऐसा नहीं है, जो जीवन को पूर्ण बनाता हो। आज हम चिंता करते हैं, क्योंकि हमारी पीछी मूल्यों में विश्वास नहीं करती। मूल्यों का विश्वास खो देना बहुत बड़ा खो देना है। इसके संबंध में जितनी हम चिंता करें, उतना ही हम विकास कर पाएंगे। आज चिंता हमें इस बात की नहीं है कि कुछ व्यक्ति असत्य बोलते हैं। हमें चिंता है कि आज सत्य का मूल्य नहीं हुआ, अवमूल्यन हो गया है। अब असत्य को ही जीवन का मूल्य मान लिया गया है। आज हमें एक नई नैतिकता चाहिए। ऐसी नैतिकता कि हम नए विज्ञान को संयोजित कर सकें, मनुष्य को कल्याण से मिला सकें। जब मनुष्य कल्याण से मिल जाएगा, तब वास्तव में हमारे मन का संकल्प भी मंगलमय हो जाएगा। तब नैतिक मूल्य तो हमारी आस्था में, विचार में रहेंगे; व्यवहार में हमारे मानवीय मूल्य रहेंगे; मनुष्य का मनुष्य के प्रति श्रद्धा-स्नेह-सौहार्द, परस्पर त्याग बलिदान हमारे आवश्यक गुण होंगे, बिना इसके मनुष्य जाति विकास नहीं करेगी।

मूल्यों को सहेजें

सूत्र

मूल्य परिवार में मिलते हैं, समाज में मिलते हैं, शिक्षा में मिलते हैं, आस्था में मिलते हैं। अनेक पीढ़ियों की धरोहर हैं, ये मूल्य। इसलिए इनको सहेजने और आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि मनुष्य का व्यक्तित्व जैसे बना है, ऐसे ही राष्ट्र का व्यक्तित्व बना है।

क्या यही पाकिस्तान का असली रंग है

धाराबाहिकों एवं यूट्यूब के जरिये पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने की रणनीति अपना रहा है। हालिया बांग्लादेशी संकट में उसके दुष्प्रचार का मुखौटा पूरी तरह उतर गया है। वह बिना किसी 'संकोच' या पश्चाताप के पीठ में छुरा घोंपता है, यही उसकी 'फितरत' है।

अमेरिकी दार्शनिक और समाज विज्ञानी एरिक हॉफ ने कहा है कि 'दुष्प्रचार लोगों को धोखा नहीं देता; यह केवल उन्हें खुद को धोखा देने में मदद करता है।' दुष्प्रचार (प्रोपेगैंडा), जिसे अब मनोवैज्ञानिक युद्ध कहा जाता है, आधुनिक युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। भूराजनीति में भी इसका इस्तेमाल होता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हिटलर और नाजी जर्मनी के प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स के नेतृत्व में जर्मनों ने फिल्मों, पोस्टरों, भाषणों, बैनरों और कई अन्य साधनों के माध्यम से जर्मनों के दिमागों को प्रभावित किया। अक्सर जोसेफ गोएबल्स की प्रसिद्ध पंक्तियों को उद्धृत किया जाता है कि 'यदि आप कोई बड़ा झूठ बोलते हैं और उसे बार-बार दोहराते हैं, तो लोग अंततः उस पर विश्वास कर ही लेंगे', क्योंकि लोग भोले होते हैं।

वीरेंदर कपूर
लेखक एवं शिक्षाविद

इसमें समय लगता है और यह झूठ जितना सूक्ष्म होगा, उतना ही बेहतर होगा। इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कहानियों के माध्यम से धीरे-धीरे झूठ के जहर को घोला जाता है। अपने दुश्मन के खिलाफ दुष्प्रचार का सबसे शक्तिशाली तरीका है, एक खास तरीके से लोगों के मन में पूर्वाग्रह पैदा करना, ताकि अनुकूल जनमत का निर्माण किया जा सके। अमेरिकी लेखक एवं पत्रकार विलियम ब्लम ने कहा था, 'दुष्प्रचार लोकतंत्र के लिए वैसा ही है, जैसे हिंसा तानाशाही के लिए।' *डॉक्टर जिवागो* की कहानी के बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जब बोरिस पास्तरनाक ने 1956 में शीतयुद्ध के चरम दिनों में अपना उपन्यास *डॉक्टर जिवागो* पूरा किया, तो सोवियत अधिकारियों ने रूसी क्रांति के दौरान एक व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी पढ़ी और इसे प्रकाशित करने से इन्कार कर दिया। रूसी क्रांति रूस में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की अवधि थी, जो 1917 में शुरू हुई थी। अक्तूबर क्रांति पर लेखक के आलोचनात्मक रुख के कारण, *डॉक्टर जिवागो* को सोवियत संघ में प्रकाशित करने से मना कर दिया गया था। इतालवी प्रकाशक के कहने पर, पांडुलिपि को मिलान में

तस्करी करके लाया गया और 1957 में प्रकाशित किया गया।

पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने जल्द ही प्रचार के एक उपकरण के रूप में इसकी क्षमता को पहचान लिया। अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने महसूस किया कि उपन्यास सोवियत सरकार को शर्मिंदा करने और रूसी नागरिकों को भड़काने का अवसर प्रस्तुत करता है। सीआईए का विचार था कि रूसियों के सामने साम्यवाद को खुरे ढंग से दर्शाया जाए और उन्हें बताया जाए कि पश्चिम का पूंजीवाद बेहतर है। सीआईए द्वारा पुस्तक प्रकाशन के बाद 1965 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म *डॉक्टर जिवागो* आई। इस मुद्दे को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन ने न केवल जोर दिया था, बल्कि उसका मौन समर्थन भी था।

भारतीय पुरुष और महिलाएं, विशेषकर महिलाएं पाकिस्तानी नाटकों को बहुत पसंद करती हैं, जो अच्छी तरह से निर्देशित होते हैं और उनकी संस्कृति को सकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। चाहे वे आंतरिक रूप से कितने भी टूटे हुए क्यों न हों, आम लोगों को सभ्य दिखाते हैं। वास्तव में लाहौरी पंजाबी और उर्दू लहजे के मिश्रण के साथ वे सभ्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। खासकर उत्तर भारतीय दर्शक महरी सांस लेकर कहते हैं, 'ये तो अच्छे लोग हैं-बिल्कुल हमारे जैसे'। उनके अभिनेता शानदार हैं और कहानी पारिवारिक जीवन से जुड़ी होती है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे आपके कट्टर दुश्मन हैं और कभी भी बर्बर हो सकते हैं। अगर आपको कोई यह बात कहे भी, तो आप कहते हैं 'भाई ऐसा हो ही नहीं सकता'। आप सीमा पार हो रही हर घटना, आतंकवाद और हत्याओं के लिए राजनेताओं और पाकिस्तानी सेना को दोषी ठहराते हुए कहते हैं-लोग सब ठीक हैं। जाहिर है, वे बहुत सूक्ष्मता से भारतीय मानस को प्रभावित करने में सफल रहे हैं।

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में यूट्यूब का भी चतुराई से इस्तेमाल किया। शुरू में इन यूट्यूबरों ने भारत की बेबाकी से प्रशंसा करके भारतीय दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने भारत की नीतियों और आर्थिक विकास की प्रशंसा की और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की भी प्रशंसा की। उनके कथनों में विभाजन पर खेद की भावनाएं प्रतिध्वनित हुईं, और उन्होंने भारत के आर्थिक उदारीकरण को सराहनीय कदम बताया। इस रणनीतिक दृष्टिकोण के चलते लाखों भारतीय उनके सब्सक्राइबर बने। शिक्षित भारतीयों ने भी पाकिस्तानी युवाओं के ऐसे दुर्लभ समझदार विचारों और विश्लेषणों की सराहना की। इसने दुनिया को यह भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है।

पहले तो पाकिस्तान के सुर में अचानक आए इस बदलाव को देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वह हमेशा से भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। इन यूट्यूबरों को भारतीयों ने खुले दिल से अपनाया, जो उनके वीडियो पर भारतीय व्यूज और कमेंट्स की अधिकता से स्पष्ट है। लेकिन समय के साथ उनका मुखौटा उतरने लगा। भू-राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने वाले चैनल धीरे-धीरे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने लगे। पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन यूट्यूबरों ने फिर से भारत के साथ व्यापार शुरू करने की वकालत की, जिसे उनके प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के विरोध में रोक दिया था। उन्होंने इमरान खान के फैसले की खुलेआम आलोचना की और इसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए मूर्खतापूर्ण करार दिया। चाल देखिए! हम सभी इससे हैरान थे कि देखिए, अब उन्हें इसका पछतावा है। लेकिन हालिया बांग्लादेशी संकट में उसके दुष्प्रचार का मुखौटा पूरी तरह उतर गया है। वह हर मंच से भारत को कोसता रहता है। बांग्लादेश उस पाकिस्तान का स्थागत करने और हाथ मिलाने तक के लिए तैयार है, जिससे सिर्फ 50 साल पहले उसके लाखों लोगों का नरसंहार किया था। यही पाकिस्तान का असली रंग है। उसके धाराबाहिकों पर मत जाइए। यह बगैर 'संकोच' के पीठ में छुरा घोंपता है, यही उसकी 'फितरत' है। मुझे यकीन है, बहुत से भारतीयों को यह बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो कहा जाना है, वह कहा ही जाना चाहिए।

edit@amarujala.com

दूसरा पहलू

2001 के भूकंप में तबाह हुए लोगों के जीवन को संवारने के लिए शुरू हुई खमीर संस्था दस्तकारों की उम्मीद बन गई है।

गुम होता हथकरघा और उम्मीद की खमीर

गुजरात के कच्छ जिले के मध्य में भुज से करीब 15 किलोमीटर दूर बसे कुकमा गांव में खमीर नामक संस्था का परिसर, जिसमें पेड़ों की हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट, चरखों और हथकरघों की खटपट के बीच काम करते बुनकर और शिल्पियों को देखकर मन सहसा ही उत्साहित हो उठता है। संस्था के पूर्व निदेशक पतित लेहरू बताते हैं कि वर्ष 2001 में आए भूकंप ने कच्छ में कई लोगों की जान ले ली थी और भुज शहर को तबाह कर दिया था। परंपरागत कारीगरों को बहुत नुकसान हुआ था।

बाबा मायाराम

इसके बाद कच्छ में बुनकरों की संख्या में तेजी से गिरावट आई थी। लोगों का जीवन स्तर काफी प्रभावित हुआ था। पुनर्वास के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने एक साझा मंच बनाने की जरूरत महसूस की, जो हस्तशिल्प से जुड़े लोगों का समर्थन और प्रचार कर सके। इसके बाद खमीर संस्था के गठन की सोच बनी और 2005 में इसकी स्थापना हुई। खमीर का मतलब कच्छ की स्थानीय भाषा में 'आंतरिक गौरव' होता है। वर्ष 2012 में, खमीर ने एक और पहल शुरू की, जिसने कच्छ की स्थानीय फसल काला कपास के उत्पादन को बढ़ावा दिया, जो कि पूरी तरह से जैविक है और इसकी उत्पादन प्रक्रिया पूरी तरह से स्थानिक है। खमीर ने कच्छ की छपाई और रंगाई पर भी काम किया। संस्था ने कारीगरों के योगदान से अजरखपुर में एक अनूठा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र विकसित किया है। इस उपचार संयंत्र में विभिन्न रंगाई और छपाई इकाइयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डाई जल अपशिष्ट को पुनर्चक्रित किया जाता है।

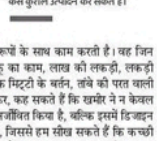

खमीर ने बुनकरों की पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने के साथ डिजाइन व मार्केटिंग जैसे आधुनिक ज्ञान को भी जोड़ा है, जिससे इस सीख सकते हैं कि पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक ज्ञान भी जोड़कर कैसे कुशल उत्पादन कर सकते हैं।

इसके अलावा, खमीर कच्छ क्षेत्र में शिल्प रूपों के साथ काम करती है। वह जिन शिल्प रूपों के साथ काम करती है, उनमें चाकू का काम, लाख की लकड़ी, लकड़ी की नक्काशी, ब्लॉक प्रिंटिंग, बांधनी और बाटिक मिट्टी के बर्तन, ताँबे की परत वाली घंटियां और अन्य शिल्प शामिल हैं। कुल मिलाकर, कह सकते हैं कि खमीर ने न केवल कच्छ की बुनकरी की पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित किया है, बल्कि इसमें डिजाइन व मार्केटिंग जैसे आधुनिक ज्ञान को भी जोड़ा है, जिससे हम सीख सकते हैं कि कच्छी पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक ज्ञान भी जोड़कर हम कुशलता हासिल कर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भी बना सकते हैं। खमीर के साथ किसान, दस्तकार, हस्तशिल्पी, प्रशिक्षक, डिजाइनर, व्यापार के जानकार एवं प्रबंधक की अच्छी खासी टीम है। युवा महिला निदेशक काव्या सक्सेना इस टीम का नेतृत्व कर रही हैं।

आंकड़े

यूक्रेन को मदद

रूस से युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन को जिन देशों से सहायता पहुंचाई है, उनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अमेरिका की है।

अमेरिका	42.7%
यूरोपीय संघ	18.3%
जर्मनी	6.5%
ब्रिटेन	5.5%
जापान	3.9%
अन्य देश	23.1%

आंकड़े यूक्रेन को सहायता पहुंचाने के प्रतिज्ञान में | स्रोत : Kiel Institute

इटावा जिले के पुरैला नामक ग्राम में जन्मे संत मथुरादास महाराज अयोध्या में रहकर भगवान की भक्ति करते थे। वह एकांत में भगवान से मीठी-मीठी बातें करते थे।

श्याम सुंदर से मीठी-मीठी बातें

इटावा जिले के पुरैला नामक ग्राम में संत मथुरादास महाराज का जन्म हुआ था। बाल्यकाल से ही उनके अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो गई थी। माता-पिता उनका विवाह कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने माता-पिता समझाया कि यह सांसारिक बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं। उनकी तर्कपूर्ण बातें सुनकर परिजनों ने विवाह का विचार त्याग दिया, लेकिन उन्हें घर का कार्यभार सौंप दिया। मथुरादास जी ने कुछ समय तक तो घर का कुशलता से संचालन किया, लेकिन उनकी वृत्ति उसमें ज्यादा टिकी नहीं।

वह घर छोड़कर अयोध्या जाकर बड़ी छावनी के तत्कालीन स्वामी ईश्वरदास जी के शिष्य बन गए। वह भक्ति के साथ ही गरीब, वृद्ध और निराश्रय की सेवा करते थे। उनके सेवा कार्य से प्रसन्न होकर एक वृद्ध संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि भगवान राम तुम्हें दर्शन देंगे। महाराज जी ने प्रतिदिन सरयू में स्नान करने व संतों के चरणों की रज सिर पर लगाने के अपने प्रण को आजीवन निभाया। वह एकांत में मीठी-मीठी बातें करते थे। यह देख एक भक्त ने उत्सुकतावश पूछा, महाराज आप अकेले में किससे बातें करते हैं। महाराज ने इशारा कर कहा, 'देखो इन्हीं श्याम सुंदर से।' यह सुनते ही भक्त का शरीर कांप उठा और बिजली की चमक से आंखें चौंधिया गईं। महाराज जी का पूरा जीवन दीन-दुखियों और साधुसेवियों की सहायता में बीता तथा जानकी नवमी के दिन रामधुन गाते हुए उन्होंने अपना भौतिक चोला छोड़ा।

अंतर्वाणी संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 मार्च, 1950

नेपाल में भारतीय लोग बिना पासपोर्ट जा सकेंगे

नेपाल में भारतीयों का प्रवेश बिना पासपोर्ट के जा सकेंगे

भारत और नेपाल के बीच संधि हो रही है कि अब भारतीय नेपाल में बिना पासपोर्ट के आ-जा सकेंगे। पहले यह सुविधा भारतीयों को प्राप्त नहीं थी, जबकि नेपाली नागरिक बिना रोक-टोक आ-जा सकते थे।

सोशल मीडिया और डिजिटल उपनिवेशवाद

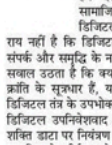

हैरानी है कि 140 करोड़ लोगों के इस देश में कोई भी ऐसा देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, जो इन विदेशी एप के सामने खड़ा हो सके।

मुकुल श्रीवास्तव — तकनीक

स्टैटिका के मुताबिक, भारत में 90 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है। देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताना-बाना तेजी से डिजिटल हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिजिटलीकरण हमारे लिए सुविधा, संपर्क और समृद्धि के नए रास्ते खोल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हम सचमुच इस डिजिटल क्रांति के सूत्रधार हैं, या बस किसी और के बनाए डिजिटल तंत्र के उपभोक्ता बनकर रह गए हैं? यह दौर डिजिटल उपनिवेशवाद का है, जहां किसी देश की शक्ति डाटा पर नियंत्रण से तय होती है।

दुनिया के शीर्ष 10 टेक प्लेटफॉर्म- गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन, एक्स आदि पर भारतीय उपभोक्ताओं की भारी संख्या है। लेकिन इनमें से एक भी कंपनी भारतीय नहीं है। हमारे लोगों का डाटा विदेशी कंपनियों के नियंत्रण में है, जो एक तरह के डिजिटल उपनिवेशवाद को जन्म दे रहा है। इन कंपनियों का नियंत्रण मुख्य रूप

से अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों के हाथों में है, जिससे भारत का डिजिटल भविष्य बाहरी ताकतियों की नीतियों और व्यावसायिक हितों पर निर्भर होता जा रहा है। ये कंपनियां न केवल हमारे डाटा का आर्थिक शोषण कर रही हैं, बल्कि हमारी चुनाव प्रणाली, न्यायिक फैसलों और समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण को भी प्रभावित कर रही हैं। हैरानी है कि 140 करोड़ लोगों के इस देश में कोई भी ऐसा देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, जो इन विदेशी एप के सामने खड़ा हो सके।

पिछले कुछ वर्षों में इन विदेशी प्लेटफॉर्म्स ने देश के सामने कई तरह की चुनौतियां पेश की हैं, जिनमें डाटा सुरक्षा, फेक न्यूज और पक्षपातपूर्ण प्रचार जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहां की चुनावी प्रक्रिया में भी इन कंपनियों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है। इंको की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते साल हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मेटा प्लेटफॉर्म्स पर चुनावी पेड प्रचार और तौबी विज्ञापनों के जरिये राजनीतिक पार्टियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे हैं। साल 2023 में यूरेस्को इप्सोस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक, देश में शहरी क्षेत्रों के 64 प्रतिशत लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गलत सूचनाओं और फेक न्यूज का प्राथमिक स्रोत माना। फेक न्यूज के प्रसार में खासकर फेसबुक, व्हाट्सएप और एक्स प्रमुख भूमिका निभाते नजर आए। फेसबुक की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में हुए दिल्ली दंगों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर 22 हजार से अधिक ऐसे पोस्ट्स और ग्रुप्स पाए गए, जिनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाई जा रही थी।

मुश्किल यह है कि ये विदेशी कंपनियां भारत में काम करने के बावजूद पूरी तरह से भारतीय कानून के अधीन नहीं हैं और अक्सर अपनी वैश्विक नीतियों का हवाला देकर बच निकलती हैं। दुखद है कि आर्थिक दृष्टि से भी ये देश को बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। उदाहरण के लिए, मेटा और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म भारत में विज्ञापन से अरबों डॉलर की कमाई करते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा हिस्सा विदेशों में चला जाता है। एक बड़ी चुनौती इन कंपनियों के क्लाउड स्टोरेज और डाटा सेंटर्स को लेकर भी है। भारत सरकार और कंपनियां बड़े पैमाने पर गूगल ड्राइव, अमेजन एडब्ल्यूएस, एजोर जैसे क्लाउड स्टोरेज पर निर्भर हैं, यानी भारत का संवेदनशील डाटा विदेशों में संग्रहित होता है, जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा है।

जुलाई, 2024 में माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड स्टोरेज में गड़बड़ी होने से पूरे देश का आईटी सिस्टम बारह घंटे के लिए ठप पड़ गया। अचानक आई एक तकनीकी खामी के कारण देश में डिजिटल बैंकिंग, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट्स, ऑनलाइन सेवाएं और कई अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां ठप पड़ गईं, जिससे न केवल रोजमर्रा की जिंदगी घंटों प्रभावित रही, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गहरा आघात पहुंचा। अब जरूरी है कि भारत भी अपना स्वदेशी सोशल मीडिया और डिजिटल इकोसिस्टम बनाए। हालांकि शेयरचैट और कू जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एक समय भारतीय बाजार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, मगर लोगों और सरकार के अपेक्षाकृत कम समर्थन के कारण इनका वैश्विक दिग्गजों से मुकाबला करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया।

तकनीकी नवाचारों के मामले में भारत की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधरी है। हाल ही में आई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2024 रैंकिंग में 133 देशों में भारत ने 39वां स्थान हासिल किया, जो देश की बढ़ती तकनीकी और डिजिटल क्षमता का प्रमाण है, हालांकि इसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। आधार, यूपीआई और कोविन जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स ने यह साबित किया है कि हम तकनीकी चुनौतियों को कैसे संभाल सकते हैं। यदि भारत अपना तकनीकी इकोसिस्टम विकसित करता है, तो यह डिजिटल उपनिवेशवाद का मुकाबला करने की दिशा में बड़ा कदम होगा।

दैनिक बढ़ता राजस्थान

सम्पादकीय

शहरों के लिए बजट की पाई-पाई का हो इस्तेमाल

इस साल बजट में हुए आवंटन पर चर्चा के दौर लगभग थम गए हैं। ऐसे में यह पड़ताल होनी चाहिए कि सरकार के तीनों स्तर और दूसरी संबंधित एजेंसियां कौन से उपाय करें, जिनसे भारत के शहरों के लिए आवंटित एक-एक पैसे का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। पिछले कुछ साल की तरह इस बार भी शहरी मंत्रालय के लिए आवंटन कुल बजट का लगभग 2 फीसदी रहा है। लेकिन शहरी उप-क्षेत्रों और कार्यक्रमों में इसका वितरण बदल गया है। शहरी आवास की हिस्सेदारी घटी है और नई योजनाओं की शुरुआत धीमी गति से हो रही है। उनके बजाय पिछली योजनाओं के तहत मकानों का निर्माण पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। परिवहन विशेषकर मेट्रो रेल और बुनियादी सेवा क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ा है क्योंकि ये योजनाएं पहले जैसी गति से चल रही हैं। स्मार्ट सिटी अभियान ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है मगर अर्बन चैलेंज फंड जैसे नए कार्यक्रम मकसद शहरों को नया रूप देना है। शहरी आवास से शुरू करें तो जिन तीन योजनाओं के लिए सब्सिडी दी गई है, वे हैं 2015 से चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) चरण 1, पीएमएवाई-यू चरण 2 और पिछले साल घोषित औद्योगिक आवासीय योजनाएं। शहरी आवास का तीन-चौथाई से अधिक बजट पीएमएवाई-यू के पहले चरण के तहत आवास निर्माण पर सब्सिडी देने के लिए है। इस चरण में 32 लाख आवास अभी बनने हैं, इसलिए नई आवासीय योजनाएं शुरू करने से पहले उनके निर्माण को प्राथमिकता देना समझदारी की बात है। इस बजट में बिल्कुल ऐसा ही किया गया है। जो मकान बनने हैं, वे ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों के लिए हैं, जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपये या उससे कम है। इन मकानों पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे परिवार का निर्माण पर आने वाला खर्च कम हो जाता है। इस सब्सिडी में 2015 से कोई बदलाव नहीं किया गया है मगर मकान बनाने का खर्च बढ़ गया है और लाभार्थियों को इसमें ज्यादा रकम लगानी पड़ रही है। इसलिए इन गरीब परिवारों को पहले की तुलना में अधिक धन की दरकार हो जाती है। उनके लिए किफायती आवास ऋण की उपलब्धता बढ़ाना इसके समाधान का एक तरीका है। पीएमएवाई-यू के पहले चरण पर हुए शोध में भी बताया गया है कि इस तरह का कर्ज नहीं मिलना ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए पीएमएवाई-यू चरण 1 के लाभार्थियों को पहले के मुकाबले अधिक आसानी से किफायती आवास ऋण उपलब्ध कराना जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के दूसरे चरण के लिए आवंटन केवल आवास ऋण के ब्याज पर सब्सिडी देने के मकसद से किया गया है। इससे परिवारों की मासिक किस्त कम हो जाती है। इसमें 70 फीसदी आवंटन ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग (सालाना आमदनी 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच) के लिए है। बाकी रकम मध्यम आय वर्ग (सालाना आमदनी 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक) के लिए है। सीएसईपी में किए गए शोध बताते हैं कि पीएमएवाई-यू के पहले चरण में ऐसी ही आवास ऋण सब्सिडी योजना के तहत केवल 21 फीसदी लाभार्थी ईडब्ल्यूएस वर्ग से थे। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस योजना के दूसरे चरण में लाभ पाने वाले ईडब्ल्यूएस परिवारों का अनुपात पहले चरण से ज्यादा हो। यह भी जरूरी है कि दूसरे चरण में ऐसे परिवारों को ज्यादा आसानी के साथ वित्तीय संस्थाओं से आवास ऋण मिले। औद्योगिक आवास के लिए आवंटन के तहत ऐसे मकान बनाने (उद्योगों के साथ मिलकर) के लिए सब्सिडी दी जाएगी, जो औद्योगिक कामगारों को किराये पर मिल सकें। इससे औद्योगिक वृद्धि तथा रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा और किराये के लिए अधिक मकान भी तैयार हो सकते हैं। इसी परियोजना में औद्योगिक कामगारों के साथ आम लोगों के लिए भी किराये के आवास बनाए जाएं तो उन लोगों को भी रिहायश मिल जाएगी, जो कारखानों के आसपास दूसरे काम-धंधे कर कामगारों को सेवा मुहैया कराते हैं।

आज का इतिहास

बढ़ता राजस्थान

6 मार्च की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- फर्डिनांड 1521 में मैगलन गाँव पहुँचा।
- रघुनाथ राव ने 1775 में पहले एंग्लो-मराठा युद्ध को समाप्त करने को लेकर अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किये।
- नर्सों की पहली पत्रिका नाइटिन्गेल 1886 में प्रकाशित हुई।
- मशहूर फुटबॉल क्लब स्पेन के 'मैड्रिड क्लब' की स्थापना 1902 में हुई थी।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर 1915 में पहली बार शांतिनिकेतन में मिले।
- इस्मेत इनोनू ने 1924 में तुर्की में एक नई सरकार बनायी।
- 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने मित्र देशों के साथ मिलकर बर्लिन पर भारी बमबारी की।
- भारत से ब्रिटिश सैनिकों को हटाये जाने का विरोध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1947 में की घोषणा की।
- बॉम्बे से इकोनोमिक टाइम्स का 1947 में सम्पादन शुरू हुआ था।
- भारत का पहला वित्तीय डेली समाचार पत्र 'द इकोनोमिक टाइम्स' टाइम्स आफ इंडिया समूह द्वारा 1961 में बॉम्बे में लॉन्च हुआ।
- जोसेफ़ स्तालिन की बेटी स्वेतलाना 1967 में भारत स्थित रूसी दूतावास से होते हुए अमेरिका पहुँची।
- यूनाइट स्टेट में 1983 में पहले फुटबॉल लीग की स्थापना हुई।
- भारत ने सन 1990 में इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता।
- महान पत्रकार अरुण तम्हांकार का 1995 में निधन हुआ।
- हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह ने 1998 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी।
- सन 2003 में अल्जीरिया का एक विमान तामारासेट में दुर्घटनाग्रस्त, 102 से भी अधिक यात्री मरे।
- दक्षिण चीन में एक कोयला खदान में 2007 में हुए विस्फोट में कम से कम 15 श्रमिकों की मौत हो गई।
- पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने 2008 में सरबजीत सिंह कि दया याचिका खारिज की।

06 मार्च को जन्मे व्यक्ति

- 1475 में इतालवी चित्रकार माइकल एंजेलो का जन्म।
- मुगल साम्राज्य का शासक बाबर के बेटे हुमायूँ का 1508 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जन्म हुआ।
- 1787 में जर्मन भौतिकशास्त्री जोसेफ़ फॉन फ्रॉन्होफ़र का जन्म।
- 1903 में जापान की महारानी कोजुन का जन्म।
- 1945 में भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक और कांग्रेस के सदस्य सैयद अहमद का जन्म।
- 1949 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शौकत अजीज का जन्म।

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उच्छृंखलता नामंजूर

ललित गर्ग

यह विडम्बनापूर्ण एवं हमारी न्याय प्रक्रिया की विसंगति ही है कि एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इस्तेमाल इन 'मियां-टियां' और 'पाकिस्तानी' जैसे शब्दों से जुड़े मुकदमे को निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक का सफर तय करने में लगभग चार साल लगे, मगर दोनों पक्षों ने किसी पड़ाव पर यह समझदारी दिखाने की कोशिश नहीं की कि यह सिर्फ अहं की लड़ाई है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक कविता पर गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने आभव्यक्ति का आजादी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई के दौरान जो कहा, वह जहां संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से खासा अहम है वहीं एक संतुलित एवं आदर्श समाज व्यवस्था का आधार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े इन मामलों में जो फैसले किए हैं और इस दौरान जो टिप्पणियां की हैं, उसके निहितार्थों को समझने की आवश्यकता है। मंगलवार को 'मियां-टियां' और 'पाकिस्तानी' शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मुकदमे के आरोपी को इस आधार पर आरोप-मुक्त कर दिया कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध के बराबर नहीं है। वैसे, अदालत ने इन शब्दों के प्रयोग को गैर-मुनासिब माना। एक प्रयोग रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले में अस्लीलता के आरोपों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद संतुलित लेकिन धारदार-सख्त टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि न तो अस्लीलता के लिए कोई गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिए और न ही इसे अभिव्यक्ति की आजादी की राह में आने देना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया को पॉडकास्ट जारी रखने की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह पैतिकता और अश्लीलता की सीमा को लांघने की गलती न करें। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी इन जटिल होती स्थितियों को गंभीरता से लिया और अनेक धुंधलकों को साफ किया है। सर्वोच्च न्यायालय के इन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जुड़े फैसलों रुपी उजालों का स्वागत होना ही चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस मामले में जांच की जरूरत बताते हुए पुलिस कार्रवाई की पुष्टि की थी। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी मायने रखती है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस को कविता पढ़नी चाहिए थी। कविता नफरत और हिंसा की नहीं, ईसफ और इश्क की बात करती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। कम से कम अब तो पुलिस को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मर्म समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बात का संदेश बिल्कुल स्पष्ट एवं न्यायसंगत है। हालांकि यह छिपी बात नहीं है कि पुलिस स्वायत्त तरीके से काम नहीं करती। अनेक कार्रवाइयां उसे सत्ता पक्ष के दबाव में करनी पड़ती हैं। इसलिए विपक्षी दलों एवं समुदाय विशेष के मामले में अगर अभिव्यक्ति की आजादी के कानून को हाशिये पर धकेल दिया या नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो हैरानी की बात नहीं। यह कम बड़ी विडंबना नहीं कि साहित्य और कलाओं में अभिव्यक्त विचारों की व्याख्या भी अदालतों को करनी पड़ रही है। सत्तारूढ़ सदा से अपनी आलोचना से तल्ख हो जाती रही है, ऐसी जटिल स्थितियों में आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई मौकों पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लम्बी बहसें हो चुकी हैं, आन्दोलन तक हुए, हिंसा एवं अराजकता का माहौल बना। हर बार अदालतें पुलिस को नसीहत देती हैं, अपने दखल से समझ एवं सीख भी देती है ताकि संतुलित वातावरण बना रहे। मगर शायद उस पर संजीदगी एवं संवेदनशीलता से अमल की जरूरत न तो पुलिस ने समझी और न उग्र एवं विध्वंसक शक्तियों ने। इसी का नतीजा है कि अब भी जब तब ऐसे मामले अदालतों में पहुंच जाते हैं, जिनसे किसी की भावना के आहत होने एवं विभिन्न समुदायों के आपसी सौहार्द-सद्भावना के खण्डित होने के आरोप लगते रहते हैं, जबकि वास्तव में उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। बेवजह नफरत, द्वेष एवं घृणा का माहौल बनता रहा है, चाहे वह फिल्मों के दृश्यों-संवादों, किसी राजनेता के बयानों, धर्मगुरुओं के बोलों या साहित्य के किसी अंश को लेकर भावनाएं आहत करने या भड़काने के आरोप किसी ऐतिहासिक-मिथकीय प्रसंग को लेकर की गई टिप्पणी पर लगते रहे हैं।

आज सोशल मीडिया जैसे मंचों के बेजा इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ रही है, फेसबुक, ट्विटर, यू-ट्यूब जैसे सोशल मंचों पर ऐसी सामग्री परोसी जा रही है, जो अशिष्ट, अभद्र, हिंसक, भ्रामक, राष्ट्र-विरोधी एवं समुदाय विशेष के लोगों को आहत करने वाली होती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को जोड़ना नहीं, तोड़ना है। इन सोशल मंचों पर ऐसे लोग सक्रिय हैं, जो तोड़-फोड़ की नीति में विश्वास करते हैं, वे चरित्र-हनन और गाली-गलौच जैसी ओछी हरकतें करने के लिये उद्यत रहते हैं तथा उच्छृंखल एवं विध्वंसात्मक नीति अपनाते हुए अराजक माहौल बनाते हैं। एक प्रगतिशील, सभ्य एवं शालीन समाज में इस तरह की हिंसा, अस्लीलता, नफरत और भ्रामक सूचनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडम्बना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के चलते सरकार इन अराजक स्थितियों पर काबू नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया से जुड़े मंचों के दुरुपयोग पर चिंता से सहमति जताते हुए भी सेंसरशिप और नॉर्म (मानदंड) के बीच के फर्क को रेखांकित किया। उसका कहना था कि सरकार को इस संबंध में गाइडलाईंस लानी चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी पर गैरजरूरी पाबंदियों का रूप न ले लें।

भारत : बदलते विश्व आर्थिक परिदृश्य का नया नायक

प्रो. आरके जैन

भारतीय कृषि क्षेत्र भी इस संकटमय वैश्विक परिदृश्य में एक सुनहरे अवसर की प्रतीक्षा में है। जब विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब भारत अपनी प्राचीन और समृद्ध कृषि परंपरा का उपयोग कर वैश्विक बाजार में एक नया मुकाम हासिल कर सकता है। मोटे अनाज, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'श्री अन्न' का सम्मानजनक नाम देकर पुनर्जीवन प्रदान किया, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुपरफूड के रूप में उभर रहे हैं।

भारत आज वैश्विक मंच पर एक नए, स्वर्णिम युग की ओर दृढ़ कदमों से अग्रसर हो रहा है। जब समूचा विश्व व्यापार युद्ध की उलझनों, आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चितता के भँवर में फँसा हुआ है, तब भारत अपनी अद्वितीय रणनीतिक दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता की अटूट शक्ति और प्रखर सूझ-बूझ के बल पर नवीन संभावनाओं का सृजन कर रहा है। वैश्विक पटल पर अमेरिका, चीन, कनाडा और मैक्सिको के बीच व्यापारिक तनाव अपने चरम पर पहुँच चुका है। अमेरिका द्वारा नए टैरिफ लागू करने के साहसिक निर्णय ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भूचाल ला दिया है, तो वहीं चीन और कनाडा ने भी जवाबी शुल्कों के साथ इस युद्ध को और प्रचंड बना दिया है। ऐसे में भारत के लिए यह एक दुर्लभ अवसर है कि वह स्वयं को एक अडिग, विश्वसनीय और प्रभावशाली व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित करे। टैरिफ की इस आँधी ने अनेक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को नए विनिर्माण ठिकानों की खोज के लिए विवश कर दिया है। यदि भारत अपने 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे दूरदर्शी अभियानों को और अधिक प्रबल गति प्रदान करे, तो वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अपरिहार्य अंग बनने की क्षमता रखता है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु व्यावसायिक सुगमता को सशक्त करने, नवाचार को प्रोत्साहन देने और अनुसंधान के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने से भारत इस व्यापार संग्राम से अभूतपूर्व लाभ अर्जित कर सकता है। यह समय भारत के लिए अपनी आर्थिक नींव को सुदृढ़ करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई पहचान गढ़ने का है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित करना भारत की कृषि शक्ति और दूरदर्शिता का ज्वलंत प्रमाण है। यह पहल न केवल भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, बल्कि भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक मंच पर एक सम्मानजनक स्थान भी दिला रही है। व्यापार और कृषि के साथ-साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था भी एक अभूतपूर्व उड़ान भर रही है। 'स्टार्टअप इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी अभियानों ने देश में तकनीकी क्रांति की नींव रखी है। जब वैश्विक कंपनियाँ नए तकनीकी केंद्रों की तलाश में हैं, तब भारत अपनी नवाचार क्षमता, कुशल मानव संसाधन और स्थिर नीतियों के दम पर एक डिजिटल महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर मिल रही मान्यता इस बात का साक्ष्य है कि भारत अब केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि नवाचार और उद्यमशीलता का एक सशक्त केंद्र बन चुका है। यह तकनीकी उछाल भारत को विश्व में एक नई पहचान देने का संकल्प रखती है। साथ ही, भारत की ऊर्जा नीति भी आत्मनिर्भरता और हरित भविष्य की ओर एक प्रेरक संकेत दे रही है। जब विश्व ऊर्जा संकट की चपेट में है और बड़े देश तेल व गैस की आपूर्ति को लेकर संशय में हैं, तब भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक अनुपम कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

दिनेश कुमार सैनी (राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक)

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बालगीत, मनोरंजन गतिविधि से शिक्षण कराने वाले, गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल-खेल में शिक्षा, कम लागत वाली शिक्षण अधिगम सामग्री बनाने वाले और शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार करने वाले शिक्षक दिनेश कुमार सैनी जी जो कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ला में कार्यरत हैं। इनका जन्म 11 जुलाई 1991 को राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के पुराना राजगढ़ गांव में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा पुराना राजगढ़, उच्च माध्यमिक शिक्षा श्री प्यारेलाल गुप्ता सीनियर सेकेंडरी विद्यालय राजगढ़ व उच्च अध्ययन राजगढ़ महाविद्यालय से किया। विद्यालय समय से ही एनएसएस और स्काउट में रहकर सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। 2012 में दिल्ली पुलिस में सरकारी सेवा में नियुक्त हुए। इन्होंने दिल्ली पुलिस में अपने कार्य के लिए अलग ही पहचान बनाई। 3 साल दिल्ली पुलिस में सेवा देने के बाद 1 अप्रैल 2015 को शिक्षा विभाग में अलवर जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आदिनाका,रामगढ़ में नियुक्त हुए और यहीं पर इनको इन्दौदा संस्था का सहयोग मिला और उससे प्रेरित होकर बच्चों के साथ लगातार गतिविधि आधारित शिक्षण और बालगीत से शिक्षण करवाते रहे। इसी दौरान विद्यालय में अनेक विकास कार्य करवाए जैसे- चार दीवारी निर्माण,विद्यालय रंगाई-पुताई और आरओ प्लांट पूरे गांव के लिए अमेरिका की संस्था से लगवाया। आदिनाका विद्यालय से ही यूट्यूब पर दिनेश हिंदी बालगीत नाम से यूट्यूब पैनल बनाया। इस पर लगातार अपने नवाचार से संबंधित वीडियो डालते रहे। 7 जून 2018 से ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ला में कार्यरत हैं। विद्यालय आने के पश्चात गांव के सरकारी कर्मचारियों का एक समूह बनाया जिसको विद्यालय विकास समिति बड़ला के नाम से जाना जाता है इस समूह के सहयोग से विद्यालय में अनेक विकास कार्य करवाए। अंत्योदय फाउंडेशन संस्था मुंबई और अनेक संस्थाओं का भी सहयोग लगातार मिलता रहा। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह इनको इनके नवाचार के लिए सम्मानित कर चुके हैं। इनके द्वारा विद्यालय समय के अलावा और छुट्टियों के दिनों में भी बच्चों को नवोदय विद्यालय और एनएमएमएस की तैयारी करवाई जाती है। अभी तक इनके द्वारा 17 बार रक्तदान करके जरूरतमंद लोगों की मदद की गई है लोगों को रक्त की जरूरत के लिए परेशान ना हो इसलिए ये और इनके बीस साथियों के साथ मिलकर नई सोच नई किरण रक्तदानी संगठन नाम से समूह बनाते हैं जिसमें 800 से ज्यादा सदस्य हैं जो आवश्यकता होने पर जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध करवाता है दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

राजकुमार गुप्ता, राजगढ़

2025_063

बढ़ता राजस्थान

Ans_2025_062

Suduko

		2		4	8			1
		3	9				8	
5		8		3			7	
9								
2	6		3			8		7
8	7	1	2		4	9		5
	2							4
1	5	6	4				9	8
4	8	7						3

8	1	3	9	5	4	6	7	2
7	6	9	3	2	1	4	8	5
5	2	4	6	7	8	3	9	1
1	8	2	7	3	9	5	4	6
4	3	6	1	8	5	7	2	9
9	5	7	2	4	6	1	3	8
3	9	5	4	1	2	8	6	7
6	7	8	5	9	3	2	1	4
2	4	1	8	6	7	9	5	3

कैसे खेलें

वर्ग को 1 से 9 तक अंकों से ऐसे भरें कि आड़ी व खड़ी पंक्ति के साथ ही 3 गुणा 3 के बॉक्स में 1 से 9 तक अंक आएं। कोई अंक दुबारा नहीं आए।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई दिनों तक्रों को पूरा करेंगे। काम आज एक समस्या रहने है कि आपके सीनियर के ऐसे चौंकने वेर है, जब आपके विचारे बुरार होंगे और दुसरी तरफ, आपकी मित्र बातें से लाभकर रहना रहेगा। रात में किसी करीबी दोस्त से और अधिक खुले को सुलझाने तथा स्वास्थ्यकारक उन्नति संबंधी समस्या रहेगी, वरिष्ठ एवंसदस्यित संबंधों में भी, जहां एक लाभकारक्षमता रहेगी संतान और कारोबार में लाभ प्राप्त होगा

मेष

आपका शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा। जरूरी कार्यों पर धन खर्च होगा। बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। दफ्तर में सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलेगा। मित्रों से मुलाकात होगी।

वृष

माता से लाभ होने के संकेत आपको मिल रहे हैं। मित्र और संबंधियों से घर का वातावरण अच्छा रहेगा। आज अचानक होने वाली घटनाओं से आप चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य खराब होने और आंखों में दर्द होने की आशंका बनी रहेगी।

मिथुन

पानी वाली जगहों से दूर रहें। आज धन का व्यय अधिक होगा। रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है और किसी खास व्यक्ति का साथ आपको आनंद देगा। महिलाओं के मायके से समाचार आने के योग हैं।

कर्क

हेल्थ का ध्यान रखने और खासकर बाहर के खाने-पीने से परहेज करने की सलाह आपको दी जाती है। आज आपमें क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए वाणी में गुस्सा ना रखें। परिजनों से उग्र चर्चा के कारण मनमुटाव न हो, इसका खास ध्यान रखें।

सिंह

आर्थिवाहितों को योग्य जीवनसाथी मिलने के योग हैं। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। मित्रों से अचानक हुई मुलाकात आनंददायी रहेगी। मित्रों से लाभ होगा। आज आपको अच्छा खाना नसीब होगा। मित्रों से लाभ होगा।

कन्या

आप तन-मन से स्वस्थ होकर कई तरह के काम आसानी से पूरे कर पाएंगे। सफलता मिलने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आज भाग्य आपका साथ देगा। इनकम बढ़ेगी। परिजनों के साथ आनंद एवं उल्लास से समय गुजरेगा।

तुला

हेल्थ का ध्यान रखने और खासकर बाहर के खाने-पीने से परहेज करने की सलाह आपको दी जाती है। आज आपमें क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए वाणी में गुस्सा ना रखें। परिजनों से उग्र चर्चा के कारण मनमुटाव न हो, इसका खास ध्यान रखें।

वृश्चिक

सरकार से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रतिकूल संयोग के बनने से आपके कार्य में विलंब होगा। शरीर में ताजगी और मन में उत्साह का अभाव रहेगा। पेट के रोग सताएंगे। नौकरी में अधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार से आपको दुख होगा।

धनु

मित्र एवं प्रियजन आपके प्रवास को आनंद से भर देंगे। नए वस्त्रों की खरीदी के योग हैं। तन-मन को तंदुरस्ती अच्छी रहेगी। अच्छे भोजन एवं वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज आप के घर में सुख शांति और आनंद का माहौल रहेगा।

मकर

आज आपके धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में व्यस्त रहने की संभावना ज्यादा रहेगी। आप में आज क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए आप सावधान ही रहें। संतान एवं व्यापार की परेशानियों के कारण आपका मन आशांत रहेगा।

कुंभ

नौकरी में आपके अधिकारी खुश रहेंगे। आपकी पदोन्नति के योग हैं। अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होगा। परिजनों के साथ खुले मन से बातचीत होगी। घर के डेकोरेशन पर कुछ खर्च हो सकता है।

मीन

संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों से आपको लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आप आज हर काम सरलता से पूरे कर पाएंगे। बाहर जाना हो सकता है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इंगोरपुरा रोड छावड़ा,जिला टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-नंदलाल पठान"। प्रधान संपादक-राम विलास विजयवर्गीय मो.नं. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक मो.नं.9414823448 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो.नं. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.नं.7023350734। ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com "पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार